R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 I अंक : 18
16 से 30 जून 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

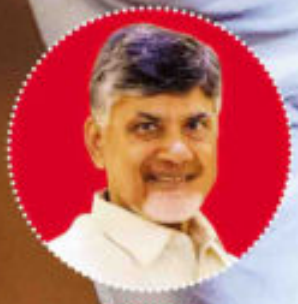

बहुमत के साथ विकास की बात

एक दशक के लंबे अंतराल के बाद गठबंधन युग की वापसी

मंत्रिमंडल और विभाग बंटवारे से समीकरण साधने की कोशिश!

उन्नति और खुशहाली की ओर
निरंतर बढ़ते कदम

मध्यप्रदेश सरकार के
180 दिन

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सुशासन से समृद्धि

समावेशी शिक्षा से संवरता कल

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

सशक्त बनती नारी शक्ति

युवा कल्याण के सतत् प्रयास

"हमारा उद्देश्य है कि सरकार उपलब्ध संसाधनों के साथ जनहितैषी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करे। प्रदेश को विकास के पथ पर निरंतर आगे ले जाना और सुशासन को सच्चे स्वरूप में धरातल पर उतारना ही हमारा लक्ष्य है"

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

इस अंक में

योजना

9 | अनुपयोगी संपत्तियों का बनेगा रिकार्ड

मप्र सहित देशभर में फैली हजारों करोड़ की मप्र की संपत्तियों पर सरकार की नजर है। दरअसल, प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में मप्र की हजारों करोड़ की संपत्तियां ऐसी हैं जो अनुपयोगी हैं। इनमें से कुछ संपत्तियों पर अवैध कब्जे भी...

डायरी

10-11 | सुशासन के लिए...

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 180 दिन के शासनकाल के दौरान एक्शन, रिएक्शन और क्रिएशन का अद्भुत तालमेल देखने को मिला है। लेकिन आने वाला समय उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

समस्या

14 | अमृत सरोवर बने खेल का मैदान

मप्र में इस बार रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण जल संकट भी बढ़ गया है। ऐसे में सभी को प्रदेशभर में बने अमृत सरोवरों की याद आ रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और पशुओं के लिए पानी मुहैया कराने के लिए लाखों...

पहल

18 | सीमाओं का होगा पुनर्निर्धारण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश में संभाग और जिलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए सरकार जिला पुनर्गठन आयोग बनाने जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 10 संभाग और 55 जिले हैं। अब सरकार की प्राथमिकता है कि इनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

2024 के लोकसभा चुनावों में एक दशक के लंबे अंतराल के बाद गठबंधन युग की वापसी हुई, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा अपने दम पर आधे से भी कम सीटें जीत सकी, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में वह बहुमत हासिल करने में सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बन गई है। अब यह सरकार 10 साल बाद बहुमत के साथ विकास की बात करेगी। यानी सरकार के सामने अगले 5 साल तक कई चुनौतियां आएंगी।

राजनीति

30-31 | अकेला चना भाड़ नहीं...

भारतीय संस्कृति में यह कहावत काफी प्रचलित है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। लेकिन कई बार लोग अकेले दम पर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर इंडी गठबंधन को धूल चटाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वे पूरी तरह...

महाराष्ट्र

35 | महाराष्ट्र में होगा खेला

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल होने वाला है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेज रहीं। नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए भाजपा ने अजित पवार गुट...

उप्र

37 | अयोध्या में हार हर कोई हैरान

लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट घोषित होने के बाद उप्र में सबसे ज्यादा चर्चा फैजाबाद (अयोध्या) सीट की हो रही है। यहां से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को 54 हजार वोटों से शिकस्त दी है।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

इच्छाएं बहुत...लेकिन कंट्रोल कैसे करेंगे...?

शा यर अमीर कजलबाश का एक शेर है...

मिरे जुनूं का नतीजा जरूर निकलेगा
इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा

कुछ इसी तरह का जुनून और जज्बात मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का है। अपने 6 माह के कार्यकाल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाने की कोशिश की है। अगर देशभर के मुख्यमंत्रियों से उनके अब तक के कार्यकाल का आंकलन करें तो वे सुपर स्ट्राइकर साबित हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन उनकी मंशा के अनुरूप कारगर साबित नहीं हुआ है। ऐसे में आगामी साढ़े चार साल सुशासन की राह पर कैसे कायम रह पाएंगे यह सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि अभी तक उन्होंने प्रशासन पर कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। मप्र में सुशासन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सख्त हैं। उन्होंने कानून-व्यवस्था के मामले में अफसरों को फ्री हैंड दे रखा है। लेकिन विड़बना यह है कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश के बावजूद भी अधिकारी अवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। दरअसल, जब मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं उसके दो-चार दिन तक अफसरों की सक्रियता देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश मिलते ही लाउडस्पीकर, नर्सिंग घोटाला, खुले में मांस-मछली विक्रेताओं और रेत माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। दिखावे के लिए दो-चार दिन कार्रवाई चली और फिर वही ढाक के तीन पात की स्थिति। बातें आई, गई हो गईं और मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। इससे अफसरशाही की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई। बड़ा सवाल यह है कि अधिकारियों को नियम विरूद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? क्या उन्हें नजर नहीं आता कि अवैध रेत खनन-परिवहन हो रहा है, नियम विरूद्ध लाउडस्पीकर बज रहे हैं, खुले में मांस-मछली का विक्रय हो रहा है। प्रदेश में 56 सरकारी विभाग हैं। यह संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को एक-एक विभाग में नियम विरूद्ध चल रही गतिविधियों को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर सकें। यह काम अफसरशाही का है। स्वतः संज्ञान लेना अफसरों का काम है। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए यह संभव नहीं है कि 50 से ज्यादा विभागों से जुड़े हजारों मामलों को लेकर वे अधिकारियों को कार्रवाई करने के संबंध में निर्देशित कर सकें। यदि मुख्यमंत्री यही सब काम करते रहे, तो वे विकास कार्यों पर फोकस कब करेंगे। प्रदेश में दवा माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया सक्रिय हैं। गांव-गांव में अवैध शराब, गांजा बिक रहा है। राजस्व अमले की कार्यप्रणाली से सीमांकन, बटान, नामांतरण के लिए किसान परेशान है। गांवों के सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है, गांव के स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुंचते। इन सारे कामों की निगरानी अफसरों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अफसर स्वतः किसी भी बात को संज्ञान में नहीं लेते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप मप्र में सुशासन का राज कैसे कायम होगा। अभी तो बस यही देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जितना करने को कहते हैं, अफसर उतना ही करते हैं। बाकी सब देखकर भी अनजान बने रहते हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 18, पृष्ठ-48, 16 से 30 जून, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

नायक बने सीएम

अपने अल्प समय के कार्यकाल में भूमिपुत्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासन-प्रशासन और जनता में मन में सुशासन का ऐसा भाव भर दिया है कि हर कोई उन्हें नायक की भूमिका में देखना चाहता है। आचार संहिता हटने के बाद अब मुख्यमंत्री का नया रूप देखने को मिल रहा है।

● **प्रवेश मीणा,** इंदौर (म.प्र.)

राह देख रहे अधिकारी

आईएएस अवॉर्ड देने का जो नियम है, उसके अनुसार प्रतिवर्ष भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगता है। मप्र में अभी कई राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस अवॉर्ड की राह देख रहे हैं।

● **गीतांजलि चौकसे,** सीहोर (म.प्र.)

हर घर नल कब तक?

केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से वर्ष 2026 तक प्रदेश के सभी 1.11 करोड़ से अधिक घरों में नल कनेक्शन से शुद्ध पानी देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक 69.55 लाख घरों में ही नल कनेक्शन हुए हैं। बुरहानपुर और निवाड़ी में ही हर घर नल कनेक्शन लगे हैं।

● **भगवान सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

भ्रष्टों पर कार्रवाई करे सरकार

प्रदेश में नर्सिंग घोटाला वर्ष 2021 में सामने आया। शिकायत के आधार पर इसकी जांच हुई। आरोप लगे कि नियमों को ताक में रखकर कॉलेजों को मान्यता दी गई। दो-तीन कमरों में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। न तो कॉलेज में लैब है और न ही 100 बिस्तर का अस्पताल है। कई कॉलेजों में तो फैकल्टी का ही पता नहीं है। सबकुछ कागजी है। सीबीआई जांच के आदेश होने के बाद लगा कि शायद बड़े खुलासे होंगे लेकिन जांच अफसर ही भ्रष्ट निकले, वे भी बिक गए। अब जनता भरोसा करे भी तो किस पर? सरकार को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई अन्य अफसर इस राह पर न जाए।

● **कपिल मिश्रा,** जबलपुर (म.प्र.)

अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई

राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनी बन चुकी है और नई कॉलोनी में प्लॉट काट रहे हैं। सीवेज से लेकर रोड पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। अब ऐसी नई अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले उन कॉलोनी पर कार्रवाई होगी, जहां अभी तक सिर्फ कॉलोनी के नाम पर रोड बनाकर प्लॉट काटे जा रहे हैं। प्रशासन का यह कदम शहर के मास्टर प्लान के अनुसार होगा, जो कि अच्छा कदम है।

● **मीनाक्षी पटेल,** भोपाल (म.प्र.)

साइबर क्राइम पर नकेल कसना जरूरी

डिजिटल जमाने में अपराध के नित नए रूप सामने आ रहे हैं। साइबर पुलिस के सामने ऐसे मामले आ रहे हैं कि अपराध के तरीके को जानकर पुलिसवाले भी हैरान हैं। मप्र में लगातार डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर साइबर ठग आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यही कारण है कि साइबर क्राइम पुलिस को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। साइबर क्राइम पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है कि यह साइबर अपराध का नया तरीका है। सरकार को इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

● **रितेश कोटवानी,** राजगढ़ (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

प्रदेश भाजपा नेताओं में खुलेआम झगड़ा

लोकसभा के चुनाव नतीजों से और कुछ बदला हो या नहीं बदला हो लेकिन एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि पार्टी का अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आने लगा है। नेता खुलेआम झगड़ने लगे हैं या अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे हैं। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से भाजपा की राजनीति पर सवाल उठाने और संघ के मुखपत्र में नतीजों को लेकर छपे विश्लेषण के बाद विवाद और तेज होने की संभावना है। सभवत: 10 साल के बाद पहली बार नतीजों को लेकर इस तरह के झगड़े देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर उप्र और बिहार से लेकर महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा तक, जहां भी भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है, वहां विवाद शुरू हो गया है। वैसे तो पूरे उप्र को लेकर पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं लेकिन पश्चिमी उप्र के दो बड़े नेताओं का झगड़ा चर्चा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने खुलकर आरोप लगाया है कि वे भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम की वजह से मुजफ्फरनगर सीट पर चुनाव हारे। दूसरी ओर संगीत सोम ने कहा है कि बालियान निराधार बात कर रहे हैं, वे अपने अहंकार की वजह से हारे। गौरतलब है कि पहले संगीत सोम ने आरोप लगाया था कि वे 2022 के विधानसभा चुनाव में सरधना सीट पर बालियान के कारण हारे हैं।

अब क्या करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा?

लोकसभा चुनाव जीतकर राहुल गांधी पहली बार अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ थीं। वहां राहुल ने कहा कि अगर उनकी बहन वाराणसी से चुनाव लड़तीं तो वे नरेंद्र मोदी को दो-तीन लाख वोट से हरा देतीं। तो सवाल है कि फिर लड़ीं क्यों नहीं? क्या सोचकर कांग्रेस ने उनको वाराणसी से क्या, कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ाया? कांग्रेस के छुटभैये नेताओं या सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स की ओर से दी जा रही इस दलील का कोई मतलब नहीं है कि प्रियंका पूरे देश में प्रचार कर रही थीं। पूरे देश में तो राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे थे फिर भी दो सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़े। गौरतलब है कि इस साल मार्च, अप्रैल में हुए राज्यसभा के दोवार्षिक चुनावों में प्रियंका गांधी वाड्रा के राज्यसभा में जाने की बड़ी चर्चा थी। कहा जा रहा था कि वे तेलंगाना या हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जाएंगी। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। फिर कहा गया कि अपनी मां सोनिया गांधी की खाली की हुई रायबरेली सीट से वे चुनाव लड़ेंगी लेकिन वह भी नहीं हुआ। उसके बाद कहा गया कि राहुल गांधी दो सीटों से जीतने के बाद रायबरेली सीट खाली कर देंगे और वहां से प्रियंका लड़ेंगी लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल रायबरेली सीट रखने के लिए तैयार हो गए हैं और वे केरल की वायनाड सीट खाली करेंगे।

मायावती की मजबूरी है आकाश को लाना

उप्र की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। भाजपा ने 2014 की चुनावी जीत के बाद राज्य की राजनीति पर जो एकाधिकार बनाया था वह 10 साल के बाद खत्म होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीटें जीतकर राज्य की राजनीति को नई दिशा दी है। अब बहुजन समाज पार्टी को भी लग रहा है कि राज्य में त्रिकोणात्मक राजनीति की स्थिति फिर से बन रही है और ऐसे में बसपा पहले की तरह फिर मजबूत हो सकती है। हालांकि अभी तुरंत बसपा ने कोई राजनीतिक गतिविधि शुरू नहीं की है लेकिन जल्दी ही पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम शुरू होंगे। बसपा के जानकार नेताओं का कहना है कि अब मायावती ब्रांड की राजनीति नहीं चलने वाली हैं। बहुजन समाज पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि पार्टी को अगर अपना खोया हुआ जनाधार वापस हासिल करना है तो बहनजी को अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे करना होगा। गौरतलब है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था लेकिन जैसे ही वे चुनाव प्रचार में भाजपा के खिलाफ आक्रामक हुए मायावती ने उनको अपरिपक्व बताते हुए उत्तराधिकारी के साथ साथ पार्टी पद से भी हटा दिया।

उपचुनाव की हड़बड़ी

लोकसभा चुनाव और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के एक हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग ने सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। सात राज्यों में 10 जुलाई को उपचुनाव होंगे, जिनके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जून है। सवाल है कि चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि लोकसभा के नतीजे आते ही उसने उपचुनाव की घोषणा कर दी? आयोग को पता है कि देश के अनेक राज्यों में विधानसभा के सदस्यों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं, जो सांसद बन गए हैं। वे अपनी एक सीट से इस्तीफा देंगे और वहां भी उपचुनाव कराना होगा। यह भी तय है कि अगर कोई विधायक लोकसभा का चुनाव जीत जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर किसी एक सीट से इस्तीफा देना होगा। सो, चुनाव आयोग को ज्यादा नहीं सिर्फ 14 दिन इंतजार करना था। उसके बाद वह एक साथ सारी सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता था। लेकिन आयोग ने दो हफ्ते इंतजार नहीं किया।

संदीप सहारे आप

आम चुनाव 2024 के नतीजे जारी होने से कथित शराब घोटाले में जेल गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर जेल चले गए हैं। इस बार जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ एक बैठक की। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। फिर उन्होंने विधायकों के साथ भी बैठक की। बताया जा रहा है कि दोनों बैठकों में पार्टी के संचालन और अगले साल जनवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल के जेल में रहने पर पार्टी के कामकाज कौन संभालेगा। क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी का कामकाज देखेंगी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि केजरीवाल ने अपनी गैरमौजूदगी में पार्टी का कामकाज देखने के लिए पार्टी के चुनावी रणनीतिकार संदीप पाठक को अधिकृत किया है। पार्टी में इससे कई लोग नाराज बताए जा रहे हैं।

शिक्षाविद् की दलाली

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक शिक्षाविद् जो निजी संस्थान से जुड़े हुए हैं, काफी चर्चा में हैं। वैसे तो साहब हमेशा ही किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार अपनी दलाली के कारण चर्चा में हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब की इन दिनों एक महिला मंत्री से खूब पट रही है। इसलिए वे महिला मंत्री के लिए बाहरी कामकाज भी देख रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक शासकीय कॉलेज में कार्यरत शिक्षाविद् को जीएम बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि इन्होंने शासकीय कॉलेज में कार्यरत शिक्षाविद् को जल निगम में जीएम बनवाने के लिए मंत्री से नोटशीट पर साइन भी करा लिया है। साहब की इस जुगाड़ से हर कोई प्रभावित है। सूत्रों का कहना है कि जबसे यह बात सामने आई है कि उन्होंने एक अन्य शिक्षाविद् के लिए दलाली की है, उनके पास अपना काम कराने वालों की भीड़ लगने लगी है। यहां हम बता दें कि जिस शिक्षाविद् की दलाली की यहां चर्चा हो रही है, वे अभी तक अपना काम-धंधा बढ़ाने के लिए जातिगत लाभ लेते रहे हैं। जाति-जाति का खेल खेलते हुए वे खेला खेलने में इस कदर माहिर हो गए हैं कि अब उन्होंने सरकार में भी अपनी अच्छी पैठ बना ली है। शायद यही वजह है कि मंत्री ने उनके माध्यम से अपने चहेते को जल निगम का जीएम बनाने के की नोटशीट पर साइन किया है और धीरे से उन्हें अपना ओएसडी बना लेंगी।

जुगाड़ की गाड़ी

ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक ख्यात है कि वे किसी पर एहसान नहीं करते। यानी वे अगर किसी के लिए अगर कुछ करते हैं तो उसके बदले में उनसे कुछ न कुछ ले लेते हैं ताकि उस व्यक्ति के मन में ग्लानि न रहे। ऐसा ही कुछ किया है एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने। साहब ईमानदार अफसरों की श्रेणी में गिने जाते हैं। संस्कृति से इनका बड़ा लगाव है। इसलिए साहब जो कुछ भी करते हैं, वह तहजीब में रहकर ही करते हैं। सूत्रों का कहना है कि तहजीब के दायरे में रहकर साहब ने अपने पुत्र के लिए एक गाड़ी की जुगाड़ की है। सूत्रों का कहना है कि साहब ने एक ट्रैवल एजेंसी से कहा कि एक नए मॉडल की स्कॉर्पियो खरीदो और विभाग के माध्यम से मेरे घर पर अटैच कर दो। बताया जाता है कि अब साहब के साहबजादे हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा होए, की तर्ज पर स्कॉर्पियो की सवारी कर रहे हैं। वैसे यहां बता दें कि साहब को जानने वालों का कहना है कि साहब ने आज तक किसी पर दबाव डालकर कोई चीज नहीं ली है। बस साहब लोगों से निवेदन करते हैं। वे भी ऐसे-वैसे लोगों से नहीं बल्कि जो लोग साहब के विभागीय कार्य से जुड़े होते हैं, साहब बस उन्हीं लोगों से निवेदन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

राख को सोना बनाने का गुण

राख को सोना कैसे बनाया जाता है, यह अभी तक हम लोगों ने किस्से-कहानियों में ही सुना है। लेकिन इन दिनों विंध्य क्षेत्र के एक जिले में एक आईपीएस अधिकारी यह कारनामा करके चर्चा में हैं। इस आईपीएस अधिकारी की धाक के आगे जिले के बड़े अफसर भी पस्त हैं। कोयले और बिजली उत्पादन के लिए देशभर में ख्यात इस जिले में पुलिस की कप्तानी कर रहे आईपीएस अधिकारी ने यहां के रेलवे के माध्यम से राख को सोना बनाने का खेला शुरू किया है। सूत्रों का कहना है कि उक्त आईपीएस ने इस एक थानेदार की ड्यूटी लगा दी है। ये साहब ही यहां से होने वाले खेल के सूत्रधार हैं। दरअसल, जब खदान से कोयला निकलता है तो वह अच्छी किस्म का होता है, लेकिन जब उसे मालगाड़ी के डिब्बों में भरा जाता है तो अच्छी किस्म की कोयला की जगह राख भरवा दी जाती है। उसके बाद वह मालगाड़ी वहां से रवाना होती है। आईपीएस अधिकारी के संरक्षण में कोयले की राख को भरकर उच्च क्वालिटी के कोयले को उतरवाकर स्थानीय बाजार में बेचा जा रहा है। स्थानीय बाजार से कम कीमत में बेचे जाने के कारण ये कोयला हाथोंहाथ बिक रहा है और कप्तान के साथ ही उनके सहयोगी जमकर कमाई कर रहे हैं। कमाई के इस खेल की पोल खुल गई है और इसकी भनक राजधानी तक पहुंच गई है। अब देखना यह है कि राख को सोना बनाने का यह खेल कब तक चलता है।

जोर का झटका धीरे से

राजनीति में शह-मात का खेल कभी रुकता नहीं है। साथ-साथ दिखने वाले नेता एक लगते हैं, लेकिन उनके बीच शह-मात का खेल उस समय भी चलता रहता है। प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक ऐसे ही खेल की चर्चा है। दरअसल, प्रदेश के एक विभाग में एक आईएएस अधिकारी को चेयरमैन बना दिया गया है। जबकि अभी तक यह होता आया है कि विभागीय मंत्री ही चेयरमैन होता है। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि राजनीति में शह-मात के खेल में यह खेला सरकार के मुखिया द्वारा खेला गया है। दरअसल, जिस विभाग की बात हो रही है, उस विभाग के मंत्री का राजनीतिक कद काफी बड़ा है। उनके आगे बड़े-बड़े नेताओं का कद छोटा हो जाता है। मंत्री बनने के बाद माननीय ने कई बार इसका अहसास भी करा दिया है कि वे जो चाहेंगे, शासन-प्रशासन में वही होगा। लेकिन शह-मात के इस खेल में फिलहाल सरकार के मुखिया ने बाजी मारी है और मंत्रीजी की जगह उनके विभाग के प्रमुख सचिव को चेयरमैन बनाकर मंत्रीजी को जोर का झटका धीरे से दिया है।

जांच के नाम पर उगाही

कोयले का धंधा ऐसा होता है जिसमें कितना भी सफेदपोश आदमी हो, अगर वह उसकी दलाली करता है तो उसके दामन पर कालिख पुत ही जाती है। ऐसे ही कालिख पुते लोगों को जांच का डर दिखाकर एक पुलिस अधिकारी जमकर कमाई कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब वर्तमान में प्रदेश की ऊर्जाधानी में एक जांच एजेंसी में पदस्थ हैं। यहीं पर राज्य पुलिस सेवा के उक्त अधिकारी के एक तथाकथित रिश्तेदार भी हैं, जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। साहब के तथाकथित रिश्तेदार ताल ठोककर कारोबार कर रहे हैं और अगर कोई उनकी राह में बाधा बनता है तो उसे साहब का नाम लेकर डराते हैं। यही नहीं वे हमेशा उन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाकर जांच का भय दिखाते हैं। उसके बाद शुरू होता है लेनदेन कर मामले को निपटाने का खेल। सूत्रों का कहना है कि तथाकथित रिश्तेदार के माध्यम से साहब ने इस खेल में अब तक मोटी कमाई कर ली है। आलम यह है कि जिले के सारे अधिकारी-कर्मचारी साहब के नाम से भय खाने लगे हैं और कई तो ऐसे हैं जो साहब के पास हिसाब-किताब करके बिना कहे ही राशि पहुंचाने लगे हैं।

आरोपी नामजद... वसूली नहीं

मप्र में सहकारी बैंकों में हो रहे घोटालों से उनकी वित्तीय स्थिति इस कदर खराब हो गई है कि बैंकों में पैसा जमा करने वाले जमाकर्ता परेशान हैं। बैंक में पैसा जमा करने वाले लोगों को उनका जमा पैसा नहीं मिल रहा है। जमाकर्ता आए दिन कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से पैसा निकलवाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उधर, घोटाला करने वाले आरोपी नामजद हैं, लेकिन न तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है और न ही उनसे राशि की वसूली हो पा रही है।

गौरतलब है कि शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में हुए 100 करोड़ रुपए के घोटाले में 3 साल बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। इनमें 13 आरोपित नामजद हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। घोटाले में वित्तीय संकट में डूबे सहकारी बैंक की राशि डकार ली गई। अब स्थिति यह है कि बैंक के पास उसके उपभोक्ताओं को लौटाने के लिए रुपए नहीं हैं। जिले की दर्जनों समितियों ने खाद आदि की राशि ही बैंक में जमा नहीं की है। सहकारिता विभाग के बड़े अधिकारी सहकारी बैंक घोटाले के आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रदेश में शिवपुरी जिले के अलावा सतना, दतिया, झाबुआ सहित सीधी में ट्रैक्टर घोटाला एवं होशंगाबाद में ऋण वितरण में गड़बड़ी के कई मामले उजागर हो चुके हैं। इससे अब सहकारी संस्थाएं कंगाल होने लगी हैं और उनकी निर्भरता सरकार के ऊपर बढ़ गई है। दतिया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं में भी करोड़ों रुपए की गड़बड़ी सामने आ चुकी है। शिवपुरी में डीएमओ से खाद लेकर किसानों को बेच दी गई, लेकिन इसका पैसा डीएमओ के खाते में जमा नहीं करवाया। भुगतान के संबंध में जिला सहकारी बैंक की ओर से समिति प्रबंधकों को कई नोटिस जारी किए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। जिलेभर में ऐसी दर्जनों समितियां हैं जिन पर करोड़ों रुपए बकाया हैं। सतना केंद्रीय सहकारी बैंक में किसानों के नाम पर 6 करोड़ के फर्जी लोन घोटाले की जांच भी लंबित है। सहकारी समिति देवरी चुरहटा में वर्ष 2015 में समिति प्रबंधक, समिति अध्यक्ष, केंद्रीय बैंक के प्रबंधक और पर्यवेक्षक ने मिलीभगत करके 603 किसानों के नाम से फर्जी कर्ज स्वीकृत किया और फिर यह राशि निकाल ली।

समिति ने छह करोड़ का बंदरबांट किया और कर्ज की राशि 2016 में जमा नहीं होने के कारण बैंक ने किसानों के नाम ऋण वसूली के नोटिस जारी किए थे। किसानों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऋण माफी योजना के नाम पर झाबुआ जिले की थांदला आदिम जाति सोसाइटी में डेढ़ करोड़ का घोटाला उजागर हुआ। तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया। जांच में पाया गया कि किसानों के फर्जी नाम से दो करोड़ 40 लाख रुपए की ऋण माफी बताते हुए शासन से अधिक पैसे मांगे गए हैं। इस मांग के विरूद्ध 1 करोड़ 47 लाख रुपए मिल गए। सीधी जिला सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक ने 1100 ट्रैक्टर फाइनेंस किए। सामान्यत: प्रदेश में इतने ट्रैक्टर फाइनेंस नहीं होते हैं। घपले का अंदेशा लगने पर पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। यहां फाइनेंस किए गए करीब 114 ट्रैक्टर किसी और के नाम पर पंजीकृत निकले। मोपेड सहित अन्य वाहनों के नंबर भी पाए गए। 167 कर्मचारियों की भर्ती में भी फर्जीवाड़ा हुआ।

● **अरविंद नारद**

खातों में राशि की बंदरबांट

रीवा जिला सहकारी बैंक की डाभौरा शाखा में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ। प्रबंधक रामकृष्ण मिश्रा ने कई खातों में राशि की बंदरबांट करते हुए अपनों के खातों में ट्रांसफर कर दी। इसके साथ ही आंतरिक अंकेक्षण में साढ़े छह करोड़ रुपए की गड़बड़ी और पकड़ाई। मामले में एफआईआर दर्ज कर सीआईडी से जांच करानी पड़ी। होशंगाबाद जिला सहकारी बैंक की हरदा शाखा में 2 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ था। यह नकदी बैंक की जांच में कम पाई गई। जब पड़ताल हुई तो पता लगा कि शाखा को इतनी नकदी रखने का अधिकार ही नहीं था। इस राशि को ब्याज पर चलाए जाने की बात भी सामने आई। बैंक कर्जमाफी योजना के दौरान भी गड़बड़ियों को लेकर चर्चित रहा है। छतरपुर जिला सहकारी बैंक की राजनगर शाखा में 3 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। यहां शाखा प्रबंधक लक्ष्मी पटेल ने 183 किसानों को क्रेडिट कार्ड पर कर्ज देकर 3 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया। कर्ज समिति के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन बिना किसी से अनुमति लिए शाखा से ही कर्ज दे दिया गया। कर्ज ऐसे किसानों को मछली पालन के नाम पर दिया गया, जिन गांव में तालाब ही नहीं है। मामला सब्सिडी हड़पने का निकला। मंदसौर जिला सहकारी बैंक में लगभग 12 करोड़ रुपए का फर्जी ऋण बांटने का मामला आया। इसमें पात्रता नहीं होने पर भी बैंक अध्यक्ष ने परिजन के नाम पर ऋण ले लिया। नीमच, जीरन व सावन के वेयरहाउस की फर्जी पर्चियों पर यह कर्ज दिया गया। जबकि वेयर हाउस में अनाज रखा ही नहीं गया था। जिन शाखाओं से यह कर्ज दिया गया, उन्हें इसकी पात्रता ही नहीं थी। हालांकि जब बवाल मचा तो बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष ने राशि ब्याज सहित जमा कर दी। ग्वालियर जिला सहकारी बैंक के क्षेत्राधिकार में आने वाली समितियों ने करोड़ों रुपए के फर्जी ऋण बांट दिए। करीब 30 करोड़ रुपए की आर्थिक अनियमितता की जांच ईओडब्ल्यू कर रहा है, लेकिन इसका मूल रिकार्ड ही नहीं मिल रहा है। घोटाले का दायरा बढ़ता जा रहा है। शहडोल जिला सहकारी बैंक की अनूपपुर और कोतमा शाखा में करोड़ों रुपए का खेल हुआ। यहां बैंक के तत्कालीन मैनेजर राजेंद्र तिवारी ने 32 लाख रुपए अपने बेटे अनिल तिवारी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। बेटा बैंक में ही कम्प्यूटर ऑपरेटर था। दामाद सुबोध तिवारी के खाते में 87 हजार रुपये डाले और एक ट्रैक्टर सुनील तिवारी के नाम से खरीदा लिया।

अनुपयोगी संपत्तियों का बनेगा रिकार्ड

मप्र सहित देशभर में फैली हजारों करोड़ की मप्र की संपत्तियों पर सरकार की नजर है। दरअसल, प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में मप्र की हजारों करोड़ की संपत्तियां ऐसी हैं जो अनुपयोगी हैं। इनमें से कुछ संपत्तियों पर अवैध कब्जे भी हुए हैं। अब प्रदेश सरकार इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी। जो संपत्तियां काम लायक होंगी उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, जो अनुपयोगी होंगी उनकी बिक्री होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके विभागों से संबंधित अन्य राज्यों में स्थित संपत्तियों की सूची मंगाई है। पत्र में विभागों से कहा गया है कि वे बताएं, किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है, उसका मूल्य क्या है?

वित्त विभाग द्वारा दूसरे विभागों से संपत्तियों की जानकारी मांगने का मुद्दा गर्मा गया है। गौरतलब है कि सरकार दूसरे राज्यों में स्थित शासकीय संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके विभागों से संबंधित अन्य राज्यों में स्थित संपत्तियों की सूची मंगाई है। पत्र में विभागों से कहा गया है कि वे बताएं, किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है, उसका मूल्य क्या है? अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी तरह का विवाद है, तो इसकी भी जानकारी दी जाए। सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इन संपत्तियों की बिक्री कर अपने लिए राजस्व जुटाएगी? मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर तत्काल श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सूत्रों का कहना है कि सरकार पिछले तीन वर्षों में मप्र में स्थित करीब 553.59 करोड़ रुपए की संपत्तियों की बिक्री कर चुकी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 26.96 करोड़ रुपए और 2021-22 में 282.97 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची थी। ऐसे ही वर्ष 2022-23 में 256.71 करोड़ रुपए की संपत्ति का विक्रय किया गया था। बेची गई संपत्तियों में अधिकतर संपत्तियां मप्र सड़क परिवहन निगम की हैं। दरअसल, मप्र सरकार 3 लाख 50 हजार से ज्यादा के कर्ज तले दबी है। सरकार विकास कार्यों और योजनाओं के लिए समय-समय पर कर्ज लेती रही है। बजट के लिए भी बड़ी राशि की जरूरत है। इस कारण सरकार आय के अतिरिक्त रास्ते ढूंढ रही है। सरकार ने उपयोग में नहीं आ रही अपनी संपत्तियों की बिक्री-नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित की है। राज्य शासन की संबंधित जिले में स्थित अनुपयोगी परिसंपत्तियों की नीलामी-विक्रय जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त एवं कार्यपालिका समिति द्वारा निर्णय के आधार पर किया जाता है। जिले में शासन की अनपुयोगी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होता है। वहीं दूसरे राज्यों में मप्र सरकार की हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं। मुंबई में मप्र सरकार की बड़ी संख्या में परिसंपत्तियां हैं। इनमें एडवर्ड विला, टैंक बंदर ठाणे, प्रिंसेस बिल्डिंग, कोलाबा, मांगलिक रोड आदि है। मुंबई की ज्यादातर संपत्तियां कानूनी विवाद वाली रही हैं। इनका रखरखाव पब्लिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड करती रही है। केरल के वायनाड में मप्र की 550 एकड़ जमीन है। यह जमीन भी केरल से विवादो में थी, जिसे अब सुलझा लिया गया है। झांसी और नागपुर में मप्र परिवहन निगम के बस डिपो हैं।

प्रदेश सरकार अब तक लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के माध्यम से तीन वर्षों में मप्र में स्थित करीब 553.59 करोड़ रुपए की संपत्तियों की बिक्री कर चुकी है। लेकिन जैसे ही वित्त विभाग ने विभागों से संपत्तियों की जानकारी मांगी है उस पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। 3 लाख 73 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी मप्र सरकार देश के दूसरे राज्यों में मौजूद मप्र के अलग-अलग विभागों की संपत्ति बेचने और उसे किराए पर देने की तैयारी कर रही है। इस कवायद का मकसद प्रदेश के बाहर मौजूद विभिन्न विभागों की संपत्ति का डेटा जुटाना है, ताकि उसे बेचकर या किराए पर देकर राशि जुटाई जा सके।

● **विकास दुबे**

10 हजार करोड़ का सरकारी राजस्व सालों से फंसा

नगरीय प्रशासन संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की बिना बिकी संपत्ति अन्य निर्माण एजेंसियों की अपेक्षा सर्वाधिक है। हाउसिंग बोर्ड की करीब साढ़े छह हजार करोड़ रुपए की संपत्ति बिना बिकी है। विकास प्राधिकरण का यह आंकड़ा तीन हजार से अधिक है। करीब 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का सरकारी राजस्व सालों से फंसा हुआ है। इसके अलावा इनके संधारण में खर्च का भार भी संबंधित निर्माण एजेंसी को झेलना पड़ता है। सालों से पड़ी संपत्ति भी जर्जर स्थिति में तब्दील होती जा रही है। लिहाजा आधे दाम में पुरानी संपत्ति का विक्रय सरकार की मजबूरी भी है। दरअसल, हर साल राज्य सरकार के बजट से पहले हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण समेत अन्य निर्माण एजेंसियां रिपोर्ट तैयार करती हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि साल दर साल उन प्रॉपर्टी की संख्या में इजाफा हुआ, जो बिक नहीं सकी हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इन संपत्तियों को बेचने के लिए कई स्तर पर पहल भी की गई। प्रॉपर्टी मेला के साथ विज्ञापन भी जारी किए गए। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 12 साल पुरानी संपत्तियों के विक्रय के लिए दाम तय करने एक कैल्कुलेशन तैयार किया गया है। इसका फार्मूला कलेक्टर गाइडलाइन, जारी टेंडर और एसओआर आधार पर होगा।

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 180 दिन के शासनकाल के दौरान एक्शन, रिएक्शन और क्रिएशन का अद्भुत तालमेल देखने को मिला है। लेकिन आने वाला समय उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस चुनौती से निकलने के लिए उन्हें शासन, प्रशासन, पार्टी संगठन, वरिष्ठ नेताओं, मीडिया, कार्यकर्ताओं के साथ ही विपक्ष को भी साधने की जरूरत पड़ेगी। यानी आने वाले समय में सुशासन के लिए उन्हें समुचित अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। ये कोई आसान काम नहीं होगा।

सुशासन के लिए समुचित अनुशासन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने अब तक के कार्यकाल में न सिर्फ राजनीति की दृष्टि से बल्कि प्रदेश में सुशासन और विकास के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं। इस कारण मुख्यमंत्री एक्शन, रिएक्शन और क्रिएशन के मामले में चर्चा में बने हुए हैं। 6 महीने के कम समय में ही उन्होंने न सिर्फ प्रशासन को अलर्ट किया है बल्कि कई बड़े एक्शन भी लिए हैं। कई मोर्चे पर तत्काल निर्णय लेकर भी उन्होंने सभी को चौंकाया हैं। यानी 180 दिन के शासनकाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुपरस्ट्राइकर की तरह परिणामदायक काम किया है। लेकिन उन्होंने सुशासन की जो राह पकड़ी है, उसमें कई बाधाएं हैं। इन बाधाओं को समुचित अनुशासन और कठोर निर्णयों से ही पार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के अभी तक के कार्यकाल को देखें तो वे रह-रहकर उज्जैन का जिक्र करते हैं। सबसे पहले उन्हें इस बात को भुलाना होगा, क्योंकि वे केवल उज्जैन के विधायक नहीं बल्कि पूरे मप्र के मुख्यमंत्री हैं।

मुख्यमंत्री को अच्छा शासक और प्रशासक बनने के लिए 2003 से लेकर अभी तक पदस्थ सारे मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना चाहिए। अभी तक प्रदेश में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों की कई जोड़ियां काम कर चुकी हैं, लेकिन इनमें सबसे अच्छा समन्वय शिवराज सिंह चौहान और इकबाल सिंह बैंस के बीच देखने को मिला। हालांकि अपनी सुशासन की पॉलिसी को दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करने के लिए उन्होंने पीएमओ की तर्ज पर पावरफुल सीएमओ बनाने की कवायद की है। मुख्यमंत्री सचिवालय में डॉक्टर, इंजीनियर के साथ ही प्रबंधक, अर्थशास्त्र, राजनीति और साहित्य विधा के हुनरमंद अफसरों को तरजीह दी गई है।

पुरानी सरकार में एसके मिश्रा जैसे चेहरे थे, जो सभी को साधते थे। डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री सचिवालय में 1990 बैच आईएएस अधिकारी एसीएस डॉ. राजेश राजौरा को पदस्थ किया है। राजेश राजौरा यह रोल अदा कर सकते हैं। डॉ. राजेश राजौरा मेहनती, तेजतर्रार और अनुभवी अफसर हैं। अनेक बड़े विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनके कृषि पीएस रहते 6 कृषि कर्मण मिले। अभी जल संसाधन, एनवीडीए भी संभाल रहे हैं। गृह, उद्योग, उद्यानिकी, परिवहन में रह चुके हैं।

डॉ. राजेश राजौरा ही संजय शुक्ल को सीएमओ लेकर गए हैं। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी प्रमुख्य सचिव संजय शुक्ल बीई (मैकेनिकल) हैं। उनकी तेज गति से काम करने वाले अफसर की छवि है। वे महिला बाल विकास की जिम्मेदारी भी संभाल रहे। इसके अलावा वे उद्योग, बिजली, पीएचई, नगरीय प्रशासन सहित अनेक विभागों में रह चुके हैं। वे भोपाल के कलेक्टर के अलावा आदिवासी जिलों के भी कलेक्टर रहे हैं। बीते ढाई साल में कई तबादले हुए, लेकिन उन्होंने मेहनत लगन और परफॉर्मेंस में कमी नहीं आने दी। दोनों ताल में ताल मिलाकर काम करने में माहिर हैं और प्रशासनिक और राजनीतिक कठिनाईयों में मुख्यमंत्री के साथ समन्वय बनाकर कुशल प्रशासन देने में सफल होंगे या असफल यह तो आगे पता चलेगा। इन दोनों अफसरों के अलावा 1997 बैच के राघवेंद्र सिंह, 2008 बैच के भरत यादव, 2009 बैच के अविनाश लवानिया, 2010 बैच के चंद्रशेखर वालिम्बे, 2015 बैच की अदिति गर्ग, 2016 बैच के अंशुल गुप्ता पदस्थ हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजौरा सक्षम अधिकारी हैं। क्योंकि वे गृह विभाग में 3 साल, कृषि में 5 साल, स्वास्थ्य में 2 साल, इसी तरह वाणिज्यिक, उद्योग, श्रम और जनसंपर्क सहित कई विभागों में काम कर चुके हैं। यानी उनका लंबा

सुशासन और जनता के सम्मान से समझौता नहीं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 6 महीने के कार्यकाल में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें अधिकारी आम जनता की तकलीफें सुनने के बदले उनकी उपेक्षा करते दिखे, ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री ने तत्काल इन अधिकारियों पर कार्रवाई की। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए मोहन यादव मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों और मंत्रियों को संकल्प पत्र-2023 की घोषणाओं और वचनों को पूरा करने और उसे जमीन पर उतारने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंची है और करीब 50 लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं का फायदा पहुंचाया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही मुख्यमंत्री ने अफसरों को टारगेट पूरा करने पर लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह योजनाबद्ध तरीके से सभी को जिम्मेदारी दी है, उससे उनकी प्रशासनिक क्षमता साफ दिखती है।

डॉ. राजेश राजौरा

संजय शुक्ल

अनुभव है। प्रदेश में सरकार के सामने तबादलों की भी बड़ी चुनौती है। प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उनकी जगह नए अफसरों की पदस्थापना करनी है। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के डीजी और एडीजी बदले जाने हैं। राजेश राजौरा समन्वयकारी अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में यह बात तो तय है कि वे राजनीतिक, प्रशासनिक और मीडिया से समन्वय बैठा लेंगे। यानी वे संकटमोचक की भूमिका में खरे उतर रहे हैं। हालांकि ब्यूरोक्रेसी को साधना उनके लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि कई अधिकारी हमाम में सभी नंगे वाली स्थिति में हैं।

इनसे कैसे पाएंगे पार

मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे अपनी ही सरकार के कद्दावर नेताओं से कैसे समन्वय बनाकर काम करेंगे। क्योंकि उनकी सरकार में कई कद्दावर नेता ऐसे हैं, जो इनसे राजनीतिक रूप से माहिर खिलाड़ी हैं। कैलाश विजयवर्गीय मालवा क्षेत्र के धुरंधर नेता हैं, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह महाकौशल क्षेत्र के धुरंधर नेता हैं, वहीं उदय प्रताप सिंह मध्य क्षेत्र के बड़े नेता हैं, जो मोहन सरकार में मंत्री हैं। मुख्यमंत्री इन सभी को किस तरह साधकर रखेंगे, यह उनके लिए बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री अवैध कामों पर नकेल कसने के लिए

पुरानी घटनाओं से सबक

मुख्यमंत्री को राजनीतिक और प्रशासनिक बाधाओं से पार पाने के लिए पुरानी घटनाओं से सबक लेना होगा। उन्हें याद करना होगा कि जो उमा भारती बड़े बहुमत के साथ प्रदेश में भाजपा को सत्ता में वापस लाई थी, उन्हें एक झटके में उड़ा दिया गया। बाबूलाल गौर को उनकी जगह लाया गया, लेकिन गौर साहब भी अधिक दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं टिक सके। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। उन्होंने 4 कार्यकाल में 15 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। इस कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने तमाम तरह के दावपेंच भी चले। उन पर डंपर और व्यापमं जैसे दाग भी लगे, लेकिन वे इन्हें सफाई से धोते हुए इनसे बाहर निकल गए। गौरतलब है कि इस मुकाम तक पहुंचने से पहले शिवराज सिंह चौहान को कई पड़ाव से गुजरना पड़ा। उन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ बनाने के लिए नर्मदा किनारे शादी न करने की कसम खाई लेकिन बाद में शादी कर ली। सत्ता में रहकर जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को वे कोसते रहे, सत्ता पाने के लिए उसी सिंधिया को सहारा बनाया। इस बीच 2018 में भाजपा को हराकर कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन वे डेढ़ साल से अधिक अपनों को साधकर नहीं रख पाए। ये सब ऐसे घटनाक्रम हैं, जिनसे डॉ. मोहन यादव को सबक लेकर काम करना होगा। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान के पास नरेंद्र सिंह तोमर जैसा सहयोगी था, वैसा यादव के पास नहीं है। इसलिए उन्हें ऐसा एक सहयोगी नेता बनाना होगा, जो दिल्ली से लेकर भोपाल तक सभी को साध सके।

कटीबद्ध हैं। उन्होंने अफसरों को सख्त निर्देश दिया है कि अवैध कामों को हर हाल में रोकें। लेकिन यह बात भी सत्य है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही सबसे अधिक गलत काम करते हैं। ऐसे में अगर अफसर उन पर नकेल कसते हैं तो उनके विरोध और खौफ का सामना मुख्यमंत्री कैसे कर पाएंगे। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और आकांक्षा पर मुख्यमंत्री को खरा उतरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को अपनों से पार पाना होगा। क्योंकि जब भी कोई राजनेता बड़े पद पर आता है। उसके नाते-रिश्तेदार अवैध गतिविधियों में जुट जाते हैं। मुख्यमंत्री के आसपास भ्रष्टाचार के ताने-बाने बुने जाने लगते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को अपने नाते-रिश्तेदारों को दूर रखना होगा। सरकार के कई मंत्री और उनके आसपास के लोग दलाली के काम में जुटे रहते हैं। इन सभी को साधना मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

वहीं मुख्यमंत्री के सामने एक और बड़ी चुनौती है, मंत्रियों को जिलों के प्रभार का आवंटन। 6 माह का समय गुजर गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं दिया है। इस कारण जिलों में विकास कार्यों की मॉनीटरिंग भी सही से नहीं हो पा रही है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि आगामी कुछ दिनों में मंत्रियों को जिले आवंटित हो जाएंगे। लेकिन किस मंत्री को कौनसा जिला दिया जाए, यह भी बड़ी चुनौती होगी।

● राजेन्द्र आगाल

मप्र कैडर के 29 आईपीएस को नई सीनियरिटी

मप्र के 29 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए सिरे से कैडर ईयर का आवंटन कर दिया है। इस सीनियोरिटी निर्धारण प्रक्रिया में मप्र कैडर के राज्य पुलिस सेवा के वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और वर्ष 2022 में आईपीएस पद पर प्रमोट होने वाले अफसरों की सीनियोरिटी तय की गई है। इसमें 8 अफसरों को 2012, एक अधिकारी को 2013 कैडर ईयर और बाकी 20 अधिकारियों को 2026 कैडर वर्ष आवंटन कर सीनियोरिटी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 2018 की सिलेक्शन लिस्ट में जिन प्रमोटी आईपीएस अफसरों को 2012 बैच मिला है उसमें आलोक कुमार, विजय कुमार भागवानी के नाम हैं। वर्ष 2019 में सिलेक्ट हुए राजीव कुमार को 2012 बैच मिला है। इसी तरह वर्ष 2020 में सिलेक्ट होने वाले अफसरों में निश्चल झारिया, रसना ठाकुर, संतोष कोरी, जगदीश डाबर, मनोहर सिंह मंडलोई को भी 2012 कैडर वर्ष आवंटित किया गया है। इसके बाद 2020 की सिलेक्शन लिस्ट में शामिल रामजी श्रीवास्तव को 2013, जितेंद्र सिंह पवार, सुनील तिवारी, संजीव कुमार सिन्हा, संजीव कुमार कंचन को भी 2016 कैडर वर्ष आवंटित किया गया है।

अब बदली-बदली नजर आएगी पुलिस

मप्र पुलिस 1 जुलाई से बदली-बदली नजर आएगी। पुराने कानूनों में संशोधन कर केंद्र द्वारा बनाए गए 3 नए कानून एक जुलाई से प्रदेश में भी लागू हो जाएंगे। प्रदेश में अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शहरी और ग्रामीण भीड़भाड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे निजी अस्पताल, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, कोचिंग संस्थान के बाहर जनसहयोग से लगाए जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग कानून बनाने पर काम कर रहा है। गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक इलाकों में अपराध को रोकने में अब सरकार जनता की मदद लेगी। ऐसे सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, शॉपिंग मॉल, कोचिंग, बैंक जहां हर दिन 100 से ज्यादा लोग आते हैं, उनको अपने सामने की सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसका एक माह का डाटा सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही किसी घटना पर पुलिस को जांच के लिए आवश्यक होने पर उसे अनिवार्य रूप से उपलब्ध भी करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा।

वहीं निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 (2005 का 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियों को नगद हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम 2018 अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त 2018 जारी की है। निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 (2005 का 29) की धारा 25 के तहत उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा रोकड़ परिवहन कार्यकलापों की सुरक्षा हेतु धारा 24 के तहत अधिसूचित केंद्रीय नियमों के अनुरूप नियम बनाए जाने को कहा गया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मॉडल नियमों के समरूप में मप्र निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम 2024 बनाए जा रहे हैं।

इन नियमों के बनाए जाने से रोकड़ परिवहन कार्यकलापों में होने वाले जोखिम पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। तथा उक्त कार्यकलापों में लगी हुई विभिन्न निजी सुरक्षा एजेंसियों एवं कैश हैंडलिंग एजेंसियों की कार्यवाहियों में एकरूपता आ सकेगी, साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य शासन द्वारा निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी निजी सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम 2020 के अनुरूप मप्र निजी सुरक्षा (विनियमन) नियम अधिसूचित किए जा रहे हैं। निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 (2005 का 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियों के केंद्रीय मॉडल नियम 2006 का अधिग्रहण करने के संबंध में निजी सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम 2020 अधिसूचना दिनांक 15 दिसंबर 2020 जारी की है।

निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 (2005 का 29) की धारा 25 के तहत उक्त अधिनियम के उद्देश्य पिछले 15 वर्षों के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निजी सुरक्षा उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजीटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के प्रमुख दृष्टिकोणों में तालमेल बिठाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मिनिमम गवर्मेंट और मेक्सिमम गवर्नेंस की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए धारा 24 के तहत अधिसूचित केंद्रीय नियमों के अनुरूप नियम बनाए जा रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मॉडल नियमों के समरूप में मप्र निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2024 आवश्यक संशोधनों सहित जा रहे हैं। इन नियमों के बनाए जाने से निजी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति सेवा शर्तों की कार्यवाहियों में एकरूपता आ सकेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

● **सुनील सिंह**

साक्षी सुरक्षा योजना को प्रभावी बनाने पर जोर

राज्य शासन द्वारा नई संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 398 के प्रावधान अनुसार राज्य में साक्षी संरक्षण योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित साक्षी संरक्षण योजना में ऐसे व्यक्तियों जो किसी अपराधी प्रकरणों में साक्षी अथवा पीड़ित हैं को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है। योजना के तहत न केवल साक्षी बल्कि उचित प्रकरण में उसके परिवारजनों को भी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे साक्षी न्यायालय में बिना किसी डर व दबाव के कथन दे सकें। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। जो मामले का परीक्षण कर साक्षी की सुरक्षा व संरक्षण के लिए निर्देश दे सकेंगे, साक्षी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। योजना के लागू होने से प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों में सजायाबी की दर में वृद्धि हो सकेगी। आम नागरिक बिना किसी डर दबाव के न्यायालय में अपने बयान दे सकेगा। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्र. 156/16, महेंद्र चावला विरूद्ध भारत संघ में भी केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकार को साक्षी संरक्षण योजना लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं।

आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगरीय निकाय

मप्र के नगर निगमों और निकायों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति यह है कि कर्ज लेकर शहरी विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इसकी वजह है टैक्स वसूली में लापरवाही। सरकार बार-बार निर्देशित कर रही है कि नगरीय निकाय टैक्स की लगातार वसूली करते रहें, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। इस कारण नगरीय निकाय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि कई निकायों में तो वेतन के लाले पड़ गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टैक्स वसूली बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा टैक्स वसूली में निकाय आगे रहे हैं। टैक्स वसूली के लिए शिविर लगाए गए और लोगों को टैक्स भरने के लिए जागरूक किया गया है। यह कार्य निरंतर जारी है। लेकिन दावों के विपरीत प्रदेश के कई नगर निगम, नगर पालिका और परिषदों की माली हालत इतनी बिगड़ गई है कि वे अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बार-बार के निर्देश के बाद भी नगर निगमों सहित सभी निकाय टैक्स वसूली में पिछड़ रहे हैं। नगर निगम भोपाल की बात की जाए तो यहां भी राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुसार नहीं हो पाई। 460 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है लेकिन 371 करोड़ रुपए की वसूली ही हो पाई है। दरअसल, भोपाल के कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां से निगम संपत्तिकर और जलकर की वसूली नहीं कर पाता है। इंदौर नगर निगम की आर्थिक स्थिति भी किसी से छुपी नहीं है। फर्जी बिलों के जरिए भले ही करोड़ों का भुगतान हो गया, लेकिन असली ठेकेदार अब भी भुगतान के लिए भटक रहे हैं। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 600 करोड़ रुपए संपत्तिकर के रूप में वसूली का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसमें से अब तक सिर्फ 25 करोड़ की वसूली ही हो सकी है। दरअसल ई-पोर्टल की गड़बड़ी का खामियाजा इंदौर निगम को उठाना पड़ रहा है। पोर्टल ने काम करना तो शुरू कर दिया लेकिन अब भी यह दो वर्ष से ज्यादा पुराना डेटा नहीं दिखा रहा है। यही वजह है कि निगम दो वर्ष से ज्यादा पुरानी वसूली नहीं कर पा रहा है। ग्वालियर नगर निगम के राजस्व वसूली अभियान की बात की जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व वसूली में कमी आई है। निगम 94 करोड़ संपत्तिकर और 24 करोड़ जल कर ही वसूल पाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में ही सवा चार करोड़ कम है। इस बार 242 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया था, जबकि केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए 112 करोड़ रुपए की वसूली की जानी थी। ग्वालियर को लगातार संपत्तिकर वसूली बढ़ाने के चलते 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन इस बार निगम का अमला इस लक्ष्य से लगभग 18 करोड़ रुपए पीछे है। जबलपुर नगर निगम के हालात और भी बिगड़ रहे हैं। कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े हैं। राजस्व वसूली में पिछड़ने के कारण निगम को 84 करोड़ रुपए का अनुदान कम मिला। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आयुक्त ने सरकार को पत्र लिखकर चेताया है कि ठेकेदारों को भुगतान न कर पाने के कारण वे काम बंद कर सकते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी भी हड़ताल पर जा सकते हैं। यही हाल अन्य निकायों का भी है।

निकायों द्वारा राजस्व की वसूली न कर पाना और आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों के वेतन पर हुए खर्च ने निकायों को संकट में ला दिया है। कम राजस्व वसूली के कारण सरकार ने भी निकायों को दिए जाने वाले चुंगी कर में कटौती कर दी है। जिसके चलते हालात और भी बिगड़ गए हैं। इन हालातों को देखकर राज्य सरकार ने सभी निकायों को निर्देश दिया है कि 2024-25 के लिए राजस्व वसूली का प्लान तैयार करें और संबंधित कलेक्टरों से कहा गया है कि वे इसकी नियमित निगरानी करें। हर माह इसकी समीक्षा की जाए। निकायों में सबसे बड़ी समस्या अनियमित नियुक्ति की है। निकाय के चुने हुए जनप्रतिनिधि सबसे पहले अपने चहेतों की निकायों में अनियोजित नियुक्तियां करते हैं। इससे आर्थिक बोझ बढ़ता है और निकायों की माली हालत प्रभावित होती है। एक बार नियुक्ति मिलने के बाद इन कर्मियों को हटाना मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक वर्ष बढ़ती नियुक्तियों का बोझ निकायों के लिए एक बड़ी मुसीबत है। इससे निपटने के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है।

● **जितेंद्र तिवारी**

कर्ज लेकर चला रहे काम

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर निगमों ने करोड़ों रुपए का कर्ज लिया हुआ है। प्रदेश के नगर निगमों पर 320 करोड़ 18 लाख रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए एमपीयूडीसी (मप्र अर्बन डेवलपमेंट कंपनी) के माध्यम से इंडियन बैंक और केनरा बैंक से 15 वर्ष के लिए कर्ज लिया गया है। कर्ज का मूलधन और ब्याज की राशि का 75 प्रतिशत भुगतान मप्र शासन और 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नगर निगमों द्वारा किया जाएगा। अधिकारियों की उदासीनता के चलते बिगड़ रहा बजट प्रदेश में 16 नगर निगम सहित 413 नगरीय निकाय हैं। निकायों का वित्तीय बजट टैक्स कलेक्शन पर निर्भर है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते निकायों में पर्याप्त टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाता है। सालाना टैक्स कलेक्शन 40 प्रतिशत से ऊपर नहीं पहुंच पाता है। इससे निकायों के विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। टैक्स कलेक्शन में कमी का एक बड़ा कारण अवैध निर्माण कार्य भी है।

अमृत सरोवर बने खेल का मैदान

मप्र में इस बार रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण जल संकट भी बढ़ गया है। ऐसे में सभी को प्रदेशभर में बने अमृत सरोवरों की याद आ रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और पशुओं के लिए पानी मुहैया कराने के लिए लाखों खर्च होने के बाद तैयार कराए गए अमृत सरोवरों में धूल उड़ रही है जिससे मवेशी पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। कई जिलों में तो अमृत सरोवर खेल का मैदान बनकर रह गए हैं जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। दरअसल, लाखों रुपए खर्च कर जब अमृत सरोवर बनाए जा रहे थे, तब लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाए गए। लेकिन अब अधिकांश अमृत सरोवर में एक बूंद भी पानी संरक्षित नहीं हो रहा है जिससे मवेशियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जबकि पशु-पक्षी भी पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। राजगढ़ में बने ऐसे ही 88 अमृत सरोवर मैदान में तब्दील हो गए हैं।

गौरतलब है कि गर्मी के प्रकोप से हर जन प्रभावित हो रहा है। निजी संस्थाएं अपने तौर पर इससे बचाव के साधन जुटा रही हैं। ऐसे में सरकार ने भी इसके लिए कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नगरीय निकायों को इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं जुटाने के लिए निर्देशित किया है। इसके तहत तेज गर्मी से राहत देने के लिए जगह-जगह ग्रीन नेट और वॉटर स्प्रे की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यावरण दिवस से जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस दौरान जल सम्मेलन के आयोजन किए जा रहे हैं। जल संरचनाओं के अतिक्रमण और जल स्रोतों को उपयोगी बनाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक प्याऊ संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तेज गर्मी से नागरिकों को बचाने के लिए शहर और गांव में आवश्यक शेड और छांव की व्यवस्था करें। जहां आवश्यक को ग्रीन नेट और वाटर स्प्रे से तेज गर्मी से लोगों को राहत दिलवाई जाए। स्थानीय निकाय सक्रिय भूमिका निभाएं। जानकारों का कहना है कि अगर मापदंडों के हिसाब से अमृत सरोवर बने होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती।

राजगढ़ में जल संरक्षण और ग्रीष्मकाल में मवेशियों से लेकर मनुष्यों को जल उपलब्धता के लिए बनाए गए अमृत सरोवर कागजों में भले ही पूरे हो गए, लेकिन मौके पर अब भी मैदान ही हैं। जिले में योजना के तहत 88 अमृत सरोवर बनाए गए, लेकिन गर्मी में इन सरोवरों में दूर-दूर तक चुल्लू भर पानी भी नजर नहीं आ रहा है। इन दिनों यह सरोवर मैदानों में तब्दील हो गए हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी योजना के तहत 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की थी। मिशन का उद्देश्य प्रत्येक जिले में 75-75 तालाब बनाना था। इसी के तहत राजगढ़ जिले में 94 अमृत सरोवर स्वीकृत किए थे, जिनमें से कागजों पर 88 पूरे हैं। इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि जलाशयों में जल संरक्षण होगा, जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी तो पानी होने स्थानीयजन रोजगार से भी जुड़ सकेंगे, लेकिन सरोवर बनाने के लिए जो लापरवाही बरती गई, उसका नतीजा दूसरे ही साल में दिखाई देने लगा है। जल संरक्षण के लिए जरूरी इंतजाम नहीं होने से यह सरोवर मैदानों में तब्दील हो गए। बड़े बांधों के किनारे के एक-दो सरोवरों को छोड़ दें तो 85 से अधिक सरोवरों में पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। जिले में 88 अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें से अधिकांश सरोवर ऐसे स्थानों पर बनाए हैं जहां या तो प्राकृतिक नाले के मार्ग में सीमेंट या मिट्टी की पाल तैयार कर दी गई है या किसी निजी कार्य के लिए मिट्टी, मुरम खोदे जाने के चलते पहले से मौजूद गड्ढों को तालाब में परिवर्तित कर दिया गया। यहां वर्षाकाल में कुछ पानी रहता है, लेकिन मानूसन विदा होते ही यह मैदान बन जाते हैं। लंबे समय तक पानी संरक्षण हो सके, इसके लिए प्रयास नजर नहीं आ रहे।

राजगढ़ से पाटन रोड पर नेसड़ी ग्राम पंचायत के जुगलपुरा में तालाबनुमा संरचना बनाई गई, लेकिन यहां पिछले चार महीनों से एक बूंद पानी नहीं है। मौके पर दूर-दूर तक लाल मैदान ही नजर आता है। तालाब के पास जरा सी हरियाली तक नहीं है। राजगढ़ की ग्राम पंचायत कलीखेड़ा के टिटोड़ी गांव में 2022 में ही अमृत सरोवर बना था। 24 लाख 87 हजार की लागत से बना यह तालाब दो वर्षाकाल देख चुका है, लेकिन इस साल तो यहां तालाब की जगह मैदान ही नजर आता है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में यहां पानी तो भरा लेकिन दीपावली के बाद ही तालाब सूखने लगा। पिछले चार-पांच माह से तो गड्ढों में जरा सा पानी ही रह गया है। पानी इतना कम है कि एक मवेशी की भी प्यास नहीं बुझ सकती।

● **प्रवीण सक्सेना**

जल स्त्रोतों की तलाश करेंगे कलेक्टर

बता दें, भारत सरकार की अमृत 2.0 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जल संरचनाओं के उन्नयन का काम हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सभी कलेक्टरों के नेतृत्व में जन प्रतिनिधि, सामाजिक तथा अशासकीय संस्थाओं और योजना व आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधीन काम कर रहे जन अभियान परिषद की सहभागिता के लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग नीरज मंडलोई ने सभी जिलों के कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा है कि अमृत 2.0 योजना में शामिल जल स्रोतों के उन्नयन का काम इस अभियान में पूरा कराया जाए। कलेक्टरों से कहा है कि पहले से जहां काम चल रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई जल स्त्रोत उपलब्ध है और उसके पुनर्जीवन व संरक्षण की आवश्यकता है तो इन संरचनाओं का उन्नयन कार्य स्थानीय, सामाजिक व अशासकीय संस्थाओं एवं जनभागीदारी से काम कराया जाए। जल स्रोतों में गंदे पानी के नाले, नालियों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के जरिए डायवर्ट कर उसका शुद्धिकरण किया जाए, और फिर जल स्रोतों में छोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे जल स्रोतों में जल प्रदाय, पर्यटन, भूजल संरक्षण, मस्त्य पालन, सिंघाड़े का उत्पादन भी जीर्णोद्धार व नवीनीकरण के माध्यम से किया जाए। जल संरचनाओं के चयन एवं उन्नयन कार्य में जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जाए। जल स्रोतों के मौके पर जाकर चिन्हित संरचना की मोबाइल एप के माध्यम से जियो टैगिंग की जाए। निकायों में पदस्थ अमृत 2.0 योजना के तकनीकी सलाहकारों की सहायता ली जाए।

सफेद हाथी बने निगम-मंडल

करीब 20 साल पहले देश के बीमारू राज्यों में शामिल मप्र आज विकसित राज्यों की कतार में खड़ा है, लेकिन मप्र में विकास को गति देने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं (निगम-मंडलों) पर है वे अधिकारियों की भर्राशाही और लापरवाही के कारण घाटे की चपेट में आ गई हैं। इनका घाटा इतना बढ़ गया है कि सरकार इन्हें बद करने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि मप्र में सरकार ने विकासात्मक कार्यों के लिए निगम-मंडलों का गठन किया है। ये संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र के कार्यों की जिम्मेदारी संभालती हैं। इनके सर्वेसर्वा आईएएस अधिकारी होते हैं। इन कंपनियों में पदस्थ रहे अफसरों ने पिछले डेढ़ दशक के दौरान अपनी मनमानी से काम किया है। जिसका असर यह हुआ है कि अधिकांश निगम-मंडल घाटे में चल रहे हैं।

मप्र में अधिकांश नगर निगम सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। जहां मप्र राज्य भूमि विकास निगम, मप्र लेदर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मप्र स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड और मप्र राज्य उद्योग निगम लिमिटेड बंद हो चुके हैं। वहीं मप्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मप्र महिला वित्त एवं विकास निगम और मप्र स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोर घाटे में हैं। अब घाटे में चल रहे प्रदेश के निगम-मंडलों को सरकार बंद करने की तैयारी में है। ऐसे निगम, मंडल और बोर्ड जिनसे शासन को या प्रदेश के नागरिकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके बावजूद वे संचालित होकर सरकार पर वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं, उनकी जानकारी मांगी गई है। वहीं, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) ने भी घाटे में चल रहे निगम-मंडलों के वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसी संदर्भ में वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर ऐसे निगम- मंडलों की 12 बिंदुओं में जानकारी मांग ली है।

बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद ऐसे निगम-मंडलों को सूचीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 46 निगम, मंडल, प्राधिकरण और बोर्डों में सरकार नियुक्तियां भी निरस्त कर चुकी है। कैग ने 31 मार्च, 2022 की रिपोर्ट में बताया है कि मप्र में ऐसे 72 में से 40 उपक्रम निष्क्रिय रहे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम तीन से 32 साल तक निष्क्रिय रहे। कैग ने राज्य शासन को यह भी सुझाव दिया है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के इन सभी उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करे और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। ऐसे निष्क्रिय सरकारी उपक्रम जैसे निगम मंडल, बोर्ड की समीक्षा कर उनके पुनरूद्धार या उन्हें समाप्त करने के लिए उचित निर्णय लें। इनमें मप्र पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, विद्युत वितरण कंपनियां, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मप्र वन विकास निगम, मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मप्र सड़क परिवहन निगम, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, मप्र माइनिंग कॉर्पोरेशन सहित अन्य निगम मंडल और बोर्ड शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवराज सरकार के दौरान बनाए गए विभिन्न बोर्ड और प्राधिकरणों की सूची भी तलब की है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार उन बोर्ड और प्राधिकरणों को भी बंद करने का निर्णय ले सकती है, जिनका पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में गठन किया गया था। विधानसभा चुनाव के पहले रजक, वीर तेजाजी, परशुराम कल्याण, तेलघानी, विश्वकर्मा, स्वर्णकला, कुश, महाराणा प्रताप, जय मीनेश, मां पूरी बाई कीर, देवनारायण सहित अन्य कल्याण बोर्ड गठित किए थे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक प्रोफार्मा भेजा है। इसमें उन्हें 12 बिंदुओं की जानकारी भरकर भेजना है। इनमें समस्त सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियों की सूची मांगी है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एवं वर्ष के अंत तक निवेशित राशि बतानी होगी। शेयरों की संख्या और भुगतान के योग बताने होंगे। शेयर की श्रेणी को भी उल्लेखित करना होगा। यदि निगम हानि में चल रहा हो तो मार्च 2024 के अंत तक पूर्ण हानि का विवरण उसके कारणों सहित बताना होगा। 31 मार्च, 2023 की स्थिति में परीक्षित लेखा की प्रति उपलब्ध करानी होगी और संस्था के अतिरिक्त लाभ में आने की तिथि से वर्षवार निवेशित राशि बतानी होगी।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

प्रदेश के लिए बोझ बने निगम मंडल

प्रदेश में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसायटी के आधार पर निगम-मंडलों की स्थापना की गई थी। इनकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि राज्य में सुव्यवस्था, विकास, रोजगार और आम लोगों को सुख-सुविधाएं मिलें। लेकिन निगम मंडल अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। प्रदेश में संचालित 23 निगम मंडलों में से मात्र 2 ही निगम मंडल ऐसे हैं, जो अपनी स्थापना से लेकर आज तक लाभ में चल रहे हैं। शेष 21 निगमों में से कुछ निगम पिछले पांच सालों में अच्छी स्थिति में आ पाए हैं तो कुछ निगम ऐसे भी हैं जो स्थापना से लेकर आज तक सफेद हाथी बने हुए हैं। आज वर्तमान परिदृश्य में कई निगमों के हालात इतने बदतर हैं कि अब उन्हें बंद करने के अतिरिक्त और कोई चारा सरकार के पास नहीं है। निगम मंडलों के गठन के समय प्रबंध संचालकों को दैनिक कार्य और व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने और अध्यक्ष एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निगम के नीति निर्धारण तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य सौंपा गया था। देखा जाए तो यह व्यवस्था एक तरह से चैक-बैलेंस के लिए की गई थी, लेकिन धीरे-धीरे निगम मंडल के अध्यक्ष पद पर राजनीतिक लोगों का कब्जा होने लगा और इन लोगों ने संस्था के मूल उद्देश्यों के बजाय अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों को पूरा करने में रूचि ली साथ ही सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए निगमों के उत्पादों और सेवाओं को भी प्रभावित किया। इतना ही नहीं इन लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए समर्थकों और रिश्तेदारों को अनावश्यक रूप से भर्ती कर लिया। ऐसे में जहां एक ओर निगमों पर अनावश्यक स्थापना व्यय बढ़ा वहीं दूसरी ओर निगमों में अयोग्य और अकुशल कर्मचारियों की भर्ती होने से उनकी व्यवसायिक कुशलता भी कम हो गई। जिसके चलते निगमों में अपेक्षाकृत लाभ की बजाय हानि हो रही है।

केंद्रीय संगठन से मिले लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाजपा ने जिस सामूहिकता के साथ 24×7 काम किया, उसी का परिणाम है कि 40 साल बाद (जब मप्र-छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था) मप्र में किसी पार्टी ने लोकसभा की सभी सीटें जीत ली है। भाजपा की इस जीत के शिल्पकार मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री (अब केंद्रीय मंत्री) शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं।

सामूहिकता से मिली ऐतिहासिक जीत

मप्र में भाजपा ने पहली बार लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। 1980 से 2024 तक हुए 12 चुनावों में यह पहला मौका है, जब प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद काबिज हुए हैं। इससे पहले 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। वर्ष 2000 से पहले अविभाजित मप्र में लोकसभा की 40 सीटें थीं। इन सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। अब ठीक 40 साल बाद 2024 में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। यह जीत ऐसे समय मिली है, जबकि भाजपा का दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा है। दरअसल प्रदेश में भाजपा संगठन व सत्ता ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा, जिसे तोड़ पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया था। इसके लिए भाजपा के रणनीतिकारों ने पांच स्तरीय चुनावी घेरा तैयार किया था। जिसकी कमान पार्टी ने अपने 6 बड़े सेनापतियों को सौंप रखी थी। इनमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री (अब केंद्रीय मंत्री) शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल थे।

दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सरकार बनने के बाद सरकार से लेकर संगठन तक कुछ माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया था, जिसका परिणाम अब सामने है।

मप्र में सत्ता और और संगठन के नेताओं ने लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के पहले से ही प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। मिशन-29 को पता करने के लिए भाजपा नेताओं ने 24×7 काम किया। कोई कार्यालय में बैठकर, तो कोई क्षेत्र में घूम-घूमकर रणनीति को अंजाम देने में लगा रहा। इसी का परिणाम रहा कि देश की दो सबसे बड़ी जीत मप्र को मिली है। इंदौर से भाजपा सांसद शंकर लालवानी 11 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोटों से जीतकर दूसरे नंबर पर हैं। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी ने नोटा में सर्वाधिक वोटों के साथ ही लोकसभा चुनावों के इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया है। इससे पहले 2019 में गुजरात के नावासार सीट पर भाजपा के सीआर पाटिल ने 6,89,668 वोटों से जीतकर अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं इन भाजपा नेताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि भाजपा ने कमलनाथ के गढ़ पर 26 साल बाद एक बार फिर कब्जा जमाया है। यहां 1997 में हुए उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराया था। अब 2024 में भाजपा के विवेक साहू बंटी ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मात दी है। साहू को कमलनाथ ने पिछले विधानसभा चुनाव में हराया था, लेकिन

ये बने जीत के शिल्पकार

लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार मप्र में पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर जो नया इतिहास रचा है उसके शिल्पकार 6 नेता रहे। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री (अब केंद्रीय मंत्री) शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल थे। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सरकार बनने के बाद सरकार से लेकर संगठन तक कुछ माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया था, जिसका परिणाम अब सामने है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उप्र, बिहार तक रोड शो और प्रचार-प्रसार किया, लेकिन मप्र में अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद से पहली बार ऐसा मौका आया है, जब मप्र में सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का इस चुनाव परिणाम से पार्टी में कद बढ़ गया है। सभी सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस के गढ़ में लगातार सेंध लगाई।

लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट को जीतने में पूरी ताकत झोंक दी थी। मप्र में 1989 से भाजपा की ताकत लगातार बढ़ी है। इंदौर, भोपाल, भिंड और दमोह सीट पर भाजपा ने 1989 से लगातार अपनी जीत इस बार भी बरकरार रखी है। इंदौर में वर्ष 1984 में कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी जीते थे। इसके बाद 1989 से लगातार भाजपा के कब्जे में यह सीट रही है। यही स्थिति भोपाल की है। यहां से आखिरी बार कांग्रेस प्रत्याशी केएन प्रधान 1984 में जीते थे। इसके बाद यहां भी 1989 से लगातार यहां भाजपा जीतती रही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को यहां से लड़ाया, पर उन्हें भी हार मिली। इस बार पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव को मात दी है। भिंड, विदिशा और दमोह में भी 1989 से भाजपा ही जीतती रही है। जबलपुर, मुरैना, बैतूल और सागर में भाजपा वर्ष 1996 से लगातार जीत रही है।

प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप किया और 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा ने प्रदेश की 29 सीटों पर करीब 59.5 प्रतिशत वोट हासिल किए। यह 2019 के 58.5 प्रतिशत के मुकाबले सिर्फ एक प्रतिशत ज्यादा रहा। कांग्रेस की बात करें तो 2019 के 34.8 प्रतिशत के मुकाबले 32.19 प्रतिशत वोट ही हासिल किए। यह करीब-करीब ढाई प्रतिशत की कमी बताता है। यह बात अलग है कि इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया था। वहीं, खजुराहो सीट को कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ा था। प्रदेश में भाजपा की जीत में पन्ना समिति की भूमिका अहम रही। खासकर तीसरे और चौथे चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं को घर से बाहर निकालकर मतदान केंद्रों तक ले जाने की रणनीति को सफलता मिली थी। इसी का नतीजा है कि भाजपा ने ग्वालियर-चंबल अंचल की मुश्किल सीटों पर भी जीत हासिल की। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कई स्तरों पर रणनीति रची गई थी। पहला तो कांग्रेस को कमजोर करना था। इसके लिए उन नेताओं की तलाश शुरू हुई, जो भाजपा में आ सकते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण

ठुकराकर कांग्रेस ने यह मौका भी दे दिया। कांग्रेस के छोटे-बड़े करीब चार लाख कार्यकर्ता भाजपा से जुड़े। इससे जमीनी स्तर पर कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का टोटा हो गया। प्रदेश के कई मतदान केंद्रों पर तो कांग्रेस की टेबल तक नहीं लगी। इससे भाजपा के पक्ष में माहौल बना। प्रदेश में करीब छह महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को 48.55 प्रतिशत मत मिले थे और कांग्रेस को 40.40 प्रतिशत। इसके मुकाबले लोकसभा चुनावों में भाजपा के वोट करीब 11 प्रतिशत अधिक है। यह पहली बार नहीं हुआ है। 1984 के बाद से जब भी प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव हुए, भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2018 के विधानसभा चुनावों में 41.02 प्रतिशत वोट भाजपा को मिले थे, जबकि उसके बाद 2019 लोकसभा चुनावों में करीब 58.5 प्रतिशत वोट उसे मिले थे।

1980 में भाजपा की स्थापना हुई और 1984 का लोकसभा चुनाव पार्टी का राज्य में पहला बड़ा चुनाव था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में कांग्रेस ने 57.1 प्रतिशत वोट के साथ राज्य की सभी 40 में से 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा को तब 30 प्रतिशत वोट मिले थे। इसके बाद के पांच साल में जैसे-जैसे राम मंदिर आंदोलन ने गति पकड़ी, भाजपा को आधार मिलता गया। भाजपा ने 1989 में 39.7 प्रतिशत वोट के साथ 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 37.7 प्रतिशत वोट के साथ सिर्फ आठ सीटें मिली थीं। 1991 में कांग्रेस ने दिल्ली की कुर्सी पर वापसी की, लेकिन भाजपा का वोट नहीं घटा। कांग्रेस ने 45.3 प्रतिशत वोट के साथ 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़कर 41.9 प्रतिशत हुआ था। उसे 12 सीटों पर ही जीत मिली थी। 1996 में 41.3 प्रतिशत वोट के साथ 27 सीटें, 1998 में 45.7 प्रतिशत वोट के साथ 30 सीटें और 1999 में भाजपा ने 46.6 प्रतिशत वोट के साथ 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। वर्ष 2000 में मप्र का विभाजन हुआ। 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में चली गईं। विभाजित मप्र का पहला लोकसभा चुनाव 2004 में हुआ और भाजपा ने 48.1 प्रतिशत वोट के साथ 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 34.1 प्रतिशत वोट के साथ 4 सीटें मिली थीं। 2009 में कांग्रेस ने वापसी की थी। कांग्रेस के युवा नेताओं ने भाजपा के स्थापित नेताओं को मात देकर 29 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसे 40.1 प्रतिशत वोट मिले थे।

● **कुमार विनोद**

मप्र के अलावा अन्य राज्यों में भी दिखा दम

मप्र की 29 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने वाले मप्र भाजपा के नेताओं का दूसरे राज्यों में दम दिखा। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने गए। डॉ. मोहन यादव ने 8 राज्यों की 33 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया। इनमें से भाजपा ने 13 सीटें जीतीं। वहीं, शिवराज 3 राज्यों की 13 सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। इनमें से भाजपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा ने डॉ. मोहन यादव को उप्र, बिहार और झारखंड की ऐसी सीटों पर प्रचार के लिए भेजा था, जो यादव बहुल सीटें हैं, जबकि शिवराज सिंह ने दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीटों पर प्रचार किया था। वहीं, भाजपा नेताओं का कहना है कि बाहरी राज्यों की कौनसी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, कौनसी सीटें हार गई, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एनडीए की सरकार सभी के प्रयासों से बनी है। भाजपा ने उप्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना में डॉ. मोहन यादव का पूरा अभियान यादव बहुल इलाकों में ही बनाया था। चार चरणों तक मप्र में पार्टी का नेतृत्व करने की वजह से वे यहीं डटे रहे।

सीमाओं का होगा पुनर्निर्धारण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश में संभाग और जिलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए सरकार जिला पुनर्गठन आयोग बनाने जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 10 संभाग और 55 जिले हैं। अब सरकार की प्राथमिकता है कि इनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाए। आयोग प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जन अपेक्षाओं के आधार पर और अधिक जनोन्मुखी एवं सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान संभाग, जिला, तहसील एवं जनपद विकासखंड प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन के संबंध में अनुशंसाए करेगा। भविष्य में नवीन प्रशासनिक इकाईयों के गठन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंध में अनुशंसाएं करेगा। प्रशासनिक इकाईयों की पद संरचना एवं उनके आकार एवं कार्यों के अनुपात में पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक इकाईयों की पदीय संरचना के युक्तियुक्तकरण की अनुशंसा भी आयोग करेगा। प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन हेतु संबंधित संभाग, जिले का भ्रमण कर सुझाव प्राप्त करेगा और प्रशासनिक इकाईयों की दक्षता बढ़ाने के लिए अन्य अनुशंसाएं करेगा।

जानकारी के अनुसार जिला पुनर्गठन आयोग बनने के बाद सीमा निर्धारण के प्रस्ताव संभागों के प्रभारी अधिकारी अपर मुख्य सचिव बनाकर आयोग को देंगे। जिसे सरकार को भेजा जाएगा। जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसमें विशेष तौर पर यह ध्यान रखा जाएगा कि आमजन को जिला या संभागीय मुख्यालय पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े। नए जिलों के प्रस्तावों को भी पुनर्गठन आयोग ही देखेगा। प्रदेश में कई गांव या कस्बे जिला मुख्यालयों से बहुत दूर हैं। यहां आने-जाने में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं, प्रशासनिक स्तर पर भी कठिनाई होती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की गई संभागीय समीक्षाओं में जब यह विषय आया तो उन्होंने इसे व्यावहारिक रूप देने के निर्देश अधिकारियों को दिए पर इंदौर को छोड़कर कहीं भी ठोस काम नहीं हुआ। पिछले दिनों उन्होंने संभागीय समीक्षाओं में दिए निर्देशों पर अमल की स्थिति की समीक्षा की तो बताया गया कि इंदौर संभाग ने इस पर काम किया है और प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजा जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिला पुनर्गठन आयोग बनाया जाए। ब्लॉक, जिला और संभाग की सीमा के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव प्रभारी अधिकारी यानी अपर मुख्य सचिवों के माध्यम से आयोग को भेजे जाएं। आयोग इनका परीक्षण करे और अनुशंसा शासन को सौंपे, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाए। इस कार्य को अधिक लंबा नहीं खींचना है इसलिए तेजी के साथ काम किया जाए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग के गठन की तैयारी प्रारंभ कर दी है। सूत्रों का कहना है कि आयोग का गठन जून में हो जाएगा और सितंबर तक सभी प्रभारी अधिकारी प्रस्ताव इसे भेज देंगे। प्रदेश में अब नए जिलों का गठन भी इसी आयोग के माध्यम से होगा। ब्लॉक, जिला और संभाग की सीमाओं के पुनर्निर्धारण में जनप्रतिनिधियों की राय ली जाएगी। जिला व जनपद पंचायत के सदस्यों से भी जानकारी ली जाएगी। दरअसल, मुख्यमंत्री का मानना है कि मैदानी स्तर पर कोई भी ऐसा निर्णय जो बड़े वर्ग को प्रभावित करता है वह जनप्रतिनिधियों की सहमति से ही होना चाहिए क्योंकि वे मंत्रालय में बैठे अधिकारियों की तुलना में स्थानीय परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

भोपाल मुख्यालय में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होंगे

मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा। आयोग एक वर्ष के लिए बनाया गया है और जरूरत के मुताबिक इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। आयोग में तीन सदस्य होंगे, इनमें से एक आयोग का अध्यक्ष होगा। आयोग के अध्यक्ष के पद पर पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव योग्यता रखने वाले व्यक्ति की तैनाती होगी। अध्यक्ष को राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के समकक्ष वेतनमान और उस पर समय-समय पर महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। इसमें से उन्हें प्राप्त पेंशन घटाई जाएगी। केंद्र या राज्य शासन में 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके तथा राज्य सरकार में सचिव या उसके समकक्ष स्तर से सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को सदस्य बनाया जाएगा। सदस्य को राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष वेतनमान और उस पर देय महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। उसमें से पेंशन घटाई जाएगी। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का प्रशासकीय विभाग राजस्व विभाग तथा विभागाध्यक्ष एवं बजट कंट्रोलिंग अधिकारी प्रमुख राजस्व आयुक्त मप्र होंगे। कार्यालय की साज-सज्जा और अन्य भुगतान कार्य प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी करेंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को सभी भत्ते और सुविधाएं जैसे आवास, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, अवकाश, चिकित्सकीय उपचार सुविधा, दूरभाष कार्यालय एवं निवास पर इंटरनेट सुविधा सहित जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल रहेगा। वाहन सुविधा उसी स्तर की मिलेगी जैसी उन्हें सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होती रही है। आयोग में सचिव प्रशासनिक अधिकारी का एक पद होगा, इसमें सचिव-अपर सचिव स्तर से सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की तैनाती की जाएगी। उसे राज्य सरकार के सचिव को देय वेतनमान और भत्ते देय होंगे। इसमें से पेंशन घटाई जाएगी, बाकी सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा संयुक्त संचालक वित्त, लेखाधिकारी की तैनाती प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के लेखाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देकर की जाएगी। पांच सदस्यीय सलाहकार, तकनीकी टीम की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से आयोग करेगा। अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव हेतु निज सहायक, स्टेनोग्राफर सहित कुल चार पद पर संविदा या आउटसोर्स से आयोग नियुक्त करेगा। लेखापाल के एक पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा नियुक्ति की जाएगी। कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर के पांच पद संविदा अथवा आउटसोर्स से भरे जाएंगे। भृत्य के पांच पद आउटसोर्स से नियुक्त किए जाएंगे।

फर्जी खरीदी में भुगतान असली

सतना जिले में सरकार द्वारा बनाए गए खरीदी केंद्र से 96 लाख रुपए के फर्जी गेहूं खरीदी और भुगतान ने पूरी खरीदी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस गठजोड़ में शामिल ट्रांसपोर्टर, बिचौलिए, अफसर और कर्मचारियों की मिलीभगत से गेहूं खरीदे बिना ट्रकों से परिवहन बताकर उसे रेलवे रैक पर उतारना बता दिया गया और किसानों को पेमेंट भी कर दिया गया। राज्य शासन ने इस मामले के संज्ञान में आने के बाद सतना जिले में पदस्थ नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक अमित गौड़ दर्जनों लोगों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फर्जी खरीदी में असली भुगतान का बड़ा मामला सामने आने के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में गेहूं खरीदी केंद्रों की जांच नहीं करवाई गई है।

गौरतलब है कि प्रदेश में हर साल गेहूं खरीदी में भ्रष्टाचार सामने आता है। इस बार जब सतना में घोटाला सामने आया तो लगा था कि पूरे प्रदेश में जांच अभियान चलेगा। लेकिन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग व नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने अपनी सुस्त कार्यप्रणाली का एक और उदाहरण दिया है। इधर साइबर मामलों के जानकारों का कहना है कि जब खरीदी केंद्र पर ऑनलाइन धोखाधड़ी कर हवा में 13 ट्रक गेहूं की खरीदी व परिवहन किया जा सकता है तो दूसरे केंद्रों पर ऐसी ऑनलाइन धोखाधड़ी न हुई हो, यह मान लेना ठीक नहीं है। इसलिए इनमें से कुछ केंद्रों पर कम से कम रेंडम जांच की जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा का कहना है कि कारीगोही केंद्र पर खरीदी व फर्जी परिवहन से जुड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद सतना के कई केंद्रों और गोदामों में भौतिक सत्यापन कराया जा चुका है। अब तक कोई गड़बड़ी नहीं मिली। आगे कार्रवाई जारी रहेगी।

दरअसल सरकारी गेहूं खरीदी पर घोटाले का दाग लग गया, फिर भी सतना के 128 केंद्रों को छोड़ प्रदेश के बचे 3152 में से एक भी केंद्र पर खरीदी की रेंडम जांच नहीं हुई। यह स्थिति तब है, जब सतना के कारीगोही खरीदी केंद्र पर 93 लाख रुपए का गेहूं खरीदी घोटाला सामने आ चुका है। फूड विभाग के अफसरों पर खरीदी की जिम्मेदारी होती है, तो नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड खरीदी की नोडल एजेंसी है। अब दोनों के जिम्मेदारों ने कहा कि सतना मामले की जांच कर संबंधितों पर एफआईआर करा दी गई है। साथ ही बाकी के केंद्रों को क्लीनचिट दे दी। प्रदेश में गेहूं खरीदी लक्ष्य के 50 फीसदी भी नहीं पहुंची है। 26 मई तक 48 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन का है। अब तक सरकार तारीख 3 बार बढ़ा चुकी है। अब 25 जून तक खरीदी की जाएगी।

खाद्य, राजस्व अफसरों की भी मिलीभगत

जिन किसानों के खाते में गेहूं बेचने के नाम पर भुगतान कर पैसे भेजे गए हैं वे सभी इस गिरोह से जुड़े अफसरों से मिलीभगत में शामिल हैं। इस पूरे मामले में खाद्य और नागरिक आपूर्ति के अफसरों के साथ राजस्व विभाग के अफसरों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि जिन किसानों को गेहूं खरीदने के नाम पर भुगतान किया गया है उनके नाम पर संबंधित क्षेत्र में फसल बोने की मंजूरी देने का काम रिकॉर्ड में बताया गया। सतना के कारीगोही केंद्र में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में किए घोटाले के 19 फर्जी किसानों की पहचान कर ली गई है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके बैंक खातों पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि इनमें से 1 ही किसान को फर्जी खरीदी के बदले भुगतान किया था। राशि मिलते ही उसने दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी थी। उक्त फर्जी किसान ने जिस अन्य खाते में राशि ट्रांसफर की, उस खाते पर भी रोक लगा दी गई है। घोटाला 13 मई को सामने आया था। मामले में 8 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। इन आरोपियों ने 13 ट्रक गेहूं परिवहन करना बताया था, जो कि वास्तव में किया ही नहीं गया। ये सरकार को 93 लाख रुपए का चूना लगाने की फिराक में थे। इस मामले में नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के सतना जिला प्रबंधक अमित गौड़ को निलंबित किया जा चुका है। अब मामले की जांच सतना पुलिस की निगरानी में बनी एसआईटी कर रही है।

जयमाल समूह खरीदी केंद्र के प्रबंधक और ऑपरेटर की आईडी पासवर्ड का उपयोग कर गेहूं खरीदी की गई और उसे उपार्जन पोर्टल पर फीड किया गया। नागरिक आपूर्ति निगम सतना के प्रबंधक व ऑपरेटर की आईडी पासवर्ड से यह गेहूं ट्रांसपोर्ट के लिए मंजूर किया गया। ट्रांसपोर्टर ने पोर्टल में खरीदी केंद्र भेजे जाने वाले ट्रकों के नंबर की एंट्री अपनी आईडी पासवर्ड के जरिए की और ट्रकों को भेजना दिखा दिया जबकि वास्तव में कोई ट्रक रवाना नहीं हुआ। ट्रकों के खरीदी केंद्र पहुंचे बिना ही खरीदी केंद्र प्रबंधक व ऑपरेटर की आईडी से इन ट्रकों में गेहूं लोड करना बताया गया और ट्रकों को लखनवाह वेयर हाउसिंग से रवाना होना बताया गया। इस बीच डीएम नान कार्यालय के जरिए निर्देश जारी किए गए कि ट्रकों को गोदाम न ले जाकर रेलवे रैक प्वाइंट लाएं।

नियमानुसार ट्रकों के रवाना होने के बाद स्थल डायवर्जन सिर्फ डीएम नान गोदाम भर जाने, भेजा गया गेहूं नान एफएक्यू होने या रेलवे में रैक आने पर कर सकते हैं। ये स्थितियां न होने के बाद भी डीएम नान द्वारा बिल्टी को डायवर्ट कर गोदाम से रेलवे रैक प्वाइंट आने कहा गया। रेलवे रैक प्वाइंट आने के पहले धर्म कांटे में तौल होना जरूरी है लेकिन बिना धर्म कांटे में तौल के इनका वजन दिखाया गया। रेलवे रैक प्वाइंट पर ट्रकों के पहुंचे बिना ही नान के संबंधित सर्वेयर की आईडी पासवर्ड से गेहूं को अनलोड करना बता दिया गया। रैक प्वाइंट पर उतरने वाले गेहूं की स्वीकृति के बाद जस्ट इन टाइम सिस्टम से भुगतान की स्वीकृति डीएम नान के आईडी पासवर्ड से कर दी गई और राशि किसानों के खाते में पहुंच गई।

● **सिद्धार्थ पांडे**

लोकसभा चुनाव की 83 दिन की आचार संहिता हटते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री ने अफसरों के सामने अपना रोडमैप रख दिया है कि प्रदेश में सुशासन और विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। इसलिए अब सरकार का पूरा फोकस विकास पर रहेगा, ताकि प्रदेश में औद्योगिक विकास हो सके और हर युवा को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ने अफसरों को भी निर्देशित कर दिया है कि सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सरकार का अब पूरा फोकस विकास पर केंद्रित हो गया है।

अब विकास पर फोकस

मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही मिशन मोड में काम कर रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आचार संहिता की पाबंदिया समाप्त होते ही एक बार फिर एक्शन में आ गए हैं। इसी के तहत 7 जून को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले के आष्टा तहसील में लगाई जाने वाली देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय रोजगार का सृजन होगा और प्रदेश के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने परियोजना के लिए जरूरी भूमि के अधिग्रहण को लेकर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सीहोर जिले के आष्टा तहसील में लगभग 60,000 करोड़ के निवेश से बनने वाली यह परियोजना देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना होगी। इस परियोजना में ग्रीन फील्ड पेट्रोकेमिकल परिसर भी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत एलएलडीपीई, एचडीपीई, एमईगी और प्रोपीलीन जैसे पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन होगा। इस परियोजना के माध्यम से निर्माण अवधि के दौरान 15,000 व्यक्तियों तथा संचालन अवधि के दौरान लगभग 5,600 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। परियोजना में 70 हेक्टेयर का टाउनशिप भी प्रस्तावित है। परियोजना का भूमिपूजन आगामी फरवरी तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन वित्त वर्ष 2030-31 में प्रारंभ होने की संभावना है।

गौरतलब है कि प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए नई इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए कई तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इसके अलावा माइनिंग, सीमेंट और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मप्र में भाजपा सरकार ने कृषि विकास दर 25 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। अब दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमूल के साथ मिलकर काम करने की योजना है। औद्योगिक विकास हो सके और हर युवा को रोजगार मिल सके इसके तहत प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए चार नए आइटी पार्क शुरू किए जा रहे हैं। उज्जैन, रीवा में आइटी पार्क बनाया जाएगा। भोपाल में दूसरा आईटी पार्क बनाया जाएगा। अब यह स्मार्ट सिटी परिसर में बनाया जाएगा। इंदौर में चौथे आइटी पार्क का काम शुरू हो गया है। यह कंपनियों की जरूरतों के अनुसार बनाए जा रहे हैं, ताकि बड़ी कंपनियां आ सकें। इससे युवाओं को आईटी सेक्टर में नौकरी करने के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। चुनाव के बाद अब विकास कार्य शुरू हो रहे हैं। आइटी पार्क सरकार की प्राथमिकता में हैं। क्योंकि इंदौर को छोड़ दें तो अन्य शहर इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसलिए उद्योग विभाग ने नए आइटी पार्क बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार उज्जैन में आइटी पार्क इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बनाया जाएगा। 2.5 हेक्टेयर जमीन चिह्नित कर ली गई है। एक

गुजरात जैसा मप्र बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मप्र में गुजरात जैसा विकास करना चाहते हैं। उनका कहना है कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों की बात हो, उद्योग-धंधों की बात हो या फिर पर्यटन, हर स्थिति में गुजरात मॉडल ही सामने होता है। मेरा लक्ष्य है कि देश में गुजरात की तरह मप्र भी जाना जाए। उनकी प्राथमिकता है कि मप्र की साढ़े आठ करोड़ जनता ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन-कल्याण, सुशासन और विकास मेरी प्राथमिकता है। मोदीजी की गारंटी पूरी करना और संकल्प-पत्र में जनता से किए गए वादों को धरातल पर उतारना मेरी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित की गईं चार जातियां गरीब, किसान, युवा और महिला का कल्याण मेरी प्राथमिकता है। मप्र आत्मनिर्भर और विकसित भारत का आधार-स्तंभ बने, यह मेरी प्राथमिकता है। बिना थके, बिना रुके मप्र के कल्याण के लिए अनवरत कार्य करना ही मेरी प्राथमिकता है। किसान मप्र की रीढ़ और मुकुट हैं। पिछले 20 वर्षों में भाजपा सरकार ने प्रदेश को बीमारू से बेमिसाल राज्य बना दिया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसानों का ही है। प्रदेश को सात बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलना इसका प्रमाण है। बात परंपरागत खेती की हो, प्राकृतिक खेती की हो या फिर श्रीअन्न उत्पादन की, हमारे किसान हर मोर्चे पर अग्रणी हैं।

साल में तैयार होने की संभावना है। रीवा में 50 हजार वर्गफीट में शहर में ही पार्क बनाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि भोपाल में नया आइटी पार्क शहर के बीच में स्मार्ट सिटी परिसर में बनाया जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन से बात की गई है। कॉर्पोरेशन जितनी जमीन उपलब्ध कराएगा उस हिसाब से उद्योग विभाग भुगतान कर देगा। इसके पहले आरजीपीवी के पास बड़बई में आइटी पार्क बनाया गया है, लेकिन वह क्षेत्र शहर से दूर होने के कारण कोई बड़ी कंपनी नहीं आई है। अधिकारियों का कहना है कि आईटी कंपनी में काम करने वाले युवा हायर क्लास के होते हैं। उन्हें अच्छा एबिएंस और नाइट कल्चर भी रास आता है। इसलिए बड़ी कंपनियां ऐसी जगह ऑफिस खोलना ज्यादा पसंद करती हैं जो आधुनिक सुख सुविधाओं वाला और विकसित हो। इंदौर में जल्द ही चौथा आईटी पार्क शुरू हो जाएगा। यह परदेसीपुरा में बने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलेक्स में 50 हजार वर्गफीट में बनाया जा रहा है। यहां कंपनियां सीधे आकर काम शुरू कर सकेंगी। सुविधाएं सरकार दे रही है।

प्रदेश में अभी स्थिति यह है कि औद्योगिक विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जो रणनीति बनाई है, उसके तहत अब हर क्षेत्र में औद्योगिक विकास किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिला स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भी शुरू कर दिया है। उद्योग को प्रोत्साहित करना मप्र सरकार का घोषित उद्देश्य है और इसके कुछ आशाजनक परिणाम भी मिले हैं। मप्र उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य से कुल निर्यात 2003-04 में लगभग 6,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 65,000 करोड़ रुपए हो गया। पीथमपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के अलावा, मप्र के इंदौर में 4 आईटी एसईजेड हैं- क्रिस्टल आईटी पार्क और तीन निजी संचालित, इन्फोसिस, टीसीएस और इम्पेटस। मप्र आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 और 2022-23 के बीच द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण, निर्माण, उपयोगिताओं का निर्माण आदि) का आकार 5.42 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद थी। सर्वेक्षण में कहा गया है, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगीकरण नितांत आवश्यक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योगों की विशेष भूमिका है। फिर भी, राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान कम है और वास्तव में पिछले दशक से इसमें गिरावट आई है। 2011-12 में उद्योग ने राज्य की जीडीपी में 27 प्रतिशत का योगदान दिया, 2021-22 में यह आंकड़ा गिरकर 19 प्रतिशत हो गया। वहीं, 2021-22 में कृषि का योगदान करीब 48 फीसदी रहा। 2011-12 और 2021-22 के बीच विनिर्माण में 6.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो इसके पड़ोसी राज्यों गुजरात (10.8 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (7.05 प्रतिशत), राजस्थान (6.97 प्रतिशत) और उप्र (6.37 प्रतिशत) से कम है। केवल महाराष्ट्र में कम वृद्धि (3.32 प्रतिशत) दर्ज की गई। जबकि सरकार अपनी उपलब्धियों में एमएसएमई विकास का हवाला देती है। राज्य सरकार के थिंक टैंक अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस (एआईजीजीपीए) द्वारा राज्य एमएसएमई विभाग के सहयोग से किए गए एक अध्ययन में इस साल कहा गया है कि राज्य के एमएसएमई को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें लिखा है, वित्त तक सीमित पहुंच एमएसएमई के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा है।

उद्योग विशेषज्ञ इस क्षेत्र में हुए लाभ को स्वीकार करते हैं लेकिन कहते हैं कि सरकार ने राज्य की क्षमता को अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त तत्परता के साथ काम नहीं किया है, साथ ही वे इन रुझानों को कृषि पर प्रशासन के निरंतर ध्यान के रूप में वर्णित करते हैं। उद्योगपतियों ने बताया कि सरकारी नीतियों से राज्य के उद्योग जगत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। हालांकि, सरकार इससे इनकार करती है। राज्य उद्योग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उसने व्यवसाय के हित में लाइसेंसिंग से लेकर भूमि अधिग्रहण तक नीतिगत ढांचे को आसान बनाने की कोशिश की है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि लाइसेंस प्रणाली से लेकर उद्योगपतियों के लिए जमीन की उपलब्धता तक, हमने पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया है। सरकार समझती है कि कृषि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में एक बड़ा हिस्सा प्रदान करती है लेकिन उद्योग रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक अन्य अधिकारी कहते हैं कि व्यापार उद्यमों को परेशानी मुक्त बनाने वाली उद्योग-अनुकूल नीति पहल के बाद पिछले दो दशकों में राज्य में औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है।

● **रजनीकांत पारे**

उद्योगों के लिए बढ़ी जमीन की डिमांड

उद्योगों के लिए आवश्यक सड़क, बिजली, पानी, और अधोसंरचना सहित सुशासन के हर पैमाने में मप्र निवेशकों के लिए पहली पसंद बन रहा है। किसी समय बीमारू के नाम से बदनाम मप्र अब विकासशील राज्य की तरफ बढ़ गया है। यहां के उद्योग मित्र माहौल का ही परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में यहां तीन लाख करोड़ के उद्योग धंधे लगे और दो लाख युवाओं को रोजगार मिला। औद्योगिक घरानों का भरोसा जीतने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को लगातार सफलता मिल रही है। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम, बिना अनुमति उद्योग की स्थापना सहित जो वादे उद्योग जगत से किए हैं, उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है। हालांकि, अब भी कुछ कमियां हैं, जैसे उद्योगों की स्थापना से जुड़े विभागों के अधिकारियों की कार्य संस्कृति में सुधार लाना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो मप्र देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां सर्वाधिक निवेश होता है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मप्र में उद्योग को विकास की अपेक्षित गुंजाइश नहीं मिल पाने में कई कारक भूमिका निभाते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) भोपाल में आर्थिक विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर बिस्वजीत पात्रा का कहना है कि मप्र की अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है जहां बुनियादी ढांचे की स्थिति अच्छी नहीं है। उद्योग उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते जहां कुछ भी नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा, मप्र सरकार ने निश्चित रूप से राज्य में उद्योगों के विस्तार की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, मप्र देश के केंद्र में है जहां से कई राज्यों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योगों पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रोफेसर अरोड़ा ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की है, लेकिन इन प्रयासों में देरी हुई है। उन्होंने कहा, मप्र के पड़ोसी राज्य इस मामले में बहुत आगे निकल गए हैं।

लोन ऐप से ब्लैकमेलिंग

मप्र में लोन ऐप से रोजाना सैकड़ों लोगों से ब्लैकमेलिंग की जा रही है। लेकिन विडंबना यह है कि ब्लैकमेलिंग के शिकार 10 फीसदी लोग भी पुलिस के पास शिकायत करने नहीं पहुंचते। इस कारण ब्लैकमेकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर मनमानी रकम वसूल लेते हैं। मप्र में ऐसे कई लोग इस तरह से ऑनलाइन लोन की ठगी का शिकार हो रहे हैं। 2023 में तो भोपाल में एक परिवार को ऑनलाइन लोन के कर्ज के चलते सामूहिक खुदकुशी तक करनी पड़ी थी। जानकारी के अनुसार मप्र में 500 से ज्यादा लोग इस तरह से ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, लेकिन 20 से 25 शिकायतें ही थाने तक पहुंचती हैं। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि पुलिस भी 10-20 हजार की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती।

साइबर लॉ विशेषज्ञ यशदीप चतुर्वेदी बताते हैं, मप्र में हर दिन तत्काल लोन देने वाली ऐप के जरिए हजारों लोन स्वीकृत होते हैं। 500 से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें लोन की राशि तत्काल जमा करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। ये लोग समाज में बदनामी के डर से लोन की राशि का 4 से 5 गुना पैसा भी किसी ओर से कर्ज लेकर जमा कर देते हैं। महज 20 से 25 शिकायत ही थाने में पहुंचती है। 2 से 10 हजार का लोन होने से पुलिस भी इन आवेदनों पर एफआईआर नहीं करती। यशदीप के अनुसार तत्काल लोन देने का पूरा नेटवर्क ऑनलाइन काम करता है। जैसे ही आप गूगल पर बिना गारंटी लोन, बिना केवायसी लोन और बिना दस्तावेज लोन जैसे की-वर्ड सर्च करते हैं, आपके मोबाइल पर मैसेज आने लगते हैं। इन्हें क्लिक करते ही व्यक्ति इन ठगों के जाल में फंसने लगता है। ये लोग खुद को लोन देने वाली कंपनी के रूप में गूगल पर रजिस्टर्ड करा लेते हैं। ऐप डाउनलोड करते ही एक प्रोफाइल खुल जाती है, जिसमें जानकारी भरते ही तुरंत लोन स्वीकृत हो जाता है। ये लोन ऐप पूरी राशि भी नहीं देते, मान लीजिए कोई आठ हजार का लोन मांगता है तो तीन हजार तक प्रोसेसिंग फीस व अन्य चार्ज काटकर उसे पांच हजार रुपए ही देते हैं, ब्याज पूरी राशि पर वसूल की जाती है।

यशदीप का कहना है कि ये ऐप ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, जिन्हें 2 से 10 हजार रुपए का तत्काल लोन चाहिए होता है। इनके पास दस्तावेज का अभाव होता है, ऐसे में ये बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड ऐसे संस्थानों से लोन नहीं ले सकते, जो गाइडलाइन के अनुसार ही लोन उपलब्ध कराते हैं। बैंक के छोटे लोन ना जमा कर पाने पर सिबिल स्कोर खराब होने वाले लोग भी इनके निशाने पर होते हैं। यशदीप के अनुसार ये ऐप भारत से संचालित ही नहीं होते, इनका नेटवर्क पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया जैसे देशों में होता है। ऐप चलाने वाले ठग भारत में किसी ठग को 5 से 10 प्रतिशत पर कमीशन पर काम दे देते हैं। यशदीप बताते हैं, बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन की राशि ग्राहक के खाते में ट्रांसफर करती है तो खाता उसी नाम से होता है। ये ऐप किसी ओर फर्म के नाम पर खाता ऑपरेट करते हैं या फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर किसी व्यक्ति के नाम पर करंट अकाउंट खोल लेते हैं। यदि पुलिस कार्रवाई होती भी है तो व्यक्ति खाता धारक को ही गिरफ्तार करती है, जबकि उसे ठगी का पता ही नहीं होता।

एडवोकेट आनंद शर्मा बताते हैं, 2022 में गूगल ने भारत के 3500 लोन ऐप को प्ले स्टोर से हटाने का फैसला लिया। नियमों को तोड़ने की वजह से गूगल ने इन्हें बैड ऐप्स बताया था। केंद्र सरकार ने भी 2020-21 में ऐसे 150 ऐप को बैन किया था। इसके बावजूद प्ले स्टोर पर अब भी एक हजार से ज्यादा तत्काल लोन देने वाले ऐप्स एक्टिव हैं। शर्मा के मुताबिक ये ऐप्स नए नाम और डोमेन के साथ फिर एक्टिव हो जाते हैं। 2020 में कोरोना महामारी के बाद इन ऐप्स ने भारत में तेजी से पैर पसारे हैं। चीन के साथ ही लोन ऐप्स कंपनियां ब्रिटेन, अफ्रीकी देशों, इंडोनेशिया समेत कई अन्य देशों में भी लोगों से फ्रॉड कर चुकी हैं।

भोपाल की बैंकर दीपा द्विवेदी ऐसे ही लोन ऐप का शिकार हो चुकी हैं। वे कहती हैं कि मैंने लोन के लिए जैसे ही ऐप की लिंक को क्लिक किया तुरंत मोबाइल का सारा डेटा कॉपी हो गया। मुझे धमकी भरे कॉल आने लगे, मैंने उन्हें कहा कि मेरे अकाउंट में तो कोई पैसा आया ही नहीं, तो वे कहने लगे कि तुम्हारे परिवार-दोस्तों को कॉल कर तुम्हें बदनाम कर देंगे। उन्होंने मेरी मम्मी, पापा, बहन यहां तक कि बॉस को भी कॉल किया था। वे किसी से कहते कि मैंने 10 हजार का लोन लिया तो किसी को 15 तो किसी को 50 हजार लोन देने की बात कहते। वे लगातार मुझे और परिवार को धमकी भरे कॉल कर रहे थे। मैंने इसकी शिकायत पुलिस और साइबर सेल में की। 2 दिन तक मोबाइल भी बंद रखा, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट थे, उन्हें कॉल कर घटना के बारे में बताया। एडवोकेट आनंद शर्मा बताते हैं, साइबर सेल 2 लाख से कम के ठगी के मामलों में कार्रवाई नहीं करता। पीड़ित व्यक्ति जब साइबर सेल जाता है तो उसे थाने में शिकायत करने के लिए कहा जाता है, थाने में भी आवेदन लेकर उसे चलता कर दिया जाता है। कार्रवाई नहीं होने से भी ठग गिरोह पुलिस गिरफ्त में नहीं आ पाते और इनका ठगी का कारोबार चलता रहता है।

● **लोकेश शर्मा**

बच्चों की गिरफ्तारी और जांच एजेंसियों के नाम पर भी साइबर ठगी

ऑनलाइन ठगी के नित नए तरीके निकाले जा रहे हैं, जिसके चलते कई लोग रोजाना इसका शिकार बन रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है। अभी कई माता-पिता को इस आशय के फोन आते हैं कि उनके बच्चों की गिरफ्तारी, बलात्कार, हत्या या नशे के मामले में हो चुकी है और फिर कोई राशि खाते में ट्रांसफर करवा ली जाती है। इसके अलावा जांच एजेंसियों का भी भय दिखाया जाता है। राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख ने इस तरह की कई समझाइश लोगों को दी है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर चूंकि सभी लोग सक्रिय रहते हैं। ऐसे में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी कई घटनाएं भी होती हैं और जाने-अनजाने में कई लोग उसके भी अपराधी बन जाते हैं। इसी तरह जिनके बच्चे विदेश में या किसी अन्य शहर में पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं उनके माता-पिता को भी साइबर जालसाजों द्वारा फर्जी कॉल किया जाता है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी या वकील बनकर बात की जाती है और कहा जाता है कि उनका बच्चा किसी बड़े केस में फंस गया है और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अगर उसे बचाना चाहते हैं तो बताई गई राशि तुरंत जमा कर दें।

...तो 30 साल में सूख जाएगी नर्मदा!

मप्र की जीवन रेखा नर्मदा सहित तमाम नदियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को फ्रीहैंड कर दिया है। मुख्यमंत्री से मिले निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है। प्रदेशभर में अवैध उत्खनन के 200 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अभियान चलाकर डंपर, पोकलेन मशीन और पनडुब्बियां जब्त की गई हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि यह कार्रवाई कितनी प्रभावी होगी। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 साल पहले अप्रैल, 2017 में नर्मदा नदी को जीवित इकाई (लिविंग एंटिटी) का दर्जा देने की बात कही थी। इस संबंध में सरकार ने 3 मई, 2017 को विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया था। इस दौरान मां नर्मदा के संरक्षण को लेकर बड़े-बड़े वादे किए गए थे, पर ये कोरे वादे ही रहे। अब नर्मदा में जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि नर्मदा का पानी अधिकतम 30 वर्ष और मिल सकता है। इसके बाद नदी बहुत हद तक सूख जाएगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अवैध माइनिंग के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है। प्रदेशभर में अवैध उत्खनन के 200 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अभियान चलाकर डंपर, पोकलेन मशीन और पनडुब्बियां जब्त की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिए गए निर्देशों के परिरपालन में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई जारी है। नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा और शहडोल सहित प्रदेश में लगभग 200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी आदि जब्त की गई है। साथ ही एक करोड़ 25 लाख रुपए का राजस्व अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद प्रदेश में नर्मदा समेत अन्य नदियों में रेत खनन में अवैध रूप से लगी मशीनों पर रोक लगने की उम्मीद जगी है।

खास बात यह है कि 7 साल पहले अप्रैल, 2017 में तत्कालीन शिवराज सरकार नर्मदा नदी को जीवित इकाई (लिविंग एंटिटी) का दर्जा देने की बात कही थी। इस संबंध में सरकार ने 3 मई, 2017 को विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया था। इस दौरान मां नर्मदा के संरक्षण को लेकर बड़े-बड़े वादे किए गए थे, पर ये कोरे वादे ही रहे। नर्मदा नदी को जीवित इकाई का कानूनी दर्जा देने का अधिकार भारत सरकार के पास है, इसलिए मप्र विधानसभा ने संकल्प पारित होने के बाद वर्ष 2017 में ही इसे कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए भारत सरकार को भेज दिया था। उसके बाद इसे सब भूल गए। नतीजा, 7 साल बाद भी नदी को जीवित इकाई का दर्जा नहीं मिल सका। कानून बनने के बाद नदी को जीवित व्यक्ति के सभी अधिकार मिलते। इसका मतलब नदी में प्रदूषण फैलाने या नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नदी के नाम से ही एफआईआर दर्ज होती। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी तैनात किए जाते या फिर किसी संस्था को अधिकार दिए जाते। सतत् मॉनीटरिंग होने से नदी में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगती, इसे प्रदूषित होने से भी बचाया जा सकता था।

सरकार हर बार नर्मदा में अवैध खनन रोकने के लिए सख्ती दिखाती है। लेकिन नर्मदा की कोख से मशीनों द्वारा खुदाई करके रेत निकाली जा रही है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में नर्मदा नदी के बाबरी घाट पर रेत खनन का ठेका नहीं दिया गया है, लेकिन यहां रेत माफिया पनडुब्बी के जरिए बहती नदी की तलहटी से रेत खनन कर रहा है। इतना ही नहीं रेत निकालने के लिए पाइपलाइन भी डाल दी गई है। अनेक कश्तियों से रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है। यहां से रोजाना सैकड़ों डंपर रेत का खनन किया जा रहा है। सरकार ने नर्मदा नदी में सीहोर जिले की रहटी तहसील में बाबरी घाट पर रेत खनन का ठेका दिया है। इसकी आड़ में सिवनी मालवा के बाबरी घाट से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण और ओवरलोडिंग पर कार्यवाही जारी है। नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगोन, हरदा एवं शहडोल सहित प्रदेश में लगभग 200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी इत्यादि जब्त की गई और 1 करोड़ 25 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह का कहना है कि संयुक्त टीम द्वारा ग्राम डिमावर तहसील भैरूदा से चार पोकलेन मशीनें, तहसील बुदनी के ग्राम सोमलवाड़ा से दो पोकलेन मशीनें रेत खनन करते हुए जब्त कर थाना भैरूदा एवं शाहगंज की अभिरक्षा में खड़े किए गए। रेत के ओवरलोड परिवहन करते हुए 17 डंपर जब्त कर थाना गोपालपुर एवं इच्छावर की अभिरक्षा में खड़े किए गए हैं। अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्ध 15 जून तक अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

● **बृजेश साहू**

पर्यावरणविदों की चेतावनी

ख्यात पर्यावरणविद डॉ. सुनील चतुर्वेदी ने चेताया और कहा कि सतपुड़ा के घने जंगल जिस तरह से कट रहे हैं और नर्मदा क्षेत्र के आसपास जिस तरह से बांधों के निर्माण हो रहे हैं, उसके चलते जीवनदायिनी नदी नर्मदा दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में भोपाल-इंदौर को नर्मदा का पानी अधिकतम 30 वर्ष और मिल सकता है। इसके बाद नदी बहुत हद तक सूख जाएगी। अतः हम आज से ही वर्षा के जल को सहेजें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। नदियां सूखकर नाले में तब्दील हो रही हैं। कुएं और बावड़ियां कम होते जा रही हैं। पोखर और तालाब भी या तो सूख चुके हैं अथवा उन पर अतिक्रमण हो गया है। ऐसे में केवल वर्षा का पानी ही अब हमारे जल का बड़ा स्रोत रह गया है। जल की कमी का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम जितना पानी जमीन से निकाल रहे हैं उतना सहेज नहीं रहे हैं। अतः यह संकट प्रकृति प्रदत्त कम और मानव प्रदत्त अधिक है।

बहुमत के साथ विकास की बात

2024 के लोकसभा चुनावों में एक दशक के लंबे अंतराल के बाद गठबंधन युग की वापसी हुई, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा अपने दम पर आधे से भी कम सीटें जीत सकी, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में वह बहुमत हासिल करने में सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बन गई है। अब यह सरकार 10 साल बाद बहुमत के साथ विकास की बात करेगी। यानी सरकार के सामने अगले 5 साल तक कई चुनौतियां आएंगी।

● राजेंद्र आगाल

अभी तक स्वच्छंद होकर शासन करने वाले नरेंद्र मोदी को तीसरी पारी में सहयोगियों के सहारे सरकार चलानी होगी। इसकी वजह यह है कि 2014 और 2019, लगातार दो चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली भाजपा की निर्भरता इस बार सहयोगियों पर होगी। ऐसे में सरकार की तस्वीर कैसी होगी, मोदी सरकार के कामकाज का क्या तरीका होगा? चुनाव नतीजों के बाद से ही इन तमाम सवालों को लेकर एक बहस सी छिड़ी हुई थी। अब मोदी कैबिनेट में विभाग बंटवारे से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने भविष्य को लेकर रोडमैप क्लीयर कर दिया है। बहुमत के साथ अब विकास की बात होगी। हालांकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे प्रमुख मंत्रालय अपने नेताओं को ही दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी गठबंधन धर्म को निभाने के लिए प्रधानमंत्री को सहयोगी पार्टियों की सलाह पर ही सरकार चलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह मोदी के लिए कठिन सफर हो सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बन गई है। चुनाव नतीजों के बाद किंगमेकर बनकर उभरी चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) और नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) की अपनी-अपनी मांगें थीं। दोनों दल मनचाहा विभाग चाह रहे थे। नायडू की पार्टी को सड़क परिवहन चाहिए था तो वहीं नीतीश की जेडीयू को रेल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने ये सभी विभाग अपने पास रखे हैं। इसे रेलवे, सड़क परिवहन में सुधार की रफ्तार धीमी नहीं पड़ने देने की भाजपा की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है तो वहीं ये संदेश भी बताया जा रहा है कि भाजपा सहयोगियों के आगे नहीं झुकेगी। भाजपा ने सहयोगी दलों को एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि गठबंधन धर्म निभाएंगे लेकिन सिर झुकाकर सरकार नहीं चलाएंगे। गौरतलब है कि रेलवे जिस किसी भी सरकार में नेतृत्व करने वाली पार्टी की जगह किसी गठबंधन सहयोगी के पास रहा है, लोकलुभावन नीतियों के चलते खस्ताहाल रहा है।

बड़े विभाग भाजपा के पास

रेल और सड़क परिवहन से लेकर शिक्षा और कानून तक, पुराने मंत्रियों को ही फिर से इन विभागों की जिम्मेदारी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि इन विभागों में शुरू हुए सुधार के काम सुस्त नहीं पड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को फिर से शिक्षा मंत्री बनाया जाना हो या अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री, ये इसी तरफ इशारा है। देश में 2024 से ही नई शिक्षा नीति लागू होनी है। वहीं, पिछली सरकार के कार्यकाल में बने नए आपराधिक कानून भी 1 जुलाई से लागू होने हैं। ऐसे में अगर किसी नए चेहरे को इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी जाती तो हो सकता था कि तय डेडलाइन पर ये कानून और शिक्षा नीति लागू करने में समस्या हो। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की इमेज कलेवर बदलते रहने वाली है। 2014 के बाद 2019 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी, तब भी ये देखने को मिला था। 2014 में गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को रक्षा और रक्षामंत्री रहीं निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। अमित शाह को कैबिनेट में शामिल कर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस बार भी माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पुराने मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त, रक्षा और गृह मंत्रालय की कौन कहे, सरकार ने दर्जनभर से अधिक पुराने मंत्रियों के विभाग बरकरार रखे हैं।

नतीजे आने के बाद से ही मनचाहे विभाग के लिए जेडीयू और टीडीपी, भाजपा पर दबाव बना रहे थे। दोनों ही पार्टियां सीसीएस से संबंधित मंत्रालय चाहती थीं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीसीएस की कौन कहे, रेल, कृषि, सड़क परिवहन, शिक्षा और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी भाजपा ने अपने ही पास रखे हैं। किंगमेकर बनकर उभरी इन पार्टियों को मुंहमांगे मंत्रालय न देकर भाजपा ने सभी गठबंधन सहयोगियों को एक तरह से यह संदेश दे दिया है कि उसके लिए गठबंधन जरूरी भले ही है, मजबूरी नहीं है। सीसीएस से जुड़े मंत्रालयों के साथ ही भाजपा ने कृषि, शिक्षा, कानून, रेलवे और सड़क परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं तो उसके भी अपने मायने हैं। किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं कृषि मंत्रालय के तहत चलती हैं तो वहीं सड़क परिवहन और रेल ऐसे मंत्रालय हैं, जिनके काम को सरकार चुनाव में सबसे ज्यादा शोकेस करती है। यही वह विभाग भी हैं जिन्हें लेकर पिछले कार्यकाल में सरकार ने सबसे ज्यादा नीतिगत फैसले लिए हैं। विभाग बंटवारे के जरिए सरकार ने एक तरह से यह संदेश भी दे दिया है कि जिन क्षेत्रों में नीतिगत फैसलों की जरूरत है, उनके लिए हम सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं रहेंगे।

समीकरण साधने की कोशिश!

केंद्र में फिर एनडीए की सरकार बन गई है। मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। तीसरी बार बनी एनडीए सरकार

अब गठबंधन की चुनौती

आम चुनाव 2024 का परिणाम आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली। मोदी ने उन्हें 400 सीटों का लक्ष्य पूरा न कर पाने के कारण हुई निराशा से उबारने की कोशिश की। हालांकि भाजपा लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और उसके गठजोड़ एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत भी है, इसलिए उसकी निराश अचंभित करने वाली है। दरअसल इस निराशा भाव के पीछे तीन कारण गिनवाए जा सकते हैं। पहला तो पार्टी का चुनावी नारा ही है- अबकी बार चार सौ पार। पार्टी 240 सीटें लाकर अपने बल पर सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत के लक्ष्य से अभी 32 सीटें पीछे है जबकि भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 400 के नारे से 106 सीटें पीछे है। अब पार्टी को यह सोचना होगा कि अपना लक्ष्य पूरा न कर पाने में उससे क्या और कहां-कहां गलतियां हुई हैं। दूसरा कारण नरेंद्र मोदी का आक्रामक और बड़बोला चुनाव प्रचार था। पार्टी के वादों को मोदी की गारंटी कहकर प्रचारित किया गया। सारे पोस्टरों और प्रचार सामग्री पर मोदी की ही तस्वीर थी। पूरे प्रचार का वही एक चेहरा थे। उन्होंने भीषण गर्मी में 210 से ज्यादा रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कीं। कुल प्रचार अभियान इस एक शख्स पर टिका हुआ था, इसलिए दावेदारी और विश्वसनीयता का कुल दारोमदार भी उन्हीं के कंधों पर आकर टिक जाता है। लोगों से कहा गया कि पार्टी या उसके घोषणापत्र या फिर अगले पांच साल के लिए उसके एजेंडे के बजाय ब्रांड मोदी के नाम पर वोट करें। अगर वाकई एनडीए 400 सीटें पार कर गया होता तो यह अकेले नरेंद्र मोदी के लिए चमकदार गौरव का क्षण होता, जो मामूली पृष्ठभूमि से उठकर प्रधानमंत्री के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं। पार्टी मुख्यालय में छाई मुर्दनी इसी बात से है कि एनडीए 400 सीटें पार नहीं कर सका यानी दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी की निजी अपील एनडीए को उस लक्ष्य तक पहुंचाने में नाकाम रह गई।

पुराने 20 मंत्रियों का कटा पत्ता

मोदी कैबिनेट में इस बार 71 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। इनमें ज्यादातर नए चेहरों को शामिल किया गया है। वहीं, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जिन 20 नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिली थी, उनको बाहर कर दिया गया है। इसमें चुनाव जीतने वाले अनुराग ठाकुर, नारायण राणे और अजय भट्ट का नाम शामिल है। वहीं चुनाव हारने वाले स्मृति ईरानी, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, साध्वी निरंजन, राजीव चंद्रशेखर, अजय मिश्र टेनी, निशीथ प्रमाणिक, सुभाष सरकार, भारती पंवार, राव साहेब दानवे और कपिल पाटिल को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। जबकि अश्विनी चौबे, मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वीके सिंह और जॉन बारला का इस बार टिकट काट दिया गया था।

में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 71 मंत्री हैं। इनमें से 60 मंत्री भाजपा से और 11 मंत्री एनडीए की बाकी पार्टियों से हैं। मोदी 3.0 में 37 नए चेहरों को मौका दिया गया है। जबकि, 34 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। नई सरकार में बड़े मंत्रालय भी भाजपा ने अपने पास ही रखे हैं। नई मोदी सरकार में सबसे ज्यादा 10 मंत्री उप्र से बनाए गए हैं, जबकि 8 मंत्री बिहार से हैं। कुल मिलाकर 24 अलग-अलग राज्यों से चुनकर आए सांसदों को मंत्री बनाया गया है। अगर मंत्रियों देखा जाए तो पता चलता है कि भाजपा की नजर अगले कुछ महीनों में होने वाले छह राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी है और मंत्रिमंडल के गठन को इसकी तैयारी माना जा सकता है।

महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल इस साल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। अक्टूबर-नवंबर में यहां की 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। हरियाणा में 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक रहेगा। महाराष्ट्र के साथ ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। झारखंड में यहां की विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है। इस साल के आखिरी में झारखंड में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। उधर, 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में अगले साल फरवरी में चुनाव प्रस्तावित हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। बिहार में विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। इससे पहले अक्टूबर और नवंबर 2025 में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। जम्मू-कश्मीर में 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे। जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर भी अगले साल तक चुनाव कराए जा सकते हैं।

बिहार में आठ सांसद मंत्री बने हैं। इनमें चिराग पासवान (एलजेपीआर), गिरिराज सिंह (भाजपा), जीतनराम मांझी (एचएएम), रामनाथ ठाकुर (जेडीयू), ललन सिंह (जेडीयू), नित्यानंद राय (भाजपा), राज भूषण चौधरी (भाजपा) और सतीश दुबे (भाजपा) शामिल हैं। इस दौरान कास्ट फैक्टर का भी ध्यान रखा गया है। तीन ऊंची जातियों (गिरिराज सिंह, सतीश दुबे और ललन सिंह), तीन ओबीसी (नित्यानंद राय, राजभूषण चौधरी और रामनाथ ठाकुर) और दो एससी (चिराग पासवान और जीतनराम मांझी) को मंत्री बनाया गया है। राजभूषण चौधरी मल्लाह समुदाय से आते हैं और निषाद बहुल सीट मुजफ्फरपुर से सांसद हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर अब भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के समुदाय के बड़े नेता हैं।

लोकसभा चुनाव में एनडीए महाराष्ट्र में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जैसी उसे उम्मीद थी। मोदी 3.0 में महाराष्ट्र से 6 मंत्री बनाए गए हैं। चार भाजपा और एक-एक शिवसेना (शिंदे गुट) और आरपीआई से मंत्री बना है। भाजपा ने एक राज्य मंत्री का पद अजित पवार की एनसीपी को भी ऑफर किया था, जिसे उसने ठुकरा दिया। महाराष्ट्र के कोटे से मोदी कैबिनेट में रक्षा खडसे को भी शामिल किया गया है। रक्षा खडसे एक युवा और ओबीसी चेहरा हैं, जिन्हें खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है।

90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के लिए इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। हरियाणा से तीन सांसदों को मंत्री बनाया गया है। करनाल से जीतकर आए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को शहरी आवास मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कृष्ण पाल गुर्जर को राज्यमंत्री बनाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर ओबीसी चेहरा हैं। हरियाणा में इस बार भाजपा 5 लोकसभा सीटें ही जीत सकी है।

झारखंड से इस बार दो मंत्री बने हैं और दोनों ही भाजपा से हैं। अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है, जबकि संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ, दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। अन्नपूर्णा देवी जहां यादव समुदाय से हैं, वहीं संजय सेठ वैश्य समुदाय से हैं। दिल्ली और जम्मू-कश्मीर दोनों ही विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली में अगले साल फरवरी तक तो जम्मू-कश्मीर में भी कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दोनों ही प्रदेशों से एक-एक मंत्री बनाए गए हैं। दिल्ली से पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा को सड़क-परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री बनाया गया है। वहीं, जम्मू की उधमपुर सीट से लगातार तीसरी बार जीते जितेंद्र सिंह को भी राज्यमंत्री का पद दिया गया है। हर्ष मल्होत्रा पंजाबी हैं और दिल्ली में पंजाबियों की अच्छी-खासी आबादी है। वहीं, जितेंद्र सिंह डोगरा राजपूत हैं और जम्मू की सियासत में डोगरा राजपूतों का ठीकठाक समीकरण बैठता है। महाराष्ट्र और बिहार में एनडीए की सरकार है। महाराष्ट्र सरकार में भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार) शामिल है। वहीं, बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और भाजपा गठबंधन में है। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। जबकि, जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे।

सरकार के सामने समस्याएं

नरेंद्र मोदी को जब 7 जून को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया था, तो उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी एनडीए सरकार थी, अब भी एनडीए सरकार बन रही है। पहले भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अब भी वही प्रधानमंत्री बन रहे हैं, फिर हम हारे कैसे और वे जीते कैसे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस और इंडी एलायंस के घटक दल अपनी जीत का

जश्न मना रहे थे, राहुल गांधी जब कांग्रेस कार्यालय में मीडिया के सामने आए तो मुस्कराते हुए उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप सोच रहे होंगे कि यह कमाल हमने किया कैसे। खुशी का इससे बढ़िया इजहार कुछ और नहीं हो सकता था।

राहुल गांधी के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि पिछला चुनाव हारने के बाद झेंप मिटाने के लिए उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस और इंडी एलायंस के बाकी घटक दलों को इस बात का अफसोस नहीं है कि संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण जैसे नेरेटिव गढ़ने के बावजूद वे मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी अब बेलगाम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।

पहली बार उन्हें 9 सहयोगी दलों के 5 कैबिनेट और 6 राज्यमंत्री बनाने पड़े हैं। 30 सदस्यीय कैबिनेट में पहली बार पांच कैबिनेट मंत्री एचडी कुमारस्वामी, जीतनराम मांझी, ललन सिंह, राममोहन नायडू और चिराग पासवान गैर भाजपा दलों से हैं, इसके अलावा जयंत चौधरी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए हैं। यही अंतर है पहले की एनडीए सरकार में और अब बनी एनडीए सरकार में, जो मोदी को समझ में तो आ रहा है, लेकिन वह भी झेंप मिटाने के लिए बोल नहीं रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो खैर 2018 में मोदी का साथ छोड़ गए थे, लेकिन पिछले पांच सालों में एक साल छोड़कर नीतीश कुमार तो मोदी के साथ एनडीए सरकार में ही थे, उन्हें पूरा अनुभव है किस तरह 17 सांसद जीतने के बाद भी घटक दलों से बात कर रहे अमित शाह ने उन्हें एक कैबिनेट और एक राज्यमंत्री पद देने से इनकार कर दिया था। कैसे नरेंद्र मोदी ने बिना उनकी सहमति लिए मनमाने ढंग से जेडीयू अध्यक्ष आरपी सिंह को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। अब मोदी ऐसा नहीं कर सकते, अलबत्ता इस बार तो जेडीयू के 12 सांसद जीते हैं, लेकिन मोदी को एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री बनाना पड़ा। मोदी के घोर विरोधी रहे ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को राज्यमंत्री बनाया गया है। इसी तरह 16 लोकसभा सीटें जीतने वाले तेलुगू देशम के भी दो मंत्री बनाने पड़े, येरानायडू के बेटे राम मोहन नायडू कैबिनेट मंत्री और चंद्र शेखर पम्मासानी राज्य मंत्री बनाए गए हैं।

नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की ओर से मनाए जा रहे जीत के जश्न की यह कहकर खिल्ली उड़ाई थी कि जो पिछले तीन चुनावों में जीते अपने सांसद जोड़कर भी हमारी इस बार की परफॉर्मेंस के बराबर नहीं पहुंचे, वे खुद को जीता हुआ बता रहे हैं। कांग्रेस 2014 में 44, 2019 में 52 और 2024 में 99 सीटें जीती है, जो कुल मिलाकर 195 बनती हैं, जबकि भाजपा इस बार भी 240 सीटें जीती है। नतीजों को देखने का अपना-अपना नजरिया होता है, 63 सीटें घटने के बाद मोदी को यह कहने का हक है कि फिर भी हम जीते हैं। लेकिन राहुल गांधी को खुशी इस बात की भी है कि 10 साल बाद कम से कम कांग्रेस को लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा तो मिलेगा। स्वाभाविक है कि यह खुशी होनी भी चाहिए कि 2014 और 2019 को मिलाकर कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलीं थीं, जितनी इस बार मिली हैं। इंडी एलायंस के लिए खुशी की बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटें बढ़ी हैं और उद्धव ठाकरे भी 9 सीटें जीतने में कामयाब रहे।

विपक्ष की खुशी जायज है, क्योंकि 10 साल बाद पहली बार मोदी अंदरूनी और बाहरी दबावों को झेलते हुए सरकार चलाएंगे। बाहर से विपक्ष इतना मजबूत होगा कि सरकार को संसद में हर बिल पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और सरकार के भीतर से घटक दलों के इतने दबाव होंगे कि मोदी भाजपा के एजेंडे को लागू नहीं कर पाएंगे। ऐसे पांच मुद्दों की शिनाख्त अभी की जा सकती है, जिन पर सरकार के भीतर मोदी दबाव में होंगे।

सबसे पहला मुद्दा है नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए मुस्लिम कोटा, जिसे धार्मिक आधार पर दिया गया आरक्षण बताकर मोदी ने चुनावों में विरोध किया था, आंध्र प्रदेश में चार प्रतिशत मुस्लिम कोटा लागू है, जिसे चंद्रबाबू नायडू ने ही अपनी पिछली सरकार के समय लागू किया था, और इस चुनाव में उन्होंने वायदा किया है कि मुस्लिम आरक्षण लागू रहेगा। वह ऐसा कोई कानून नहीं बनाने देंगे, जिससे मुस्लिम आरक्षण कोटे में कोई बाधा आए। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार भी उनके साथ होंगे।

दूसरा मुद्दा है समान नागरिक संहिता। भाजपा के तीन मुख्य मुद्दों में से एक यही

चुनाव नतीजों का दिख सकता है बजट पर असर

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी सरकार बनने के बाद पेश किए जाने वाले बजट 2024-25 में चुनावी नतीजों का असर दिख सकता है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तीसरी बार जब उनकी सरकार चुनकर आएगी, तो प्राथमिकता अर्थव्यवस्था पर होगी। लेकिन अब जिस तरह चुनाव के परिणाम आए हैं, उसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चुनाव में जाने पर पहले इंडिया गठबंधन ने सौगातों की बौछार करते हुए देश की जनता से तमाम बड़े वादे किए थे और उदाहरण के तौर पर इनमें महिलाओं को सालाना एक लाख रुपए देने का वादा भी किया गया था। लेकिन इस तरह के वादों का असर भी चुनाव नतीजों पर देखने को मिला और इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। ऐसे में अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भी बजट में इसी से मिली-जुली घोषणाएं कर सकती हैं। हालांकि इकोनॉमी की रफ्तार को लेकर सरकार अपने कदम पीछे खींचने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और चुनाव नतीजों के बाद देश को संबोधित करते हुए उनके भाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जिक्र भी शामिल रहा। हालांकि, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार के पूर्ण बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए मोदी सरकार कुछ नए और बड़े ऐलान कर सकती है। हालांकि, कांग्रेस के घोषणापत्र में जो ऐलान किए गए थे, तो मोदी सरकार भी पहले से ही गरीबों और महिलाओं के लिए कुछ खास योजनाएं संचालित कर रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शामिल है, जिसके तहत देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

मुद्दा बचा था, जिसे मोदी ने अब तक लागू नहीं किया था, यह मुद्दा उन्होंने अपनी तीसरी टर्म के लिए छोड़ रखा था, क्योंकि यह मुद्दा भी मुस्लिमों और ईसाईयों से जुड़ा है, इसलिए इस बार की एनडीए सरकार में इसे लागू करना असंभव होगा। इसी तरह एनआरसी का भी मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चाहेंगे कि एनआरसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। चुनावों में अमित शाह ने एक नहीं अनेक बार कहा था कि एनआरसी देशभर में लागू किया जाएगा और जल्द ही लागू किया जाएगा।

बाकी दो विषय हैं अग्निवीर और डिलिमिटेशन। जेडीयू के महासचिव और नीतीश कुमार के अत्यंत करीबी केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार करने की मांग रख दी है, इसका मतलब है कि चुनाव नतीजों पर उसके असर को देखते हुए जैसे पिछली बार मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, उसी तरह अग्निवीर योजना या तो वापस लेनी पड़ेगी या उसमें इतना बदलाव किया जाएगा कि वह स्वीकार्य हो सके। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है डिलिमिटेशन, 1973 में अगले 50 सालों के लिए लोकसभा की सीटें सील कर दी गईं थी, यानि यह तय हो गया था कि देश की आबादी भले ही कितनी भी बढ़े अगले 50 साल तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी। पिछले 50 सालों में देश की आबादी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। अब अगला लोकसभा चुनाव डिलिमिटेशन के बाद होगा। पिछली मोदी सरकार ने नया संसद भवन बनाकर और महिला वंदन बिल पास करवाकर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत बढ़ी हुई सीटें आरक्षित कर दी थीं। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा की 33 प्रतिशत सीटें बढ़ेंगी, जिन पर महिलाएं ही चुनी जाएंगी।

18वीं लोकसभा का जनादेश वाकई ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी के शब्दों में तो पहली बार 60 साल में तीसरी बार सरकार कायम रहने का इतिहास बना, लेकिन वे भूल गए कि आजाद भारत में तीसरी बार किसी पार्टी को नहीं, गठबंधन को बहुमत मिला और उनके विशाल बहुमत पाने के लक्ष्य धराशायी हो गए। बड़ा इतिहास इस मायने में बना कि 90 के दशक के बाद गठबंधन सरकारों का दौर एक दशक के अंतराल के बाद फिर लौट आया। 2014 और 2019 की तरह किसी एक को बहुमत हासिल नहीं हुआ। इससे भी बड़ा इतिहास यह है कि यह जनादेश खारिज करने का ज्यादा है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह तीसरी बार अपनी पार्टी को बहुमत दिलाने का मोदी का सपना भी खारिज हो गया। सबसे बढ़कर देश के बड़े हिस्से ने संविधान बदलने की आशंकाओं को खारिज किया। उन नीतियों को खारिज किया, जो बेरोजगारी, महंगाई, गैर-बराबरी, सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र में बदलने, श्रम कानूनों, कृषि के कॉर्पोरेटीकरण को विकास का मानक मानती हैं। खारिज करने का यह सिलसिला अलग-अलग हिस्सों में दूसरी राजनीतिक पार्टियों के हिस्से भी आया, लेकिन उस किस्से से पहले यह देखना महत्वपूर्ण है कि नीतियों के मामले में इस जनादेश का खारिज अभियान कितना व्यापक है। जैसे, महामारी के आपदाकाल में आए तीन केंद्रीय कृषि कानून किसान आंदोलन की वजह से खारिज हुए थे, उसी दौर में आई सेना में अग्निवीर योजना को मौजूदा जनादेश खारिज करता दिखता है। गौरतलब है कि विपक्ष प्रचार के दौरान अग्निवीर योजना को कूड़ेदान के हवाले करने का वादा कर रहा था तो पंजाब में आखिरी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम सेना को आधुनिक बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा- मैं विरोध करने वालों की सात पीढ़ियों की करतूतें खोलकर रख दूंगा।

गठबंधन की मौजूदा स्थिति

कम से कम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उप्र में यह और सरकारी भर्ती-परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र लीक का मुद्दा नौजवानों के गुस्से का कारण बना हुआ लगता है। इसी तरह पुरानी पेंशन नीति पर भी लोगों की मुहर लगती और नई पेंशन नीति की पैरोकारी खारिज होती दिखी। दरअसल गौर करें तो 90 के दशक में शुरू हुईं उदारीकरण और बाजारवादी नीतियों को उसके बाद हुए हर चुनाव में खारिज करने का ही जनादेश मिला है। 1996 में पीवी नरसिंह राव की सरकार आखिरी वर्षों में आर्थिक सुधार का मानवीय चेहरा पेश करने के बावजूद हार गई। फिर 2004 में इंडिया शाइनिंग का दावा करने वाली एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हार गई। 2009 में आर्थिक सुधारों के उलट मनरेगा और किसान कर्जमाफी ही यूपीए को जिता पाई। इसी तरह 2014 तथा 2019 में भी मुद्दे आम आदमी को आर्थिक राहत देने या राष्ट्रवाद के थे। 2024 में निजीकरण, विकसित भारत और 50 खरब की अर्थव्यवस्था का सपना खारिज होता दिखा है। यानी जनादेश उन नीतियों को खारिज करता दिखता है जो बेरोजगारी, महंगाई, गैर-बराबरी, सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र में बदलने, श्रम कानूनों में बदलाव, कृषि के कॉर्पोरेटीकरण को विकास का मानक मानती हैं। इसका असर राजनीतिक पार्टियों के दूसरे मुद्दों के मद में भी दिखा। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा असर नहीं दिखा पाया और भाजपा हार गई। इसी तरह बनारस को आधुनिक विकास का रूप देने की पहल भी खारिज हुई और नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर घटकर महज 1.5 लाख के करीब आ गया। राजनीतिक जोड़तोड़ से सियासत हथियाने की कोशिश खारिज करने की मिसाल महाराष्ट्र बना, जहां भाजपा इकाई अंक में सिमट गई। दूसरी ओर भारी विकास और कल्याण योजनाओं का दम भरने वाली ओडिशा में नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकारें भी खारिज कर दी गईं। कांग्रेस भी तेलंगाना और कर्नाटक में अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के बल पर केंद्र की सियासत के लिए लोगों को पर्याप्त भरोसा नहीं दिला पाई। यह जरूर है कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा मगर वह इतना नहीं हुआ कि पार्टी को सीटों पर एकतरफा जीत दिला देता। तेलंगाना में कांग्रेस को कुल 17 सीटों में से 8 से ही संतोष करना पड़ा और आठ सीटें पाकर भाजपा ने अपनी 2019 की संख्या को दोगुना कर लिया। कर्नाटक में वह दहाई का अंक नहीं छू पाई और कुल 28 में से 9 सीटों से संतोष करना पड़ा। बाकी 18 सीटें भाजपा और दो जनता दल-सेक्युलर को मिल गईं। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में चार सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत करने में तो कामयाब हुई, मगर केंद्रीय सियासत के लिए लोगों को अपनी नीतियों से भरोसा नहीं दिला सकी और चारों संसदीय सीटें हार गई। हरियाणा में भी तमाम किसान और नौजवान नाराजगी के बावजूद वह 10 में से आधी सीटें ही जीत पाई। उधर, बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन ने अभियान तो बहुत आक्रामक चलाया, मगर उसे ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया।

मोहन की निगरानी में सिंहस्थ की तैयारी

बारह बरस में एक बार होने वाले महाकाल के दरबार के बड़े आयोजन सिंहस्थ की तैयारियां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद संभालेंगे। इसके लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाई जाएगी। इन तैयारियों के बीच नमामी क्षिप्रा प्रोजेक्ट भी जल्दी ही शुरू किया जाएगा। चूंकि, डॉ. मोहन उज्जैन से ही हैं, इस वजह से महाकाल लोक से लेकर सिंहस्थ कामों तक में उनकी गहरी रूचि और अहम भूमिका रही है। इसी के चलते उन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथों में रखने का निर्णय लिया है। सिंहस्थ को लेकर अभी तक कार्ययोजना में 18 हजार 840 करोड़ की लागत से 523 कार्य प्रस्तावित किए जा चुके हैं, इनमें अधिकतर स्थायी प्रवृत्ति के कार्य हैं, जिनका लाभ सिंहस्थ के बाद भी मिलेगा। प्रशासन सिंहस्थ-2028 में 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का आंकलन कर रहा है। यह आंकड़ा सिंहस्थ-16 से लगभग दोगुना है। सिहंस्थ महाकुंभ 27 मार्च से शुरू होगा। सिंहस्थ में 27 मई तक तीन शाही स्नान होंगे।

राज्य सरकार ने चार साल बाद यानी वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियां तेज कर दी हैं। वर्ष 2028 में ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। सिंहस्थ का आयोजन मार्च से मई के बीच होगा और उसके करीब छह महीने बाद यानी नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। सरकार नहीं चाहती कि जिस तरह 2016 में सिंहस्थ में निर्माण कार्यों और खरीदी में गड़बड़ी के आरोपों से सरकार की बदनामी हुई थी, वैसी ही किसी प्रकार की अनियमितता सिंहस्थ-2028 के आयोजन में हो और चुनाव से पूर्व विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल जाए। यही वजह है कि पूर्व की तरह इस बार किसी मंत्री विशेष को सिंहस्थ के आयोजन की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंहस्थ के आयोजन की मुख्य कमान अपने हाथ में रखेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल्द ही मंत्रियों की एक कमेटी गठित की जाएगी। उधर, वरिष्ठ अधिकारियों की टीम उप्र पहुंचकर 28 मई से प्रयागराज कुंभ-2025 की तैयारियों का अवलोकन करेगी।

सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर उज्जैन में होने वाले बड़े विकास कार्यों के लिए जुलाई में पेश होने वाले मप्र सरकार के बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा, ताकि इन कार्यों में बजट के अभाव में किसी तरह की रुकावट नहीं आए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल, वर्ष 2016 के उज्जैन सिंहस्थ का प्रभार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्कालीन गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह को सौंपा था। सिंहस्थ के समापन के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सिंहस्थ के निर्माण कार्यों और खरीदी में हुए फर्जीवाड़े को जोर-शोर से विधानसभा में उठाया था। कांग्रेस ने सदन में तथ्य प्रस्तुत करते हुए कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप सरकार पर लगाए थे। इससे सरकार की किरकिरी हुई थी। विधानसभा चुनाव 2018 तक कांग्रेस ने इस मद्दे को गरमाए रखा। इसके बाद उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण कार्यों में हुई अनियमितता के आरोपों से सरकार की बदनामी हुई थी। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन से आते हैं और वे महाकाल के भक्त हैं। वे नहीं चाहते कि सिंहस्थ के आयोजन में कोई कमी रह जाए या फिर आयोजन के बाद किसी तरह की अनियमितता के आरोप सरकार पर लगें, इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं सिंहस्थ का आयोजन देखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को अलग-अलग संभागों का प्रभारी बनाया है। उज्जैन संभाग का प्रभार तेजतर्रार अधिकारी अपर मुख्य सचिव जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा को सौंपा गया है। उन्हें उज्जैन संभाग का प्रभार सौंपने की मुख्य वजह सिंहस्थ का आयोजन है। डॉ. राजौरा लगातार उज्जैन का दौरा कर संभाग के अफसरों के साथ सिंहस्थ की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वे मुख्यमंत्री को समय-समय पर सिंहस्थ की तैयारियों से अवगत कराते रहते हैं।

मप्र सरकार सिंहस्थ अधिनियम-1955 में बदलाव करने जा रही है। इसमें 17 की जगह 40 धाराएं होंगी। इसके तहत सिंहस्थ मेला क्षेत्र में भूमि प्रबंधन, आवंटन, मेला शुल्क, सुरक्षा, आवागमन से लेकर सभी सुविधाएं दी जाती हैं। अधिनियम में बदलाव की सबसे बड़ी वजह सिंहस्थ के स्वरूप में पिछले 70 सालों में बदलाव को माना जा रहा है। प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ का आयोजन होता है, इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु क्षिप्रा में स्नान कर दर्शन पूजन करते हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

भीड़ प्रबंधन पर विशेष जोर

भीड़ में खासी वृद्धि हो चुकी है। पहले जहां लाखों श्रद्धालु आते थे, वहीं अब करोड़ों श्रद्धालु इस सिंहस्थ के आयोजन में भाग लेते हैं। आधुनिक यातायात व्यवस्था, संचार, चिकित्सा और स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार हुआ है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थाई अस्पताल, पुलिस नियंत्रण कक्ष और स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं। सिंहस्थ का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। जिससे देश-विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी व्यापक रूप से फैलाई जाती है। मप्र के गठन से पहले सिंहस्थ को सकुशल कराने मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम-1955 बना था। इतने सालों से इसी अधिनियम के आधार पर मेले का संचालन हो रहा है। उस वक्त सिंहस्थ मेले में कम संख्या में श्रद्धालु आते थे। समय के अनुसार, अधिनियम में साइकिल, तांगा से लेकर बर्फ के गोले की बिक्री आदि पर मेला शुल्क लगाया जाता था। अब यह पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुका है, लेकिन शुल्क के जरिए प्रबंधन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। सरकार चाहती है कि इस अधिनियम में बदलाव कर मौजूदा समय के हिसाब से प्रबंधन हो। सरकार के मुताबिक, अभी मेला क्षेत्र करीब 3 हजार हेक्टेयर का है। पिछली बार इसमें से करीब 23 फीसदी क्षेत्र खाली रह गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि वर्ष 2040 तक में यह क्षेत्र भर जाएगा। मेला क्षेत्र में आने वाले वाहनों, दुकानों आदि से एक निश्चित शुल्क लिया जाएगा। अभी अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। इस सुझाव के आधार पर एक्ट तैयार कर उसे संभवतः दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में पारित कराया जाएगा।

अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता...

भारतीय संस्कृति में यह कहावत काफी प्रचलित है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। लेकिन कई बार लोग अकेले दम पर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर इंडी गठबंधन को धूल चटाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वे पूरी तरह असफल हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए जो बातें कही थीं, मौजूदा चुनाव नतीजों का उन बातों से सीधा ताल्लुक है। इंडी एलायंस को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी अकेला सब पर भारी है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि भाजपा अकेले 370 सीटें जीतेगी और एनडीए की सीटें चार सौ पार होंगी। उनके ये तीनों ही डायलॉग उन पर भारी पड़ गए। देश की जनता ने जवाब दिया कि उसे एक अकेला सब पर भारी वाला तानाशाह नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। लोकतंत्र में जब-जब कोई एक सब पर भारी पड़ा है, जनता ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। यही भारत के लोकतंत्र की खासियत है, जो किसी को तानाशाह बनने से रोक देती है।

मोदी ने पिछले दस सालों में लाख अच्छे काम किए होंगे, लेकिन उनकी तानाशाह बनने की प्रवृति लोगों को पसंद नहीं आई। 370 तो बहुत दूर की बात है, भाजपा को 270 के भी लाले पड़ गए हैं। हालत यह है कि चुनावों के आखिरी दिनों में एनडीए में लौटे तेलुगू देशम और जेडीयू के कारण ही भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में आई है। भाजपा को यह डर था कि ये दोनों बिदक गए तो एनडीए की नहीं, इंडी एलायंस की सरकार बन सकती है। ओपिनियन पोल और एक्जिट पोल के दावों के विपरीत भारतीय जनता पार्टी की 64 सीटें कम होने को पांच कारणों से परिभाषित किया जा सकता है।

2014 और 2019 में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने समझ लिया था कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बन चुकी है। 1989 से लेकर 2014 तक चली गठबंधन की राजनीति का अंत हो गया है। इसलिए गठबंधन के सहयोगियों से विचार विमर्श बिलकुल बंद हो गया था। प्रधानमंत्री ने उनकी उपेक्षा शुरू कर दी थी। पहले 2018 में तेलुगू देशम छोड़कर गई थी, फिर 2019 के बाद चार बड़े क्षेत्रीय दल शिवसेना, जेडीयू, अकाली दल और अन्ना द्रमुक छोड़कर गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को याद रखना चाहिए था कि 2004 में जब द्रमुक जैसे बड़े घटक दल एनडीए छोड़कर गए थे, तो भाजपा को हिंदी पट्टी में भी नुकसान हो गया था। ये दल एनडीए को छोड़कर जा रहे थे, तो उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई। भाजपा ने जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना कबूल कर लिया, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत थी।

एनडीए के संयोजक भी नीतीश कुमार या किसी अन्य सहयोगी दल के नेता को बनाने के बजाय खुद अमित शाह बन गए। ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एनडीए को खत्म करने का मन बना लिया है, क्योंकि 2019 के बाद एनडीए की बैठक ही नहीं बुलाई गई। एक बैठक बुलाई भी गई, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें प्रवचन दिया गया। शिवसेना, जेडीयू को कमजोर करने की नरेंद्र मोदी की रणनीति को भांपते हुए ही इन दोनों दलों ने एनडीए छोड़ा था। नरेंद्र मोदी को एनडीए की याद तब आई, जब जून 2023 में इंडी एलायंस बन रहा था। यह अलग बात है कि अपने-अपने प्रदेशों की स्थानीय राजनीति के चलते तेलुगू देशम और जेडीयू एनडीए में वापस आ गए। आज चुनाव नतीजे देखते हैं तो साफ है कि इन्हीं दोनों दलों के भरोसे एनडीए सरकार बनने की स्थिति बनी है। लेकिन इनका साथ कब तक टिका रहेगा, यह बहुत कुछ मोदी और अमित शाह के व्यवहार पर निर्भर करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विकास के मुद्दे के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, उसे वह ज्यादा देर बरकरार नहीं रख सके। पहले दौर की कम वोटिंग से घबराकर उन्होंने हिंदू-मुस्लिम करना शुरू कर दिया। जिसके जवाब में इंडी एलायंस के नेताओं ने रणनीति बनाई, तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वह हिंदू-मुस्लिम करके ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू कर रहे हैं,

संघ को भी नहीं लिया साथ

संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि राम मंदिर के मामले में भाजपा ने संघ की बात सुननी बंद कर दी थी। शुरुआत चंपत राय पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप से हुई थी। संघ ने चंपत राय को चित्रकूट की प्रतिनिधि सभा में बुलाया और सख्त चेतावनी भी दी। इसके बाद भाजपा ने राम मंदिर का मसला सीधा अपने हाथ में ले लिया। संघ की सलाह पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया। नृपेंद्र मिश्र 2014 और 2019 में पीएमओ के सबसे खास अधिकारी थे। राम मंदिर आंदोलन के वक्त जब कारसेवकों पर गोलियां चली थीं, तब नृपेंद्र मिश्र उप्र सरकार में प्रमुख सचिव थे। नृपेंद्र मिश्र को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया जाना, संघ के कई पदाधिकारियों को पसंद नहीं आया। संघ ने इस पर भाजपा से बात भी की, लेकिन भाजपा ने फैसला नहीं बदला। ये संघ और भाजपा के बीच खाई बनने की सबसे पहली ठोस वजह थी।

मोदी की नीतियों से संघ की नाराजगी

मोदी सरकार के नारे से संघ 2014 से ही नाराज है। ये नारा संघ की आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठता। संघ व्यक्ति को नहीं, संगठन या समूह को तरजीह देता है। मोदी सरकार के नारे से एक व्यक्ति सर्वोपरि दिखाई देता है। भाजपा लंबे वनवास के बाद सत्ता में लौटती दिख रही थी, इसलिए संघ इस पर खामोश रहा। अब इस पर चर्चा हो रही है कि क्या चुनाव में मोदी को सर्वोपरि मानना बड़ी गलती थी। चुनाव में उप्र ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। इस झटके को संघ ने टिकट बंटवारे के वक्त ही भांप लिया था। संघ ने 10 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट पर असहमति जताई थी। इनमें प्रतापगढ़, श्रावस्ती, कौशांबी, रायबरेली और कानपुर जैसी सीटें शामिल थीं। कानपुर के अलावा सभी सीटों पर भाजपा कैंडिडेट की हार हुई है। संघ का कहना था कि कुछ सांसदों को छोड़कर, हमें नए लोगों को टिकट देना चाहिए, जैसा दिल्ली में किया है। हालांकि, टिकट बंटवारे के मामले में भी संघ बेबस ही दिखा। संदेशखाली के मुद्दे पर भाजपा ने संघ को भरोसे में नहीं लिया। संघ ने पहले ही बता दिया था कि आंदोलन के अंदर ही कई धड़े हैं। आंदोलन के अंदर दरार है। इस पर भाजपा को भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें यहां नेशनल और कल्चरल सिक्योरिटी के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए, जैसे उप्र के विधानसभा चुनाव में किया था। ओडिशा में संघ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यहां की जीत पर भाजपा को भ्रम नहीं पालना चाहिए। ओडिशा के लोग नवीन पटनायक की बीमारी और ब्यूरोक्रेसी के हाथों में सत्ता जाने से नाराज थे। उनके सामने कांग्रेस का विकल्प नहीं था, सामने सिर्फ भाजपा थी। अगर कांग्रेस दम लगाती, तो नतीजा ऐसा नहीं होता।

तो हमें भी संविधान और आरक्षण की बात करनी चाहिए, जिस पर इंडी एलायंस में सहमति बनी और फ्रंट फुट पर खेल रहे मोदी और अमित शाह बैकफुट पर आ गए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की इस रणनीति से हिंदुत्व की राजनीति तार-तार हो गई, और जिस जातिवाद को तोड़कर 2014 और 2019 में भाजपा जीती थी, उस पर जातिवाद की राजनीति हावी हो गई। मोदी और अमित शाह को सफाई देनी पड़ी कि वे न तो संविधान बदलेंगे, न आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन दलितों और ओबीसी को डराने के लिए संघ और भाजपा नेताओं के पुराने बयान भुनाए गए, जिनमें आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही थी। इस प्रचार का दलित समुदाय पर खासकर असर हुआ और उप्र, राजस्थान और हरियाणा में बसपा का सारा वोटबैंक इंडी एलायंस की तरफ शिफ्ट हो गया। भाजपा को मायावती को कमजोर करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उप्र में अब दलित वोटबैंक का नया भाजपा विरोधी मसीहा पैदा हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की सामूहिक नेतृत्व वाली पुरानी नीति को किनारे करके सारी पार्टी को दब्बू बना दिया था। प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेशों के महामंत्री ही नहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति भी दिल्ली से होने लगी थी। यहां तक कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोई फैसला बिना अमित शाह और प्रधानमंत्री की सलाह लिए नहीं कर रहे थे। संसदीय बोर्ड भी पंगु बनकर रह गया था। सारी परंपराओं को तोड़कर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। पिछले पांच सालों से पार्टी के भीतर नियुक्तियों पर सारा नियंत्रण मोदी और शाह के हाथ में था। पहले संगठन पर संघ से भेजे गए संगठन महामंत्रियों की पकड़ रहती थी, लेकिन जबसे अमित शाह पार्टी अध्यक्ष बने तब से न सिर्फ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, बल्कि राज्यों के संगठन महामंत्री भी किनारे कर दिए गए। जनसंघ और भाजपा के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने संघ में वापस जाने की इच्छा जाहिर की और संघ ने उन्हें वापस बुला लिया। अन्यथा संगठन महामंत्रियों को लग्जरी लाईफ का चस्का लग जाता है और वापस जाने का नाम तक नहीं लेते।

हाल के चुनावों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न जाने किसके कहने पर यह कह दिया कि पार्टी आत्मनिर्भर हो गई है। संघ इससे खफा हुआ और संगठन महामंत्रियों को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। कर्नाटक के संगठन महामंत्री को वापस बुलाने से इसकी शुरुआत हो गई है। यह क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि संघ ने इस बार के चुनाव में मन से काम नहीं किया, क्योंकि संघ में व्यक्ति पूजा नहीं होती, जबकि नरेंद्र मोदी ने पिछले दस सालों में अपना कद संघ और भाजपा से बड़ा बनाकर पेश किया, जब उन्होंने मोदी की गारंटियां बांटनी शुरू की, तो उसे संघ में ठीक नहीं माना गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के क्षत्रप येदियुरप्पा, महाराष्ट्र के क्षत्रप देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान की क्षत्रप वसुंधरा राजे, मप्र के क्षत्रप शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा में जातीय समीकरणों के चलते क्षत्रप बन चुके मनोहर लाल खट्टर को उनके राज्यों की राजनीति से दूर करने का खामियाजा भी भुगता है। मप्र को छोड़कर इन सभी राज्यों में भाजपा को कांग्रेस के हाथों मार खानी पड़ी है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर उद्धव ठाकरे से उनके पिता की विरासत छीनने में भाजपा पूरी तरह नाकाम रही। शरद पवार की पार्टी तोड़ने का फैसला भी गलत साबित हुआ, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सहानुभूति का लाभ मिला और उसका फायदा कांग्रेस को हुआ।

भाजपा नेतृत्व को यह बड़ी गलतफहमी हो गई है कि वह अब काडर बेस पार्टी नहीं रही, मास बेस पार्टी बन गई है। इसलिए काडर की कोई जरूरत नहीं रही। 370 खत्म होने और राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बावजूद भाजपा काडर अपने नेता से खफा था। इसका बड़ा कारण यह था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पार्टी संगठन पर हावी होने के बाद संगठन और विचारधारा से जुड़े नेताओं को किनारे करके बाहरी लोगों को भारी तादाद में टिकट दिए गए, खासकर ब्यूरोक्रेट्स और अन्य पार्टियों से आए दलबदलुओं को नेता बनाकर संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ताओं से उनके लिए काम करने को कहा गया। जिस काडर ने पीढ़ी दर पीढ़ी विचारधारा के लिए काम करते हुए भाजपा को इस स्थिति तक पहुंचाया था, उन्हें बिलकुल किनारे कर दिया गया था। इस बार ऐसे अनेक कार्यकर्ता और नेता घर बैठ गए। भाजपा को इसका भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।

● **विपिन कंधारी**

देश में सात चरण में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा चार चरण तक मजबूत स्थिति में रही। इसी दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया कि शुरुआत में हम कम सक्षम थे। तब हमें संघ की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं। आज भाजपा खुद अपने आप को चलाती है। ये बयान अचानक नहीं था। उस खींचतान का नतीजा था, जो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच 3-4 साल से चल रही है। तो क्या संघ चुनाव में भाजपा के साथ नहीं था? जवाब में संघ के प्रांतीय स्तर के एक पदाधिकारी कहते हैं कि भाजपा चुनाव में संघ आइडियोलॉजी के साथ नहीं थी। और संघ किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ आइडियोलॉजी के साथ होता है। भाजपा पीछे हटी, संघ नहीं।

भाजपा-संघ के बीच की दूरियां

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा रिश्तों की जिस सच्चाई पर अब तक केवल चर्चाएं हो रही थीं, वो अब स्पष्ट है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा कि पार्टी अब आरएसएस से स्वतंत्र हो गई है और उसे अब किसी मददगार की जरूरत नहीं है। यह रहास्योद्घटन किसी ऐसे वैसे नहीं, खुद भाजपा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने किया है। जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो यह है कि यह 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों के ठीक बीच में आया है। इस वक्तव्य में उलझन में डालने वाली बात यह है कि यह आरएसएस की सावधानीपूर्वक विकसित और अंतरनिहित की गई उस रणनीति को तोड़ता है जिसके तहत सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई भी बात न कहें या करें जो एक संघ परिवार के संगठनात्मक मोनोलिथ के मेहनत से बनाए गए मुखौटे को नुकसान पहुंचा सके। ऐसा मुखौटा जो उसके विरोधियों को लगातार भयभीत रखता हो। तो, हम नड्डा के इस खुलासे को क्या समझें?

कोई गलती न करें, एक तरह से भाजपा द्वारा आरएसएस से अपनी आजादी की एक घोषणा है। यहां इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है क्योंकि इसे खुद नड्डा ने इतने सीधे शब्दों में कहा है। और यह कोई अनायास टिप्पणी नहीं थी जिसे नड्डा ने इसकी गंभीरता को समझे बिना मूर्खतापूर्ण ढंग से कह दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा स्पष्ट रूप से उचित समय पर इस मुद्दे को उठाना चाह रही थी और कुछ समय से भाजपा के शीर्ष नेताओं के भीतर जो भावना थी, उसे व्यक्त करने के लिए नड्डा ने एक इंटरव्यू का इस्तेमाल लिया। नड्डा का खुलासा, इस भ्रम को खत्म कर देता है कि आरएसएस और भाजपा पूरी तरह से एक-दूसरे के साथ हैं और दोनों के लिए एक-दूसरे से परेशानी जैसी कोई बात नहीं है।

वहीं, कई विश्लेषकों का मानना है कि आरएसएस को भाजपा और मोदी से शिकायत या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी ने आरएसएस के मूल एजेंडे को पूरी तरह से लागू कर दिया है। किसी को यहां आरएसएस की मूलभूत विचार प्रक्रिया में गहराई से उतरने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आरएसएस अपने वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों से खुश है, लेकिन निश्चित रूप से यही सबकुछ नहीं है। आरएसएस अपने एजेंडे को लागू होते देखना चाहता है, लेकिन अपने संगठनात्मक कामकाज के बारे में अपनी मूलभूत विचार प्रक्रिया की कीमत पर नहीं। उस विचार प्रक्रिया के केंद्र में एक अटल सिद्धांत है कि संगठन को सर्वोच्च शासन करना चाहिए (संगठन सर्वोपरी है) और किसी भी व्यक्ति या किसी विभूति पूजा द्वारा अवरूद्ध नहीं होना चाहिए। भाजपा से आरएसएस की वर्तमान अस्वस्थता का कारण भी मोदी शासन के तहत पिछले दस सालों में पूरे संघ परिवार के साथ हुआ ठीक यही व्यवहार है।

मोदी किसी को भी खुश रखने के लिए कुछ भी करने में विश्वास नहीं करते, जब तक कि उन्हें एक प्रभावशाली स्थिति में बनाए रखने के लिए इसकी सख्त जरूरत न हो। पिछले दस साल में हमने जो स्पष्ट रूप से देखा है वो यह है कि मोदी संघ परिवार के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन गए हैं और हर चीज उनके इर्द-गिर्द घूम रही है। यह कुछ ऐसा है जो आरएसएस के मूलभूत

मोदी के लिए इसकी अघोषित चुनौती है

अगर आपको लगता है कि आपको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो जाइए और अपने दम पर जीतिए। इस चुनाव में आरएसएस की ओर से उत्साह की कमी का कारण अलगाव की भावना के अलावा और कुछ नहीं हो सकता और यह इस बेहद महत्वपूर्ण चुनाव से आरएसएस की दूरी है जो चुनावी मौसम के ठीक बीच में आरएसएस से आजादी की नड्?ा की संक्षिप्त घोषणा के पीछे हो सकती है। नड्डा यह भी कहते हैं कि आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है जबकि यह मूल संगठन है और भाजपा इसका राजनीतिक मोर्चा है। क्या नड्डा ने जानबूझकर आरएसएस के लिए मोर्चा शब्द का इस्तेमाल किया या भाषाई कौशल की अपर्याप्तता के कारण यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह संघ परिवार के भीतर आरएसएस के व्यापक महत्व को कम करता है। तो, आरएसएस और भाजपा के बीच यह दूरियां किस ओर जा रही हैं? चुनाव के नतीजे आने के बाद यह साबित हो चुका है। मोदी अकेले बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, उन्हें एनडीए की मदद से सरकार बनानी पड़ी।

सिद्धांत के खिलाफ है कि कोई भी संगठन से ऊपर नहीं है, यहां तक कि आरएसएस प्रमुख भी नहीं। आरएसएस ने अपनी स्थापना के बाद से ही किसी भी व्यक्ति को अधिनायकवाद को दूर रखने के लिए भगवा ध्वज को गुरू मानने पर जोर दिया है। संगठन में ही शक्ति है, यह निर्विवाद है और इसलिए इस पर कोई आंच नहीं आने दी जाती है। मोदी ने अपने विशिष्ट अधिनायकवादी अंदाज में उस सिद्धांत का उल्लंघन किया है और यही आरएसएस की उनके प्रति बेचैनी का कारण है।

आरएसएस के इस मूल आधार में एक विडंबना है, जबकि आरएसएस सैद्धांतिक रूप से, लेकिन चतुराई से इस परोपकारी तानाशाह के विचार को बढ़ावा देता है, यह संघ परिवार संगठन के भीतर किसी भी व्यक्ति को यह भूमिका निभाने के लिए तैयार होने नहीं दे सकता है। आरएसएस का मानना है कि जिस क्षण संगठन किसी व्यक्ति के अधीन हो जाता है, यह उसके लिए लौकिक मौत की घंटी साबित हो सकता है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन संगठन रहना चाहिए। यह अपने इस अस्तित्व की चिंता है जिसने आरएसएस को पूरे संघ परिवार की तुलना में नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से अलग कर दिया है। इसके साथ ही मोदी की भाजपा कई आरएसएस कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ-साथ पार्टी संगठन के भीतर भी महत्वपूर्ण पदों और महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए आकर्षित कर रही है। इसने संगठन के प्रति नि:स्वार्थता के उस मूल्य को काफी हद तक भ्रष्ट कर दिया है जिसे आरएसएस बचपन से ही अपने कार्यकर्ताओं के भीतर विकसित करता आया है। इसीलिए आरएसएस इस चुनाव में जाहिर तौर पर खुद को भाजपा से अलग रख रहा है।

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन बनाना था। इस मसले पर संघ ने भाजपा से सीधे बात की थी। उसका मानना था कि राम मंदिर राजनीतिक आंदोलन नहीं है। इस पर राजनीति से बचना चाहिए। ये हिंदुत्व का मुद्दा है। लोगों की आस्था है। अगर जनता को लगा कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है, तो वो भाजपा से दूर हो जाएगी। संघ की इस सलाह को भी नहीं माना गया। इसका असर ये हुआ कि भाजपा अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाई। संघ की तरफ से कहा गया था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चुनाव के ठीक बाद हो। मशविरा दिया गया था कि मंदिर का काम तो चल ही रहा है, अगर प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई, तो लोग चुनाव आते-आते इस मुद्दे को भूल जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा बाद में हुई, तो लोग मंदिर का मुद्दा याद रखेंगे। चुनाव के दौरान उनके दिमाग में ये बना रहेगा। राम मंदिर बनने की आशा को बचाए रखना था, ये तभी होता जब प्राण प्रतिष्ठा चुनाव के बाद होती, लेकिन भाजपा को जल्दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई धर्मगुरु भी भाजपा के फैसले के विरोध में आ गए। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मामले में भी संघ, भाजपा से बहुत नाराज था। संघ चाहता था कि सभी शंकराचार्य और धर्मगुरु आयोजन में शामिल हों। उन्हें तवज्जो दी जाए। भाजपा ने हड़बड़ी में किसी को मनाने की जरूरत नहीं समझी, जो नाराज थे, उन्हें नाराज ही रहने दिया। भाजपा ने अपने गेस्ट बुलाए, जो ग्लैमर और बिजनेस की दुनिया से थे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई बॉलीवुड स्टार्स को ऑफिशियल निमंत्रण दिया गया। संघ चाहता था कि इस आयोजन में ग्लैमर का तड़का न लगे। जिन्हें आना है, वे खुद आएं, जैसे आम लोग आते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पवित्र मौका बनाया जाए, लेकिन ये मौका पवित्र की जगह ग्लैमरस ज्यादा दिखा। संघ इस आयोजन में उन लोगों को बुलाना चाहता था, जिन्होंने राममंदिर से जुड़ा कोई संकल्प लिया हो। कई लोगों ने शपथ ली थी कि मंदिर बनने तक चप्पल और पगड़ी नहीं पहनेंगे। अयोध्या के आसपास कुछ राजपूत कम्युनिटी हैं, जिन्होंने मंदिर बनने तक पगड़ी न पहनने का संकल्प लिया था। संघ की लिस्ट में शामिल इन लोगों को तरजीह नहीं दी गई। भाजपा ने लालकृष्ण आडवाणी की सेहत का हवाला देकर उन्हें आयोजन से दूर रहने की सलाह दी थी, जबकि आडवाणी प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहते थे। संघ के सूत्रों का कहना है कि कोई कैसे राम मंदिर बनने में आडवाणी जी की भूमिका भूल सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि इस अहम मौके की लाइमलाइट कोई और ले। हालांकि, विश्व हिंदू परिषद के विरोध और संघ के कड़े तेवर के बाद आडवाणी को निमंत्रण भेजा गया।

संघ लगातार ये बात भाजपा तक पहुंचा रहा था कि चुनाव में ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल न करें। इससे एक तबका विपक्ष को विक्टिम मान रहा है। भाजपा की छवि प्रताड़ित करने वाले तानाशाह की बन रही है। विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा। ग्राउंड पर कार्यकर्ता इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वे डिफेंसिव हो रहे हैं। भाजपा ने इस चेतावनी को भी इग्नोर किया। संघ ने भाजपा की वाशिंग मशीन वाली छवि पर भी चेतावनी दी थी। पार्टी ऐसे नेताओं को शामिल कर रही थी, जिन पर करप्शन के आरोप थे। संघ ने बताया था कि ग्राउंड पर ये मुद्दा भाजपा को नुकसान पहुंचा रहा है। विपक्ष की छवि विक्टिम की बन रही है। राहुल गांधी लगातार भाजपा के सताए नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। हालांकि, एक बार फिर भाजपा अड़ी रही। संघ की सलाह ठंडे बस्ते में डाल दी गई। संघ का कहना था कि मुफ्त के खेल में विपक्ष हमसे बहुत आगे है। इसलिए हमें मुफ्त में राशन देना बंद करना चाहिए। भाजपा की पॉलिसी के हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए।

● इन्द्र कुमार

प्रधानमंत्री मोदी के शासन में आरएसएस से दूरियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को दूर रखते हुए हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाया है। उन्होंने किसी को भी अपना कमांडर नहीं बनने दिया, यहां तक कि आरएसएस को भी नहीं। रिश्ते के बीच तनाव इतना स्पष्ट था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रधानमंत्री रहते हुए अपने दस साल के शासन के दौरान, मोदी द्वारा आरएसएस से सलाह लेने के शायद ही कोई उदाहरण हों। आरएसएस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जब भी आरएसएस के दूत सरकार को कुछ बताना चाहते थे तो वे व्यक्तिगत रूप से उनसे बात नहीं करते थे। मोदी उस तरह की विनम्रता वाले आखिरी व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने जाते। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और उनके उत्तराधिकारी एमएस गोलवलकर की नागपुर स्थित समाधियों-स्मारकों पर न जाना और उन्हें प्रधानमंत्री बनने में मदद करने के लिए आरएसएस का ऋणी होने की भावना व्यक्त न करना इस संगठन के प्रति उनकी उदासीनता का प्रमाण है।

ब्याज पर पैसा खर्च कर रहे हैं देश

दशकों से भारत एक ऐसा देश रहा है जहां लोग कमाई का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर रख लेते हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में शुद्ध घरेलू बचत 47 साल के निचले स्तर पर है। किसी परिवार के कुल धन और निवेश में से उसका कर्ज और उधारी अगर घटा दी जाए तो उसे शुद्ध घरेलू बचत कहते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में बचत घटकर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5.3 प्रतिशत हो गई है जो साल 2022 में 7.3 प्रतिशत थी। इस गिरावट को अर्थशास्त्रियों ने बहुत चिंताजनक बताया है। इसी अवधि में घरेलू कर्ज के मामले में तेज उछाल आया है। सालाना कर्ज, जीडीपी का 5.8 प्रतिशत हो गया है, जो 1970 के बाद दूसरा उच्चतम स्तर है। जैसे-जैसे लोग घर चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, उनकी बचत कम होती जा रही है। ज्यादा उधारी के मामलों में परिवार के सामने मुश्किल यह है कि उन्हें कमाई का एक हिस्सा उस उधारी और उसके कर्ज को चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में परिवार के पास बचत के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं।

सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को 2030 तक पूरा करने में मुश्किल से 6 साल बचे हैं। इस बीच दुनियाभर के देश अभूतपूर्व कर्ज तले दब गए हैं। कर्ज का भुगतान कई देशों का एक प्रमुख व्यय है। यह उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर पर्याप्त खर्च का अवसर नहीं दे रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के अनुसार, वैश्विक ऋण (परिवारों, व्यवसायों और सरकारों के ऋण सहित) 2024 में 315 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तीन गुना है। वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम के अध्यक्ष बोरगे ब्रेंडे इस बोझ को समझाते हुए कहते हैं, आज दुनिया में हम जैसे लगभग 8.1 बिलियन लोग रहते हैं। अगर हम उस ऋण को व्यक्ति के हिसाब से विभाजित करें, तो हम में से प्रत्येक पर लगभग 39,000 डॉलर का ऋण होगा। ऋण या उधार लेना व्यक्तिगत, संस्थागत और राष्ट्रीय व्यय को वित्तपोषित करने का एक स्थापित तरीका है। लेकिन अब यह असहनीय स्तर पर पहुंच गया है जहां उधारकर्ता राजस्व का अधिकांश हिस्सा उधारी चुकाने के लिए ब्याज के रूप में देता है। कुल वैश्विक ऋण में घरेलू ऋण 59.1 ट्रिलियन डॉलर, व्यावसायिक ऋण 164.5 ट्रिलियन डॉलर और सार्वजनिक ऋण (सरकारों का उधार) 91.4 ट्रिलियन डॉलर है। बहुत से लोग इस ऋण की तुलना लगभग दो शताब्दियों पहले नेपोलियन युद्धों के दौरान लिए गए ऋण से करते हैं।

बढ़ता सार्वजनिक ऋण चिंताजनक है जिसके लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सख्त चेतावनी की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकास क्षेत्रों पर सार्वजनिक खर्च को इसके द्वारा रोका जा रहा है। 5 जून को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने एक नई मूल्यांकन रिपोर्ट 'ए वर्ल्ड ऑफ डेब्ट 2024 : ए ग्रोइंग बर्डन टु ग्लोबल प्रोस्पेरिटी' में कहा है कि सार्वजनिक ऋण का स्तर न केवल ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, बल्कि विकासशील और गरीब देशों में विकास पर होने वाले खर्च को भी खतरे में डाल रहा है।

क्यों बढ़ रहा है कर्ज?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ काम करने वाले अर्थशास्त्री निखिल गुप्ता का कहना है कि भारत के बढ़ते घरेलू कर्ज का एक बड़ा हिस्सा नॉन मॉर्गेज लोन है। इनमें से आधे से ज्यादा कर्ज कृषि और बिजनेस से जुड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2022 में भारत नॉन मॉर्गेज लोन के मामले में ऑस्ट्रेलिया और जापान के बराबर आ गया और उसने अमेरिका और चीन सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया। गुप्ता का कहना है कि क्रेडिट कार्ड, शादी और हेल्थ इमरजेंसी के लिए कर्ज, कुल घरेलू कर्ज का 20 प्रतिशत से कम है, लेकिन यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट था। तो कम बचत और ज्यादा कर्ज की यह स्थिति हमें दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताती है? अर्थशास्त्री गुप्ता कहते हैं कि उपभोक्ताओं को कुछ हद तक विश्वास है। ऐसे कई भारतीय हैं जिन्हें उम्मीद है कि भविष्य में वे ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। या फिर वे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचने के बजाय वर्तमान में एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। गुप्ता कहते हैं, हो सकता है कि ज्यादा खर्च करने को लेकर भारतीयों की मानसिकता बदली हो, लेकिन यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है?

वैश्विक सार्वजनिक ऋण (सरकारों द्वारा घरेलू और बाहरी ऋण दोनों) में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। 2023 में यह 97 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, जो 2022 की तुलना में 5.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है। विकासशील देशों की कुल वैश्विक ऋण में हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है। इन देशों की ऋण वृद्धि दर विकसित देशों की तुलना में दोगुनी है। ऋण तब जोखिम बन जाता है जब उसे लेने वाले देश के पास ऋण चुकाने की क्षमता नहीं होती। ऐसी स्थिति में देश को विकास कार्यक्रमों के लिए बजट में कटौती करते हुए सिर्फ ऋण चुकाने के लिए धन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिन देशों के पास ऋण चुकाने की सबसे कम क्षमता है, वही सबसे कर्जदार देश भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकलन में कहा गया है कि 2023 में विकासशील देशों ने ब्याज-भुगतान में 847 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो 2021 की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। इन देशों के लिए ब्याज दर भी अमेरिका की ब्याज दर से चार गुना अधिक है।

यह ऋण देशों के खातों में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में जहां ऋण तेजी से बढ़ रहा है, वहां 60 प्रतिशत से अधिक ऋण-जीडीपी अनुपात वाले देशों की संख्या 2013-2023 के दौरान 6 से बढ़कर 27 हो गई है। लगभग 27 अफ्रीकी देश केवल ऋण के ब्याज भुगतान के लिए सरकारी निधि का 10 प्रतिशत खर्च करते हैं। विकास व्यय पर इसका प्रभाव स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र के आंकलन में कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 3.3 बिलियन लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां ऋण के ब्याज का भुगतान शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च से अधिक है। अफ्रीका में ब्याज पर प्रति व्यक्ति खर्च 70 अमेरिकी डॉलर है, जो शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च 60 अमेरिकी डॉलर और स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च 39 अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

● **टीपी सिंह**

महाराष्ट्र में होगा खेला

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल होने वाला है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेज रहीं। नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए भाजपा ने अजित पवार गुट की एनसीपी को भी ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। अजित गुट के प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री का ऑफर था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इसे ठुकरा दिया कि वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और ये उनका डिमोशन होगा।

सत्ताधारी शिंदे सेना ने दावा किया कि उद्धव सेना के दो नवनिर्वाचित सांसदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वे एनडीए और शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं। दूसरी ओर, अजित पवार की एनसीपी के कई लोगों के शरद पवार के संपर्क में होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि अजित पवार के लोगों ने यही दावा शरद पवार की पार्टी के लोगों के लिए किया। उद्धव ठाकरे के भी एनडीए को समर्थन देने की चर्चाएं चलीं। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दावा किया गया कि शिंदे गुट के 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में तीन से चार महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे अनुमानों के विपरीत आए। उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार मजबूती से उभरे, जबकि अजित पवार और भाजपा को भारी नुकसान हुआ। केंद्र में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे में भाजपा की नजर उद्धव सेना पर है। बताया जा रहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उद्धव सेना के नेताओं से संपर्क किया है, परंतु उन्हें राज्य में देवेंद्र फडणवीस को लेकर एलर्जी है। इधर, फडणवीस ने जिस तरह हार का ठीकरा खुद पर लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है, उससे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में व्यापक घटनाक्रम के अनुमान लगाए जाने लगे हैं।

दिल्ली के महाराष्ट्र भवन में शिंदे सेना के प्रवक्ता नरेश म्हस्के ने दावा किया कि उद्धव सेना के दो नवनिर्वाचित सांसदों ने एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वह शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं क्योंकि वे अपने चुनाव क्षेत्र का विकास चाहते हैं। साथ ही जिस तरह से एक तबके ने फतवा निकालकर उद्धव का फेवर किया, उससे वे सांसद भी नाराज हैं। पिछले दिनों अजित पवार ने पार्टी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिसमें पांच विधायक और मंत्री नहीं आए। अब उनकी पार्टी के नेता व कैबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने दावा किया कि शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल हमारे साथ आ सकते हैं, जबकि जयंत ने दावा किया कि अजित गुट के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। सेंटर में भाजपा को गठबंधन की सरकार चलानी होगी। ऐसे में चर्चा है कि एनडीए में वापसी के लिए भाजपा के नेता उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में उद्धव ठाकरे को वापस एनडीए में लाने पर चर्चा हुई। ऐसे में भाजपा के सामने एकनाथ शिंदे को मनाना बड़ी चुनौती होगी।

लोकसभा चुनाव में एनसीपी (अजित गुट) के नेता अजित पवार ने चाचा शरद पवार की तारीफ की है। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने कहा, मैं पिछले 24 वर्षों से पार्टी का नेतृत्व करने के लिए शरद पवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इसकी स्थापना के बाद से इसके साथ बने हुए हैं। बता दें कि शरद पवार ने साल 1999 में पार्टी की स्थापना की थी। मुंबई में एक पार्टी समारोह को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट पद से किसी भी पद पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमने भाजपा को स्पष्ट कर दिया है कि हम कैबिनेट पोर्टफोलियो से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें अपने कई घटकों को कैबिनेट पद देने की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने कहा कि हम अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं और आने वाली महीनों में एनडीए का आंकड़ा 293 से बढ़कर 300 पार हो जाएगा।

मुंबई में एक पार्टी समारोह को संबोधित करते हुए, अजित पवार ने नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट पद से कम किसी भी पद पर समझौता नहीं करने के राकांपा के रुख की पुष्टि की। उन्होंने कहा, हमने भाजपा को स्पष्ट कर दिया है कि हम कैबिनेट पोर्टफोलियो से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें अपने कई घटकों को कैबिनेट पद देने की जरूरत है। अजित पवार के इस बयान से भाजपा से उनकी दूरी और चाचा शरद पवार की निकटता दिखाई दे रही है। ऐसे में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीति में बड़ी फेरबदल हो सकती है। हालांकि मोदी की नई कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज अजित पवार का कहना है कि हम अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं।

● **बिन्दु माथुर**

अजित पवार के बदले बोल

इस बीच लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अजित पवार के बोल बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल, एनसीपी के 25 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने शरद पवार की जमकर तारीफ की। अजित पवार ने कहा कि शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठाया था और अलग होकर नई पार्टी बनाई थी। उस वक्त से ही वे पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे संगठन को दिशा देने का काम कर रहे हैं। जून 2023 में शरद पवार से अलग होने के बाद से ऐसा पहली बार देखा गया कि, जब अजित पवार ने उनकी तारीफ की हो। अजित पवार की ओर से ऐसे वक्त में अपने चाचा शरद पवार की तारीफ करने से कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। वो भी तब जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में उनके गुट को केवल एक लोकसभा सीट मिली है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में कुछ दिन पहले खबर आई थी कि महाराष्ट्र में अजित पवार के एनसीपी गुट के करीब 10-15 विधायक शरद पवार खेमे के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले इस तरह की खबर से राजनीतिक हलचल तेज है। दरअसल, किसी पार्टी का नाम लिए बिना एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा था कि कई नेता उनके संपर्क में हैं।

ओवर कॉन्फिडेंस में रही भाजपा

लोकसभा चुनावों के परिणामों में राजस्थान ने राजनीतिक समीकरणों की पुरानी घिसी-पिटी परिभाषा को बदलकर रख दिया है। साथ ही कई मिथकों को भी तोड़ दिया है। भविष्य के लिए इन नतीजों में काफी कुछ छुपा है। कांग्रेस गठबंधन खुश है- क्योंकि 25 में से 11 सीटें जीती हैं। इससे भी बढ़कर इसलिए कि देश में भी इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की हैं। भाजपा में भारी चिंता हैं, क्योंकि सबसे सुरक्षित राजस्थान से 11 सीटें उसने गंवा दी हैं। देश में भी सीटें कम हुई हैं। पिछली 2 बार से भाजपा को यहां पूरी सीटें मिलती आ रही थीं। 2019 में तो कांग्रेस की सरकार के बावजूद भाजपा सभी 25 सीटें जीत गई थी।

राजस्थान में चुनाव की शुरुआत से ही भाजपा के नेता से लेकर कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। राजस्थान को भाजपा का गढ़ होने का मिथक पाल लिया। स्थानीय मुद्दे बजाय राष्ट्रीय मुद्दों के भरोसे रहे। यहां की जातिगत खांटी राजनीति को समझकर सुलझाने वाला कोई नेता नहीं था। इससे परंपरागत राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए। 1 मार्च को भाजपा की लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची आने के साथ जाट-राजपूत विवाद की जातिगत कहानी शुरू हो गई। लगातार चुनाव जीत रहे चूरू सांसद राहुल कस्वां का टिकट काटना भाजपा के लिए कोढ़ में खाज बना। इसके बाद अलग-अलग इलाकों में पूरा चुनाव जाति केंद्रित हो गया। इस बात को समझकर डैमेज कंट्रोल करने वाला नेता भी पार्टी में नहीं था। बल्कि जीत के अति विश्वास में इस आग को और भड़का दिया। इस कारण कई सीटें भी हारे। जाट-राजपूत विवाद न सिर्फ चूरू बल्कि पूरे राजस्थान में फैल गया। उधर, किरोड़ी मीणा को कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिलने से अपमान का मुद्दा भी पूर्वी राजस्थान में हावी रहा।

राजस्थान में पूरे चुनाव का नेतृत्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने किया। इनके अलावा कोई नेता प्रदेश में सक्रिय नहीं था। भजनलाल का भी पूरे प्रदेश का राजनीतिक कुल जमा अनुभव पांच महीने का है। वे पहली बार के विधायक हैं और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री। कैबिनेट में कोई ऐसा मंत्री नहीं है, जिसकी प्रदेश स्तर पर पहचान हो। भाजपा के ज्यादातर नेता अपने इलाकों में फंसे थे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी खुद चुनाव लड़ रहे थे तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपने इलाके में फंसे थे। वहां भी हार का मुंह देखना पड़ा। पहले दो चुनावों में ऐसा नहीं था। मोदी लहर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा की लीडरशिप में चुनाव लड़े गए थे। इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरी तरह साइड लाइन थीं। झालावाड़ के अलावा वे कहीं सक्रिय नजर नहीं आईं। भाजपा में अनुभवी नेतृत्व की कमी बड़े हार का कारण बनी। इसके उलट कांग्रेस ने तमाम मतभेदों को ग्राउंड पर हावी नहीं होने दिया और मिलकर चुनाव लड़ा। सर्वसम्मति नहीं होने के बावजूद गठबंधन को तीन सीटें दीं और तीनों जीतीं।

भाजपा चुनाव में कैंडिटेट को लेकर कोई प्रयोग नहीं कर पाई थी, जबकि कांग्रेस ने सभी 22 चेहरे बदल दिए। तीन सीटें गठबंधन उम्मीदवारों को दीं। भाजपा के चेहरे बदलने के प्रयोग उल्टे साबित हुए। कोई गठबंधन नहीं किया। ज्यादातर प्रत्याशी रिपीट किए। भाजपा के कैंडिटेंट के प्रति एंटीइन्कम्बेंसी तो थी ही उनके पास खुद का विजन और काम भी नहीं था। वे पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी और धर्म के सहारे ही थे। पार्टी ने भी पूरी तरह मोदी फॉर्मूला लागू किया था। विधानसभा में हाल ही में जीते मप्र और छत्तीसगढ़ में मतदाताओं ने इस फॉमूले को स्वीकार कर लिया, लेकिन राजस्थान में अलग तेवर अपनाते हुए रद्द कर दिया। यहां विकास और प्रत्याशी के लिए उसने कांग्रेस और निर्दलीय को मौका दिया।

राजस्थान में भाजपा की चुनावी हार का एक बड़ा कारण यह भी है कि जातिगत समीकरणों के आगे पार्टी की रणनीति पिछड़ गई। इधर, जातिगत ध्रुवीकरण का सीधा और भरपूर फायदा कांग्रेस को मिला। लगभग हर सीट पर वोट बैंक जातियों में बंटा दिखाई दे रहा था। दौसा, चूरू, बाड़मेर, सीकर, भरतपुर, दौसा-सवाईमाधोपुर जैसी सीटों पर चुनाव जातियों में बंट गया। ऐसे माहौल में भाजपा की रणनीति और तैयारी फीकी पड़ गई। राजपूत वोट बैंक ने इस बार पूरे उत्साह से चुनाव में हिस्सेदारी नहीं निभाई। भाजपा नेताओं से नाराजगी के कारण राजपूत वोट बैंक वोट डालने नहीं निकले। भाजपा के लिए ये बड़ा डेंट रहा। कांग्रेस ने गठबंधन कर सीटें दूसरे दलों के लिए छोड़ीं, जिससे कांग्रेस को खुद की सीटों पर फायदा पहुंचा। गुर्जरों, मीणा, यादवों में भी नाराजगी थी, जो भाजपा भांप नहीं पाई और कई इलाकों में इसका नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है, लेकिन अभी उनके बदलने की संभावना नहीं है। क्योंकि भजनलाल को अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने काम संभालने के बाद कुछ ही समय में पेपर लीक माफिया पर सख्त एक्शन लिया और बुलडोजर मॉडल को भी लागू किया। आचार संहिता के बाद उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे राज्य को जिताने की जिम्मेदारी उनकी और प्रदेशाध्यक्ष की होती है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

कमबैक करने की तैयारी में वसुंधरा राजे

मोदी कैबिनेट में राजस्थान के चार सांसदों को जगह मिली है। भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भागीरथ चौधरी को मंत्री बनाया है। पहले अटकलें लगाई जा रहीं थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को मंत्री बनाया जाएगा। दुष्यंत झालावाड़-बारां संसदीय क्षेत्र से लगातार पांचवीं बार सांसद बने हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दुष्यंत सिंह की तुलना में गजेंद्र सिंह शेखावत को तवज्जो दी है। सियासी जानकार इसके अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर भजनलाल शर्मा हटाए जा सकते है। वसुंधरा राजे की वापसी हो सकती है। शायद यहीं वजह है कि वसुंधरा राजे के बेटे को मंत्री नहीं बनाया है। वसुंधरा राजे कैंप के नेता फिलहाल खामोश हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने भाजपा से 11 सीटें छीन ली हैं। भाजपा को सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि वरिष्ठ विधायकों को जगह मिल सकती है।

अयोध्या में हार हर कोई हैरान

लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट घोषित होने के बाद उप्र में सबसे ज्यादा चर्चा फैजाबाद (अयोध्या) सीट की हो रही है। यहां से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को 54 हजार वोटों से शिकस्त दी है। इसको लेकर सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों ने एक पुण्य काम के लिए गरीबों के आशियाने को नष्ट कर दिया, इसलिए अयोध्या और आसपास के इलाकों के लोगों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया।

अयोध्या में भाजपा की हार से हर कोई हैरान है। यहां 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और चार महीने पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। बावजूद इसके भाजपा के हिंदुत्व की प्रयोगशाला अयोध्या में धराशाई हो गई। अखिलेश यादव के दलित चेहरे ने भाजपा के धुरंधर ठाकुर चेहरे को हराकर दिखा दिया कि अयोध्या पर कमंडल नहीं मंडल भारी है। क्या ये जातीय समीकरणों का चमत्कार है या फिर लोगों को कम मुआवजे का विकास रास नहीं आया! फैजाबाद सीट की हार ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और भाजपा से लेकर संघ परिवार तक सभी को सदमे में डाल दिया है। देश ही नहीं दुनियाभर में अगर भाजपा की किसी एक सीट के हारने की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी है तो वह है अयोध्या। वही अयोध्या जो भाजपा के हिंदुत्व के विचारधारा के मूल में है, जिस अयोध्या में 22 जनवरी को नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देशभर में 2024 के चुनाव का आगाज हुआ, भाजपा वही अयोध्या हार गई।

पिछले 40 सालों से जिस अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन की बदौलत भाजपा ने अपनी पूरी पार्टी खड़ी कर ली, भाजपा वह अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कुछ महीनों के भीतर ही हार गई। अभी हार के कारण तलाशे जा रहे हैं, कोई इसे भाजपा के ओबीसी और दलितों के छिटकने की हार बता रहा है, कोई अखिलेश के सॉलिड जातीय समीकरण साधने को वजह मान रहा है, कोई इसे भाजपा के भीतर दिल्ली और लखनऊ के तनाव से जोड़कर देख रहा है।

अयोध्या की हार सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि देशभर के भाजपा समर्थकों और हिंदुत्ववादी सोच के लोगों के लिए एक सदमे जैसा है। यूं तो फैजाबाद समाजवादी पार्टी के सबसे तगड़े समीकरण के सीटों में से एक है, लेकिन इस बार संविधान बदलने का जो माहौल, जो नैरेटिव पिछले कुछ दिनों में तैयार हुआ उसकी पृष्ठभूमि में अयोध्या और उसके सांसद लल्लू सिंह थे, जब भाजपा ने 400 पार का नारा दिया तो लल्लू सिंह ही वह पहले सांसद थे जिन्होंने अयोध्या में कहा कि 400 सीट भाजपा को संविधान बदलने के लिए चाहिए और उसके बाद तो संविधान बदल देने का मुद्दा ऐसा जोर पकड़ा कि भाजपा पूरे चुनाव में इस पर सफाई देती रही और इस नैरेटिव का जवाब देती घूमती रही। जो भाजपा अयोध्या के बल पर 2024 चुनाव का नैरेटिव गढ़ रही थी इस अयोध्या से निकली संविधान विरोधी आवाज ने उप्र में भाजपा का पूरा खेल बिगाड़ दिया।

वैसे भाजपा कोई पहली बार यह सीट नहीं हारी बल्कि 1984 के बाद से फैजाबाद की सीट पहले भी दो बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी दो बार इसे जीत चुकी है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा यह सीट हार जाएगी यह किसी को यकीन नहीं था। 1991 के बाद से भाजपा अयोध्या में मजबूत हुई, यहां से भाजपा के बड़े कुर्मी और हिंदूवादी चेहरे विनय कटियार ने तीन बार जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव 1989, 1998 और 2004 में यहां से सांसद चुने गए। जीतने के बाद भी भाजपा ने अयोध्या में अपने ओबीसी चेहरे विनय कटियार को हटाकर 2004 से लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाना शुरू किया जो 2014 और 2019 में जीते, जब-जब हिंदुत्व सिर चढ़कर बोला या मोदी मैजिक चला तब तक भाजपा जीती, लेकिन जैसे ही चुनाव जातियों पर आया भाजपा यहां से चुनाव हार गई।

इस हार की सबसे बड़ी वजह यहां के जातीय समीकरण बने। अयोध्या में जातियों का आंकड़ा समझ लीजिए। अयोध्या में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर हैं जिसमें कुर्मियों और यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। ओबीसी 22 फीसदी हैं, दलित मतदाता दूसरे नंबर पर आते हैं जिनकी तादाद लगभग 21 फीसदी है और उसमें भी पासी बिरादरी सबसे ज्यादा है, जिस तबके से सपा के जीते हुए उम्मीदवार अवधेश प्रसाद आते हैं। इसके अलावा मुस्लिम भी लगभग 18 फीसदी यहां हैं। ये तीनों मिलकर 50 फीसदी से ज्यादा होते हैं। इस बार ओबीसी वोटरों का एक साथ आना, इसके अलावा दलित वोटरों का इस सामान्य सीट पर दलित कैंडिडेट को जिताने का जुनून और मुस्लिम यादव वोटरों का एकमुश्त सपा का समर्थन, भाजपा की हार का कारण बना। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी की जीत और भाजपा की हार पर अखिलेश यादव ने कहा- सच्चाई यह है कि भाजपा उप्र में और भी सीटें हारती। मैं अयोध्या के लोगों को धन्यवाद देता हूं। समय-समय पर अयोध्या का दर्द देखा है। उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

शहर में हुआ विकास, गांव वालों की गई जमीन

अयोध्या के विकास में लोगों की जमीनों का अधिकार ग्रहण और मन मुताबिक मुआवजा न मिलना भी नाराजगी की एक वजह बनकर सामने आई। अयोध्या में लोगों के बीच एक चर्चा रही कि अयोध्या में अगर मंदिर बना, अयोध्या शहर का अगर विकास हो रहा है तो इसका फायदा अयोध्या के सुदूर गांव वालों को नहीं मिल रहा है, बल्कि बाहर से आने वाले बिजनेस करने वाले लोग ही उठा रहे हैं। जबकि अयोध्या के लोगों को बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में अपनी जमीन गंवानी पड़ रही है। भाजपा सिर्फ अयोध्या ही नही हारी बल्कि अयोध्या से सटी सभी सीटें हार गई। बस्ती, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी जैसी सीटें भी भाजपा हार गई। पूरे तरीके से जातीय गोलबंदी ने भाजपा को अयोध्या में धराशाई कर दिया। अयोध्या की हार को सिर्फ भाजपा की हार नहीं बल्कि हिंदुत्व के उनके पूरे नैरेटिव की हार के तौर पर देखा जा रहा है। जिस अयोध्या में विपक्ष के राम मंदिर नहीं जाने का मुद्दा भाजपा ने अखिलेश और गांधी परिवार के खिलाफ बनाया था, अब विपक्ष अयोध्या की हार को प्रधानमंत्री मोदी और संघ की हार बता रहा है।

बिहार की पॉलिटिक्स का फीनिक्स

राजनीति में पहले भी हारी बाजी पलटते रहे हैं नीतीश

नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में हार-जीत का दौर चलता रहा है। कई बार जब लोग उन्हें चुका हुआ मान लेते हैं तो वो फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। 1974 में जेपी आंदोलन से राजनीति में एंट्री करने वाले नीतीश 1985 में पहली बार विधायक बन पाए थे। इससे पहले उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा था। 1991 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव हारने के बाद नीतीश की राजनीति पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए थे, लेकिन 1995 आते-आते समता पार्टी बनाकर नीतीश कुमार फिर खड़े हो गए। 2004 की लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री रहते हुए नीतीश बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे, साथ ही एनडीए की भी बिहार में करारी हार हुई थी। लगभग 1 साल बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीट जीतकर उन्होंने वापसी कर ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीट पर सिमटने के बाद नीतीश युग के खत्म की बात हुई, लेकिन 1 साल बाद ही नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी, एक बार फिर 4 सीट कम जीतने के बावजूद नीतीश कुमार ने 5 साल की राजनीति जीत ली है।

एक पक्षी के बारे में किवदंतियां मशहूर हैं। हालांकि उसे किसी ने आज तक देखा नहीं लेकिन कहा जाता है कि वो जब भी मरता है तो खुद जल उठता है। इसके बाद खुद की राख से वो दोबारा जिंदा हो जाता है। उसे कहा जाता है फीनिक्स। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुछ वैसा ही माना जा रहा है। बिहार में जदयू के 12 सांसदों की जीत के बाद नीतीश कुमार की अहमियत बढ़ गई है। उनके बिना केंद्र में नई सरकार बनना मुश्किल है। चंद दिन पहले पटना में उनकी सियासी ताकत पर सवाल उठ रहे थे। अब वह पटना से लेकर दिल्ली तक सबसे मजबूत दिखने लगे। यही नीतीश कुमार की राजनीति है। वह राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके अगले कदम के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होता है। उन्हें उनके विरोधियों ने पलटू राम कहा। उन पर मीम बने। उनका एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें लिखा है- नीतीश सबके हैं। इन सबके बीच देश की सियासत में यह भी सच स्थापित हुआ है कि नीतीश कुमार हर बार पलट कर अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं। जब-जब उनके राजनीतिक रूप से खत्म होने की अटकलें लगीं वह मजबूत बनकर उभरे।

2013 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे। इसकी वजह थी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मिलना। 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश अकेले लड़े। राज्य में एकतरफ उनके प्रबल विरोधी रहे लालू प्रसाद थे तो दूसरी ओर भाजपा। 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बड़ी जीत मिली थी। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के दलों की बुरी तरह हार हुई थी। नीतीश कुमार की राजनीति का अंत होने की अटकलें लगाई जाने लगी थीं कि आगे उनके वापसी की राह कठिन है। तब चुनाव परिणाम के दिन ही उन्हें जानकारी मिली थी कि भाजपा ने उनके दो दर्जन विधायकों से संपर्क साधा है और वे पाला बदलने को तैयार थे। चंद घंटे में ही इतनी तेजी से घटनाक्रम बदले कि उनके पास सोचने का वक्त नहीं बचा। उस वक्त नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी ने बताया था कि उन्हें हार से अधिक हताशा चंद मिनटों में उनके ही दलों के कुछ नेताओं के बदले अंदाज से हुई। उन्हें माजरा समझने में देर नहीं लगी। लगभग एक घंटे वह अपने कमरे में बंद रहे। इसके बाद उन्होंने एक फोन लगाकर हालचाल पूछा और इसके बाद सीधे बोले, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। साथ आ जाइए। फोन के दूसरी ओर उनके धुर विरोधी लालू प्रसाद थे। 2015 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक ही था। नीतीश के उन करीबी नेताओं के अनुसार भले डेढ़ दशक तक दोनों एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हों लेकिन उससे पहले दो दशक तक साथ काम करने के कारण दोनों एक-दूसरे को नजदीक से पहचानते थे। लालू ने नीतीश के फोन का राजनीतिक संदेश भी समझा और उसके बाद दोनों की बातचीत का दौर जो शुरू हुआ वह अगले कुछ दिनों में मुकाम चढ़ गया। कल के धुर विरोधी बिहार में जय-वीरू की जोड़ी के रूप में सामने आ गए थे। इसके बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में नीतीश दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में आए और मुख्यमंत्री बने। यह शानदार वापसी मानी गई।

2017 तक बिहार में राजद के साथ सरकार चली। उसमें नीतीश का इकबाल कम होने लगा। नीतीश कुमार पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह कमजोर दिखने लगे। चारों ओर से घिरने लगे। कहा जाने लगा कि अब नीतीश कुमार की सियासी पकड़ कमजोर हो गई और राज्य में भाजपा-राजद ने जदयू को कमजोर कर दिया। ठीक उसी समय उन्होंने भाजपा में अपने सबसे पुराने सहयोगी रहे सुशील कुमार मोदी को फोन किया, बोले- दम घुट रहा है। सुशील मोदी ने उनसे कहा- आ जाएं वापस। वह मान गए। अगले कुछ दिन में भाजपा के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। 2019 में आम चुनाव में राज्य की 40 सीटों में एनडीए ने 39 सीटें जीतीं। उनमें 16 सांसद जदयू के थे। भाजपा को अकेले 303 सीटें मिली तो नीतीश को केंद्र में उम्मीद के मुताबिक जगह नहीं मिली। वह नाराज रहे।

नीतीश 2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ लड़े। एनडीए की जीत हुई, लेकिन जदयू बेहद कमजोर हो गई। नीतीश मुख्यमंत्री बने लेकिन उन पर कमजोर होने का ठप्पा लग गया। भाजपा का दबाव साफ दिखने लगा। इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव से बात की। बोले, काम करोगे साथ? तेजस्वी यादव को ऑफर अच्छा लगा। फिर दोनों साथ आ गए। नीतीश फिर उभर गए। वे पूरे देश में विपक्षी एकता के धुरी बन गए। संभावित प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की चर्चा होने लगी। बाद में अचानक मामला ठंडा लगने लगा। भाजपा और मजबूत दिखने लगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद नीतीश कुमार और भी कमजोर लगने लगे। उसी वक्त अचानक सीधा नरेंद्र मोदी से उनका संपर्क हुआ। वह रातों रात फिर बदल गए। फिर भाजपा के साथ सरकार बना ली। सवाल उठा कि क्या इस बार भाजपा उन्हें पहले की तरह जगह देगी। मगर, नीतीश ने 17 सीटें लीं। लोकसभा चुनाव के दौरान माना जा रहा था कि जदयू भाजपा के मुकाबले कमजोर रहेगी। मगर, नीतीश ने फिर चौंकाया। उनकी पार्टी को भाजपा के बराबर 12 सीटें मिलीं।

● **विनोद बक्सरी**

कवच भेद रहीं चीन की स्टील बुलेट

जम्मू-कश्मीर में चीन निर्मित स्टील बुलेट्स

2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद नाटो सेनाओं के अनेक हथियार और गोला बारूद वहीं पर छूट गए थे। तालिबान के कब्जे में आए वे घातक हथियार, अब पाकिस्तान के रास्ते जम्मू-कश्मीर तक पहुंच रहे हैं। इस आशंका ने भारत की सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। सैन्य बलों पर हुए हमले की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि तालिबान के पास मौजूद अमेरिकन एम16 राइफल व एम4 कार्बाइन जैसे हथियार, जम्मू-कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हाथ लगे हैं। हालांकि अभी इनकी संख्या तय नहीं है। इनके अलावा अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुई स्टील बुलेट पहले से ही घाटी में मौजूद हैं। अब चीन निर्मित स्टील बुलेट, पाकिस्तान के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में पहुंच रही हैं।

जम्मू-कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों के मद्देनजर, कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चार दिन में चार जगहों पर हुए आतंकी हमलों ने कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के माहौल को गरमा दिया है। विपक्ष, सरकार पर सवाल उठा रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की खुफिया इकाई एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। सर्च जारी है, बहुत जल्द दहशतगर्दों का खात्मा हो जाएगा। सूत्रों ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा, जम्मू-कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान के आतंकी संगठन, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाली अमेरिकन एम16-एम4 कार्बाइन का सौदा किया है। हालांकि अभी तक इन घातक हथियारों की बड़ी खेप घाटी में नहीं पहुंची है, लेकिन दर्जनभर कार्बाइन, आतंकियों के हाथ में हैं। वे इनका इस्तेमाल, सुरक्षा बलों पर हमले के दौरान कर रहे हैं। कठुआ में मारे गए आतंकी के पास से एम4 कार्बाइन बरामद हुई है। इतना ही नहीं, दहशतगर्दों के हाथ में जो घातक हथियार हैं, उनके लिए खास स्टील की बुलेट इस्तेमाल की जा रही हैं। ये बुलेट चीन निर्मित हैं। साथ ही जो ड्रोन और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, वे भी चीन निर्मित हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से इन हथियारों को भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश की जाती है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आतंकी हमलों पर कहा, जिस दिन देश में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, कई राष्ट्रों के अध्यक्ष आए हुए थे, उसी दिन रियासी में आतंकी हमला हुआ। उसमें नौ तीर्थयात्री मारे गए थे। वह मंजर देखकर सभी दहल गए। उसके बाद से लगातार जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा, क्या यही नया कश्मीर है। वहां रोज आतंकी हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। सूत्रों के अनुसार, अब यह बात स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर के जंगलों में छिपे बैठे आतंकियों के पास एम4 और एम16 जैसी घातक कार्बाइन हैं। उनके पास अमेरिकी निर्मित हथियारों के अलावा गोला-बारूद भी है। आतंकियों द्वारा जब कभी सैन्य कैंप, वाहन या नाके पर हमला किया जाता है, तो अमेरिकन कार्बाइन और चीन निर्मित हैंड ग्रेनेड एवं स्टील की गोलियों का इस्तेमाल होता है।

गत दो वर्षों में राजौरी और पुंछ के इलाकों में हुए आतंकी हमलों में तालिबान से मिले हथियार प्रयोग में लाए गए हैं। आतंकियों ने स्टील बुलेट इस्तेमाल की हैं। ये बुलेट किसी भी बख्तरबंद गाड़ी को भेद सकती हैं। सामान्य बुलेटप्रूफ जैकेट और पटका, इससे बचाव नहीं कर पाते। तालिबान से घातक अमेरिकन राइफलें और स्टील की गोलियां, घाटी में पहुंच रही हैं, ये सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय है। देश में अभी तक सुरक्षाबलों के साजो सामान का जो पैटर्न है, वह लेवल-3 का है। मतलब, ज्यादातर बुलेटप्रूफ वाहन, मोर्चा, जैकेट और पटका लेवल 3 श्रेणी वाले होते हैं। स्टील की गोलियां, जिसे आर्मर पियर्सिंग इन्सेंडरी (एपीआई) कहा जाता है, इन्हें भेद सकती हैं। देश में हर जगह पर लेवल-4 बुलेटप्रूफ कवच नहीं है। इस कवच को केवल चुनिंदा ऑपरेशनों में ही इस्तेमाल किया जाता है।

सुरक्षा बलों के सूत्रों के मुताबिक, पिछले कई दशकों से जम्मू-कश्मीर में आतंकियों द्वारा जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वे लोकल थे। उनमें से ज्यादातर हथियार, सुरक्षा बलों पर हमला कर लूटे गए थे। उस वक्त आतंकी, एके 47 राइफल का ही ज्यादा इस्तेमाल करते थे। 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो समूह की सेना, वापस गई तो वहां की सत्ता तालिबान के हाथों में आ गई। नाटो की सेनाओं के ज्यादातर हथियार और गोला बारूद वहीं पर छूट गए। उसके बाद तालिबान के कब्जे में आए वे घातक हथियार, पाकिस्तान के रास्ते जम्मू-कश्मीर तक पहुंचने लगे। 2022 में एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पाकिस्तान के दो आतंकी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, तालिबान से अमेरिकी हथियारों का सौदा करने के प्रयास में हैं। हालांकि ट्रायल के लिए कई हथियार, इन आतंकी संगठनों को मुहैया कराए गए थे। सूत्रों का कहना है कि दोनों आतंकी संगठनों ने जम्मू-कश्मीर के लिए तालिबान से करीब सत्तर एम16 व एम4 राइफलों की मांग की थी।

अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों के वापस लौटने के बाद 85 बिलियन डॉलर के एयरक्राफ्ट, बख्तरबंद गाड़ियां, रॉकेट डिफेंस सिस्टम, मशीन गन और असॉल्ट राइफल सहित भारी मात्रा में गोला बारूद पर तालिबान का कब्जा हो गया था। हालांकि अमेरिका ने दावा किया था कि उसने तालिबान के हाथ लगे अपने अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट, बख्तरबंद गाड़ियां व रॉकेट डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया है। अफगानिस्तान में 4 सीब-130 ट्रांसपोर्ट्स, 23 एम्ब्रेयर ईएमबी 314/ए29 सुपर सुकानो, 28 सेसेना 208, 10 सेसेना एसी-208 स्टाइक एयरक्राफ्ट फिक्सड् विंग एयरक्राफ्ट बताए गए हैं। इनके अलावा 33 एमआई-17, 33 यूएच-60 ब्लैकहॉक व 43 एमडी 530 हेलीकॉप्टर भी हैं। अमेरिकी 22174-ह्मवे, 634 एमआई 117, 155 एमएक्सएक्स प्रो माइन प्रूफ व्हीकल, 169 एमआई 13 आर्म्ड पर्सनल केरियर, 42000 पिक अप ट्रक एंड एसयूवी, 64363 मशीन गन, 8000 ट्रक, 162043 रेडियो, 16035 नाइट गॉगल, 358530 असॉल्ट राइफल, 126295 पिस्टल और 176 आर्टलरी पीस भी तालिबान के कब्जे में बताए गए हैं।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

रूस-चीन की बढ़ती नजदीकियां

वैश्विक भू-राजनीति के मामले में हर एक कूटनीतिक कदम अपनी अहमियत रखता है, खासकर जब उसमें प्रमुख देशों के नेता भी शामिल हों। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाल की चीन यात्रा से खलबली मची है, उसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर इस दृष्टि से कि भारत के लिए इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। दुनिया की दो सबसे प्रभावशाली शक्तियां, रूस और चीन जबकि करीब आ रही हैं, जाहिर है उसके नतीजे उनके तात्कालिक द्विपक्षीय रिश्ते से आगे बढ़कर निकल सकते हैं। पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल के दिनों में ऑनलाइन संपर्कों के अलावा कई बार प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर शिखर बैठकें भी की हैं। इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के बाद ही रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। इस बैठक में दोनों देशों ने असीम साझीदारी की घोषणा की थी। इस भू-राजनीतिक मोड़ के बीच में स्थित भारत के लिए इस साझीदारी के परिणाम बहुआयामी हो सकते हैं और इनका सावधानी से विश्लेषण करने की जरूरत है।

पुतिन ने चीन की जो यात्रा की और यूक्रेन के खारकीव क्षेत्र पर रूस ने जो ताजा हमला किया उसकी पृष्ठभूमि को अगर समझें तो इसके कारण भारत पर होने वाले प्रभावों का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। रूस-चीन संबंधों में हाल में उल्लेखनीय बदलाव आया है। शीतयुद्ध के दौर में इन दोनों के संबंध संदेह और प्रतियोगिता से भरे थे, जो 21वीं सदी में रणनीतिक साझेदारी में बदले। अब इन दोनों ने जो असीम साझेदारी की घोषणा की है उसके कई कारण हैं, जिनमें अमेरिकी वर्चस्व को लेकर साझा चिंता, आर्थिक हितों की चिंता, और कुछ अंतरराष्ट्रीय मसलों पर नजरिए में समानता शामिल हैं।

रूस और चीन के बीच सहयोग का एक प्रमुख घोषित क्षेत्र है- ऊर्जा। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण ऊर्जा समझौते किए हैं, जिनमें पाइपलाइनों के निर्माण और प्राकृतिक गैस की बिक्री के समझौते शामिल हैं। इनके कारण उनके आर्थिक संबंध भी मजबूत हुए हैं। चीन की यात्रा के दौरान पुतिन ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए पावर ऑफ साइबेरिया-2 गैस पाइपलाइन को चालू करने पर वार्ता की। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी प्रभावित होगी। रूस जबकि चीन के साथ अपनी ऊर्जा साझेदारी को मजबूत कर रहा है, भारत को किसी एक ही सप्लायर पर निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा के कई स्रोत ढूंढने की जरूरत पड़ सकती है।

पुतिन की यात्रा से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। इस क्षेत्र में भारत और चीन के हितों का टकराव है और दोनों की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी टकराती हैं। मॉस्को और बीजिंग में बढ़ती नजदीकियां चीन को इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी पर अमल करने और हिमालय क्षेत्र में भारत के साथ भूमि विवाद में कार्रवाई करने की हिम्मत बढ़ा सकती हैं। ऐसे संघर्षों में रूस का गुप्त समर्थन या उसकी तटस्थता भारत के रणनीतिक समीकरणों को जटिल बना सकती है और उसे अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को बदलना पड़ सकता है। असीम साझेदारी, और इस धारणा के कारण कि चीन रूस की युद्ध संबंधी कार्रवाईयों का स्पष्ट समर्थन कर रहा है, भारत युद्ध की स्थिति में चीन पर अंकुश लगाने की रूस से अपेक्षा नहीं कर सकता है।

एक और विचारणीय पहलू यह है कि रूस-चीन सहयोग अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को किस तरह प्रभावित करेगा। भारत ने रूस के साथ अपनी पारंपरिक साझेदारी और अमेरिका के साथ मजबूत होते अपने रणनीतिक रिश्ते के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने कोशिश की है। रूस-चीन की बढ़ती नजदीकियां भारत को अमेरिकी खेमे में और अंदर धकेल सकती हैं। वैसे, भारत चीन-रूस साझेदारी के कारण बढ़ते दबाव को संतुलित करने की ही कोशिश करेगा।

यह भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधी सहयोग में वृद्धि और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मसलों पर बढ़ती करीबी के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन भारत की विदेश नीति का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है, रणनीतिक स्वायत्तता, उसकी कड़ी परीक्षा लेगा रूस-चीन का गहराता संबंध। इसके अलावा, पुतिन की चीन यात्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के गतिशास्त्र में आ रहे बदलाव को भी रेखांकित करती है। शक्ति पश्चिमी देशों के हाथ से धीरे-धीरे पूरब की उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर खिसक रही है। रूस-चीन की साझेदारी जबकि मजबूत हो रही है, वे पश्चिमी संस्थानों तथा मानदंडों के वर्चस्व वाली मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। इस उभरती बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था को आकार देने में भारत को ज्यादा जोरदार भूमिका निभाने के मौके दे सकता है। इसकी वजह यह है कि वह अपनी रणनीतिक स्थिति और बढ़ती आर्थिक ताकत का लाभ उठा सकता है। भारत अपनी सक्रियता बढ़ाने की जो कोशिश कर रहा है और ग्लोबाल साउथ (जिसे जी-20 के दौरान काफी समर्थन मिला) की आवाज बनकर उभरने की जो कोशिश कर रहा है वह सब सही दिशा में उठाया गया कदम है।

● **कुमार विनोद**

सजग रहे भारत

अपने हितों की रक्षा के लिए भारत को काफी संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। उसे समझना चाहिए कि रूस-चीन नजदीकियां भारत को दोनों देशों के साथ आपसी हितों (जैसे आतंकवाद विरोध, क्षेत्रीय स्थिरता, और आर्थिक विकास) के मसलों पर ज्यादा कार्रवाई करने के मौके प्रदान करती हैं। रूस-भारत के दशकों पुराने रिश्ते को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर सैन्य सहयोग के रिश्ते को। दशकों से, भारत ने तमाम तरह के रूसी हथियार हासिल किए हैं, मसलन सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमान, टी-90 टैंक, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आदि। एस-400 मिसाइल सिस्टम की बात ही क्या करें, जिसका करार अमेरिका के भारी विरोध और उसके सीएएटीएसए जैसे प्रतिबंधात्मक कानून के साए में किया गया। इसके अलावा, रूस भारत को अहम रक्षा टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है ताकि खास वेपन सिस्टम का भारत में ही उत्पादन हो सके और उपयोग लायक बनाया जा सके। रूस-चीन नजदीकी, और मॉस्को तथा वाशिंगटन के बीच संतुलन साधने की भारतीय कोशिशें उसी बात को दोहराती हैं जो 19वीं सदी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन ने एक बार कहा था- स्थायी शत्रु कोई नहीं होता, और न कोई स्थायी दोस्त होता है, स्थायी कुछ है तो वे हैं अपने हित।

संघर्ष कर पाया मुकाम

मप्र में भाजपा के जीते सभी 29 सांसदों में 6 महिला सांसद भी हैं। ये पहली बार है, जब एक ही पार्टी से इतनी महिलाएं संसद में पहुंची हैं। राजनीति में संघर्ष के बाद ये महिलाएं संसद की दहलीज पर पहुंची हैं।

भिंड सांसद संध्या राय का बाल विवाह हुआ था। शादी के बाद उन्होंने न केवल आगे की पढ़ाई जारी रखी, बल्कि राजनीति में भी अपनी अलग छाप छोड़ी है। सागर की लता वानखेड़े कभी पति के साथ गांव की पंच चुनी गई थीं, अब पति बिजनेस संभाल रहे हैं और लता संसद पहुंच चुकी है। बालाघाट की भारती पारधी दादा ससुर के बाद संसद में पहुंचने वाली परिवार की दूसरी सदस्य हैं। उनके दादा ससुर 62 साल पहले गैर कांग्रेसी सांसद चुने गए थे। अनीता नागर ने रतलाम में कांतिलाल भूरिया को हराकर एक नई लकीर खींची है। तो शहडोल से दूसरी बार जीत दर्ज करने वाली हिमाद्री सिंह अपनी मां व पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं।

भिंड-दतिया सीट से लगातार दूसरी बार जीतीं संध्या राय के मुताबिक शादी के बाद उनके पति ठेकेदारी करने लगे थे। बाद में सरपंच का चुनाव भी लड़े। 25 साल की उम्र में संध्या राय की राजनीति में एंट्री संयोग से हुई। दरअसल, 2000 में कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित हुआ, तो पार्टी की ओर से उनके पति को सुझाव दिया गया कि संध्या का नॉमिनेशन करा दो। ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हो रहे थे। लेकिन पार्टी समर्थित लोग ही मैदान में उतरे थे। पार्टी के दबाव में पति ने फॉर्म तो भरवा दिया, लेकिन वे तीनों बच्चों के छोटे होने के चलते इसके लिए तैयार नहीं थे। संध्या के मुताबिक उन्हें भी राजनीति का कोई अनुभव भी नहीं था। अभी तक वो घर ही संभाल रही थी। पति की मंशा थी कि आखिरी डेट में फॉर्म वापस ले लेंगे। फॉर्म वापस लेने वो पति के साथ गईं भी, लेकिन उस समय अम्बाह में पदस्थ एसडीएम गुप्ता ने सलाह दी कि संध्या को चुनाव लड़ने दो। जब प्रचार की बारी आई तो पति ने कहा कि घर से नहीं निकलना है। पर हमारी युवा टीम और वोट देने वाले किसान इस पर अड़ गए कि प्रत्याशी को देखना है। वे ट्रैक्टर लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच जाते थे। उनकी मांग और पार्टी के दबाव के आगे पति को झुकना पड़ा। आखिरी के चार दिन प्रचार के लिए वो निकलीं। संकोच और झिझक के साथ शुरुआत हुई, लेकिन महिला टीम का साथ और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने से वो जीत गईं। 2003 के विधानसभा में उन्हें दिमनी विधानसभा से सीटिंग एमएलए मुंशीलाल का टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया, जबकि दावेदारी उनके पति ने की थी। वह ये चुनाव जीत गईं। उन्हें 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा में टिकट नहीं मिला, मगर वे संगठन में सक्रिय रहीं। 2017 में संध्या को राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाया गया। इसके बाद 2019 में उन्हें भिंड लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया। वे पहली बार सांसद का चुनाव जीतीं। संध्या के पति अब व्यवसाय में रम चुके हैं। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा बीई के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा है तो छोटा बेटा एमबीए कर चुका है।

शहडोल लोकसभा सीट से हिमाद्री सिंह लगातार दूसरी बार सांसद चुनी गईं। उन्होंने पुष्पराजगढ़ में 500 मीटर दूर रहने वाले फुंदेलाल मार्को को 3.97 लाख वोटों के अंतर से हराया है। हिमाद्री का परिवार कांग्रेसी था। 2009 में मां राजेश नंदिनी के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनौती देने वाले नरेंद्र मरावी से 2017 में हिमाद्री ने शादी की। इस शादी ने हिमाद्री की किस्मत पलट दी। हिमाद्री कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुईं। 2019 में भाजपा ने हिमाद्री को शहडोल लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और वे जीत गईं। रतलाम-झाबुआ लोकसभा सीट से चुनाव जीतीं अनीता नागर चौहान इस क्षेत्र की दूसरी महिला सांसद हैं। 1962 में जमुना देवी यहां से पहली महिला सांसद बनी थीं। रतलाम लोकसभा सीट से भाजपा की किसी महिला उम्मीदवार ने पहली बार सांसद का चुनाव जीता है। अनिता के पति नागर सिंह चौहान चौथी बार के विधायक और प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं।

भाजपा ने सागर लोकसभा सीट से इस बार अपनी सीटिंग सांसद राजबहादुर सिंह का टिकट कर डॉ. लता वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया था। लता ने इस सीट को 4.71 लाख के अंतर से जीता है। इस सीट से जीतने वाली वे दूसरी महिला सांसद हैं। इससे पहले यहां 1980 में कांग्रेस की सहोद्राबाई सांसद चुनी गई थीं। इस सीट पर भाजपा की वो पहली महिला सांसद हैं। दमोह के पथरिया में जन्मी लता के पिता सरकारी विभाग में एग्रीकल्चर में इंजीनियर थे। पांच भाई बहनों में तीसरे नंबर की लता ने एमए अर्थशास्त्र और पत्रकारिता से मास्टर डिग्री ली है। पत्रकारिता में ही उन्होंने पीएचडी भी की है। लता की 1991 में कांट्रेक्टर व भाजपा नेता नंदकिशोर उर्फ गुड्डू वानखेड़े से शादी हुई थी। उधर, बालाघाट सीट से चुनाव जीतीं भाजपा की भारती पारधी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। वे बालाघाट सीट पर जीतने वाली पहली महिला सांसद हैं। भाजपा ने अपने सीटिंग सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर उन्हें मैदान में उतारा था। उनका मुकाबला कांग्रेस के सम्राट सिंह सारस्वत से था। भारती ने ये चुनाव 1.74 लाख के अंतर से जीता। भारती पारधी ने पार्षद से सांसद का सफर तय किया है।

● ज्योत्सना

सावित्री दूसरी बार सांसद और पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री

10वीं पास धार की भाजपा सांसद सावित्री ठाकुर ने राजनीति में अपने दम पर मुकाम बनाया है। पिता राज्य वन विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। पति तुकाराम ठाकुर किसान है। मायके और ससुराल में कोई भी राजनीति में नहीं था। सावित्री राजनीति में आने से पहले एनजीओ में को-ऑर्डिनेटर थीं। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आईं। पढ़ी-लिखी महिला आदिवासी होने का फायदा सावित्री को मिला। वर्ष 2004 में सावित्री जिला पंचायत सदस्य चुनी गईं। 2014 में भाजपा ने धार लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। सावित्री ने इस चुनाव में कांग्रेस के उमंग सिंघार को हराया। सावित्री ठाकुर को उद्योग पर बनी संसदीय समिति का सदस्य बनने का अवसर मिला। 2019 में उनका टिकट काटकर भाजपा ने छतर सिंह दरबार को प्रत्याशी बनाया था। भाजपा ने इस बार छतर का टिकट काटकर फिर सावित्री को मौका दिया और वे दूसरी बार संसद में पहुंच गईं। साथ ही उन्हें मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया है।

पाप करने के लिए क्यों विवश हो जाता है मनुष्य

महाभारत के युद्ध में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना आज भी है। क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप यहां जान सकते हैं कि किन परिस्थियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है।

अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा था

केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः।
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः॥

इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण से यह प्रश्न पूछते हैं, कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है। जिसके उत्तर में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है।

इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्॥

यानी जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढंका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढंका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढंका रहता है। भगवान श्रीकृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआ अग्नि को ढंक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढंक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है।

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥

और हे अर्जुन! इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढंका हुआ है।

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम॥

इन्द्रियां, मन और बुद्धि- ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य की वासना एवं निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की किसी चीज को पाने की इच्छा है, इसलिए काम वासना से मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है।

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम॥

इसलिए हे अर्जुन! तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना (किसी चीज को पाने की इच्छा) है क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है। भगवान श्रीकृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं। जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है।

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥

इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है।

एवं बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना।
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम॥

इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात् सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल।

श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। आसक्ति विरक्ति का अभाव होना उत्तम जीवन माना जाता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि रजोगुण, आत्मा को भ्रमित कर उसे यह विश्वास दिलाता है कि सांसारिक सुख से ही सबकुछ है जिस कारण किसी भी मनुष्य में इन्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। कामना से लोभ उत्पन्न होता है और लोभ पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना, लोभ और क्रोध इन तीनों विकारों से ग्रस्त होकर मनुष्य पाप करता है।

श्रीकृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा पाप करते हुए पश्चाताप का बोध कराती है, हमें रोकती है। भगवान का अंश होने के कारण हममें स्वाभाविक रूप से अच्छाईयां मौजूद रहती हैं, जिसके कारण हममें अंतर्बोध की स्थिति होती है और अंतर्बोध के कारण हमें कहीं न कहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज हमें ऐसे कृत्य करने से रोकती है। लेकिन हम फिर भी नहीं रुकते बल्कि अपनी कामना पूर्ति के लिए पाप करते हैं। इसलिए, हम यह कहकर नहीं बच सकते कि चोरी, ठगी, निंदा, लूट-खसोट, हत्या, अत्याचार और भ्रष्टाचार पापजन्य कृत्य नहीं हैं। हमारी अंतर्दृष्टि यह बोध कराती है कि ये सब कार्य पापजन्य हैं फिर भी हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि कोई शक्ति हमें बलपूर्वक ऐसा करने के लिए विवश करती है।

ईश्वरीय दूतों का इसलिए पापों से दूर रहना आवश्यक है क्योंकि यदि वे लोगों को पापों से दूर रहने की सिफारिश करेंगे किंतु स्वयं पाप करेंगे तो उनकी बातों का प्रभाव नहीं रहेगा जिससे उनके आगमन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय दूत समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक होते हैं इसलिए मानव जाति की महानता की अंतिम श्रेणी पर उनका होना आवश्यक है क्योंकि यदि ऐसा न हुआ तो और वे अपने से उच्च श्रेणी वालों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों पर उनकी बातों का प्रभाव नहीं होगा।

● **ओम**

गम और खुशी

एक घर में गम बहुत दिनों से डेरा जमाए बैठा था। निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसी घर के बाहर बहुत दिनों से खुशी खड़ी थी, यह सोचकर कि कब गम बाहर आए और वह घर के अंदर चली जाए। अब गम भी बहुत दिनों बैठा उकता गया और उस घर से निकलने लगा। दरवाजे पर ही खुशी मिली और इतरा कर गम से बोली- आखिर उकता गए ना इस घर में बैठे बैठे, आखिर उकताते कैसे नहीं घर में तुम्हें सब कोस रहे होंगें, अब जाती हूं घर के अंदर देखना, मुझे इस घर के लोग सर आंखों पर बैठा लेंगे तुम्हें कोई चाहता ही नहीं...।

गम बोला- अरे खुशी, इतना मत इतरा तू उसी जगह पर जा सकती है, जिस जगह को मैं तेरे लिए खाली कर देता हूं, तू भी कब से खड़ी थी दरवाजे पर मुझे भी तुझ पर तरस आ गया और मैंने ये घर छोड़ दिया। मैं अपनी जगह ना छोड़ूं तो तुझे कहीं जगह मिल ही नहीं सकती, जा अब तू रह ले इस घर पर मेरे निकल जाने के बाद तू कहीं जाती है ना तो ही लोग तेरी कीमत समझते है, वरना तेरी भी किसी ने कीमत नहीं समझी और तू भी तो टिकती नहीं एक जगह, मेरे पीछे-पीछे घूमती रहती है। गम की बातों का खुशी के पास कोई जवाब नहीं था वह झट से घर के अंदर चली गई।

- अमृता राजेंद्र प्रसाद

लालच

राजेंद्र और रोहिणी के बीच तलाक हुए दस बरस बीत गए। गौरव की परवरिश राजेंद्र ने की। गीतिका रोहिणी के पास पली-बढ़ी। राजेंद्र ने गौरव के वास्ते दूसरी शादी नहीं की।

रोहिणी ने अपना दूसरा घर बसा लिया। उसे जयेश से एक और बेटी सुनंदा मिली।

इसी बीच उनके एक ही शहर में होने के कारण गौरव अपनी मां रोहिणी से अक्सर मिलने चला जाया करता था। पर गौरव के बड़े होने पर जयेश को पता नहीं क्या सूझा कि अपने परिवार से उसके मिलने-जुलने पर सख्ती बरतने लगा। फिर भी जयेश की अनुपस्थिति में गौरव रोहिणी से मिल लिया करता था।

एक दिन रोहिणी ने ही बड़े कड़े स्वर में गौरव से कहा- गौरव! आज के बाद तुम इस तरह मुझसे मिलने मत आना। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। तुम अकेले भी तो नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा हैं। रोहिणी का सख्त स्वर सुनकर गौरव को बड़ा दुख हुआ- मम्मी! मैं बड़ा लालची हो गया हूं। एक ही लालच मुझे आप तक खींच लाता है।

लालच! लालच, किस चीज का? रोहिणी के मन में घबराहट और अचरज दोनों ने एक साथ दस्तक दिया।

आपके प्यार का। कहते हुए गौरव पीछे मुड़ा। वह लंबे कदमों से आगे बढ़ रहा था। रोहिणी उसे नहीं रोक सकी।

- टीकेश्वर सिन्हा गब्दीवाला

आओ धरती का श्रृंगार करें

कब तक जंगल काटोगे?
चंद सिक्कों के लालच में।
कब तक जहर बांटोगे?
चंद रूपयों के लालच में।।
काट रहे हो हरियाली,
बना रहे हो बंजर धरती।
अन्न कहां से पाओगे?
बिन पानी खेती परती।।
तुम्हारे घर भी जलेंगे,
उस सूरज की तपिश में।
तुम्हारे श्वांस भी रुकेंगे,
जीवन की खलिश में।।
क्या तेरे दर आंच न आएगी?
तेरा मकां भी है इसी शहर में।
ढह जाएगा तेरा भी घर,
उस कुदरत के कहर में।।
तप रही है सारी धरती,
तप रहा सारा आकाश।
समय रहते हों सचेत,
वरना होगा महाविनाश।।
जब तरु ही न रहेंगे भू पर,
वर्षा कहां से आएगी?
बिन छाया, बिन पानी,
धरती तब थर्राएगी।।
आओ धरती का श्रृंगार करें,
मिलकर पेड़ लगाएं हम।
हरी-भरी हो धरा हमारी,
जीवन सफल बनाएं हम।।

- महेन्द्र कुमार साहू 'खलारीवाला'

एमएलसी का भविष्य तय करेगा विश्वकप

दुनिया की सबसे लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग की बराबरी करने के लिए एक ओर जहां पाकिस्तान ने 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग शुरू की तो वहीं 2011 में बिग बैश लीग की शुरुआत कर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने भी आईपीएल से मुकाबला करने की कोशिश की थी। अब अमेरिका पहली बार किसी क्रिकेट विश्वकप की मेजबानी कर रहा है। जिसकी शुरुआत 2 जून से हो गई है। चर्चा है कि अमेरिका अपनी फ्रेंचाइजी मेजर लीग क्रिकेट को विश्वकप के जरिए क्रिकेट जगत में इतना बड़ा बनाएगा कि वो आईपीएल को मात दे सके। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि विश्वकप से अमेरिकी क्रिकेट लीग को कैसे फायदा मिलेगा? क्या एमएलसी का भविष्य विश्वकप तय करेगा?

मौजूदा समय में क्रिकेट की सबसे लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण वर्ष 2008 की शुरुआत में खेला गया था और तब इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने भी प्रतिभाग किया था। लेकिन इसी साल नवंबर महीने में मुंबई हमला हुआ और आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका बदला लेने के लिए आठ साल बाद यानी 2016 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) शुरू की लेकिन अभी तक यह लीग आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाई। ऐसी ही एक कोशिश 2011 में बिग बैश लीग की शुरुआत कर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने भी की थी मगर सफलता नहीं मिली। इसके बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) द्वारा भी द हंड्रेड लीग प्रस्तावित की गई थी लेकिन वो भी फेल ही रही। अब अमेरिका पहली बार किसी क्रिकेट विश्वकप की मेजबानी कर रहा है। जिसकी शुरुआत 2 जून से हो गई है। अमेरिका की कोशिश है कि विश्वकप के जरिए क्रिकेट में उसकी जगह बने और विश्वकप के जरिए अपनी फ्रेंचाइजी मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) को इतना बड़ा बनाए कि वो इंडियन प्रीमियर लीग को मात दे सके।

खेल समीक्षकों और पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि अमेरिका में पहले से बैट और बॉल से जुड़ा खेल बेसबॉल काफी लोकप्रिय है। यहां इस खेल की फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग एमएलबी यानी मेजर लीग बेसबॉल का आयोजन होता है। अमेरिका ने अपनी क्रिकेट लीग का नाम भी इसी तर्ज पर रखा है ताकि बेसबॉल के प्रेमी इस लीग की ओर भी आकर्षित हो सकें। इसके अलावा सॉकर (फुटबॉल) लीग का नाम भी इसी तर्ज पर एमएलएस है, यानी मेजर लीग सॉकर। अमेरिकी क्रिकेट बोर्ड ने 2018 में फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट लीग शुरू करने की बात कही थी। शुरुआती अड़चनों से पार पाते हुए मई 2022 में लीग के लिए 120 मिलियन डॉलर, यानी करीब एक हजार करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई गई। राजारमण, एडोबी के पूर्व प्रमुख शांतनु नारायण शुरुआती इन्वेस्टर्स में शामिल रहे। एमएलसी का पहला सीजन जुलाई 2023 में 6 टीमों के साथ खेला गया। सभी टीमों में भारतीय इन्वेस्टर्स शामिल थे। शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी केकेआर, मुंबई इंडियंस को रन करने वाली कंपनी इंडिया विन स्पोर्ट्स, दिल्ली कैपिटल्स की मालिक जीएमआर स्पोर्ट्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने अलग-अलग सहयोगियों के साथ टीमें खरीदीं। एमएलसी के पहले सीजन में 14 जुलाई से 26 जुलाई तक ग्रुप स्टेज के 15 मैच खेले गए। 27, 28 और 30 जुलाई को प्लेऑफ के 4 मुकाबले हुए। सभी 19 मैच डलास और मोरिसविले स्टेडियम में ही कराए गए। 6 टीमों ने ग्रुप स्टेज में 5-5 मैच खेले, यानी एक टीम ने बाकी 5 टीमों से 1-1 मैच खेला। मुंबई न्यूयॉर्क ने एलिमिनेटर और क्वालिफायर-2 जीतकर सीटल ओरकास को फाइनल में 7 विकेट से हराया था। अब टी-20 विश्वकप का फाइनल 29 जून को होगा। इसके सात दिन बाद यानी 6 जुलाई से अमेरिका में एमएलसी का दूसरा सीजन शुरू हो जाएगा। इस बार भी 2 ही स्टेडियम में मैच होंगे, लेकिन ग्रुप स्टेज में 15 की बजाय 21 मैच खेले जाएंगे। एक टीम 5 की जगह 7 मैच खेलेगी। ऐसे में विश्वकप के ठीक बाद एमएलसी का दूसरा सीजन शुरू होगा, इससे अमेरिकन खेल प्रेमियों के साथ दुनिया के क्रिकेट प्रेमी भी जुड़ेंगे। दूसरे सीजन के मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे और सुबह 6 बजे से शुरू होंगे। ये टाइमिंग अमेरिका के हिसाब से रात की रहेगी, इससे ज्यादा दर्शक स्टेडियम पहुंचकर मैच देखेंगे। जबकि पहले सीजन में कुछ मैच अमेरिकन टाइमिंग के हिसाब से दोपहर में हुए थे। इससे मैच टिकट ज्यादा नहीं बिके थे।

इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू 89 हजार करोड़ रुपए है, जबकि एमएलसी की एक हजार करोड़ रुपए है। आईपीएल में एक हजार करोड़ रुपए तो खिलाड़ियों के वेतन पर ही खर्च हो जाता है, इसके मुकाबले में एमएलसी में खिलाड़ियों की सैलरी पर महज 57 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेलों में क्रिकेट शामिल नहीं है, जबकि भारत में क्रिकेट से ज्यादा कोई और खेल नहीं देखा जाता है। मेजर लीग क्रिकेट फिलहाल शुरुआती फेज में है, यहां प्लेइंग-11 में 6 विदेशी प्लेयर खेल सकते हैं जबकि आईपीएल में महज 4 ही विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं। आईपीएल के सफल होने की सबसे बड़ी वजह इंडियन खिलाड़ी भी हैं।

● आशीष नेमा

अमेरिका में क्रिकेट की घरवापसी

अमेरिका उन देशों में शामिल है जहां दुनियाभर के लोग बसे हुए हैं। इसकी आबादी 33 करोड़ से ज्यादा है जिनमें करीब पांच करोड़ लोग दूसरे देशों के यानी अप्रवासी हैं। इनमें भी 50 लाख साउथ एशियन हैं और करीब 1.50 करोड़ लोग उन देशों के हैं, जहां क्रिकेट की लोकप्रियता ज्यादा है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और वेस्टइंडीज शामिल हैं। यानी अमेरिका में इस बार टी-20 विश्वकप के जो 16 मैच होंगे, वहां टीमों को सपोर्ट की कमी नहीं रहेगी। आईसीसी अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करेगी। जीडीपी के हिसाब से अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है। यहां क्रिकेट बढ़ा तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) अमेरिका की बड़ी कंपनियों को स्पॉन्सरशिप के लिए टारगेट करेगी। इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में मनी-फ्लो तेजी से बढ़ जाएगा। फिलहाल क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास है। अमेरिका में क्रिकेट सफल रहा तो आईसीसी की कमाई भी बीसीसीआई को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच सकती है।

इसे निकालो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा

अमिताभ को हटाने के लिए प्रोड्यूसर ने दिया लालच

सात हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म के रिलीज होने के करीब 4 साल बाद अमिताभ को एक ऐसी फिल्म मिली जिसने उनके करियर को संवार दिया था लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही फ्लॉप हो गई थी।

यहां जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह फिल्म थी बंधे हाथ यह फिल्म साल 1973 में रिलीज हुई थी। इसे कोई खरीददार नहीं मिला था। इतना ही नहीं रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ओपीआर लहन अमिताभ बच्चन के साथ आरके स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। तभी जीपी सिप्पी और उनकी टीम ने रलहन से मुलाकात की। जीपी सिप्पी ने अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकालने के लिए रलहन से कहा।

उन्होंने कहा- तुम इसे (अमिताभ) बाहर निकाल दो और किसी दूसरे अभिनेता को ले लो और अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन रलहन ने साफ मना कर दिया। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। जब फिल्म रिलीज हुई, जैसा कि अनुमान था, यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जब अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई तो बंधे हाथ फिल्म के प्रोड्यूसर ने इसे फिर से कई जगहों पर दोबारा रिलीज किया। इसके बाद बिग बी की किस्मत चमक उठी।

घमंडी थे राजेश खन्ना, अपने आगे किसी को नहीं समझते थेः फरीदा जलाल

राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की फिल्म आराधना 1969 की सबसे बड़ी हिट थी। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फरीदा ने अपने करियर की शुरुआत इसी से ही की थी। आराधना के सफलता का सारा श्रेय राजेश खन्ना को ही जाता है। अब इस फिल्म के रिलीज के 55 साल बाद फरीदा जलाल ने दिवंगत सुपरस्टार को घमंडी कहा है।

एक इंटरव्यू में फरीदा जलाल ने आराधना फिल्म के दिनों को याद किया। उन्होंने बातचीत में बताया कि राजेश खन्ना संग काम करना काफी मुश्किल था। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा- आराधना की रिलीज के समय तक राजेश थोड़े घमंडी भी हो गए थे और आराधना की सफलता के बाद, उनका घमंड और भी बढ़ गया था वह अपने आगे किसी को नहीं समझते थे। फरीदा ने खुलासा किया वह राजेश को उनकी बाकी फीमेल फैंस की तरह उतना महत्व नहीं देती थीं, जिसकी वजह से अभिनेता उनके थोड़ा नाराज भी रहते थे। इसलिए अक्सर दोनों के बीच तू-तू, मैं-मैं हो जाया करती थी। उन्होंने कहा-मैंने रिहर्सल करने के लिए कहा तो वो चिल्लाकर बोले कितनी रिहर्सल। मैं नई थी, मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा- आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं और हमारा झगड़ा हो गया।

संजय दत्त से शादी करना चाहती थी ये एक्ट्रेस, पिता ने दिखाई एक्टर की करतूत

रति अग्निहोत्री ने 70 और 80 के दशक के सभी टॉप एक्टर्स के साथ काम किया है। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, कमल हासन और मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त जैसे सुपरस्टार्स के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा वह साउथ की फिल्मों में भी काफी फेमस थीं। उन्होंने मात्र अपने 16 साल की उम्र में वह स्टारडम पा लिया था जिसके लिए लोग तरसते थे।

बता दें कि रति का नाम बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त संग काफी जोड़ा गया था। 90 के दशक में इनकी लव स्टोरी काफी फेमस थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड में कदम रखने के बाद रति संजय दत्त के प्यार में भी पड़ीं। लेकिन उनके पिता ने रति

की शादी संजय से नहीं होने दी। संजय दत्त का अफेयर कई अभिनेत्रियों से रहा है। लेकिन रति अग्निहोत्री उनके प्यार में पागल थीं। वह उस समय ड्रग्स की लत से जूझ रहे संजय दत्त से शादी कर फिल्मी करियर छोड़ने तक के लिए तैयार हो गई थीं। हालांकि, उनके पिता को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रति के लिए उनके पिता संजय को सही लड़का नहीं मान रहे थे।

अपनी बेटी रति को समझाने के लिए उनके पिता ने फ्रीलांस फोटोग्राफरों को हायर किया। उन्होंने फोटोग्राफरों से कहा कि वह संजय के उन पलों और मनोदशा को कैद करें जब स्टार नशे में डूबा हो। इसके बाद कई तस्वीरों को मिलाकर रति के पिता ने एक वीडियो बनाकर अपनी बेटी को दिखाया। संजय की तस्वीरें देख रति बिखर गईं। उन्होंने संजय से शादी करने की जिद छोड़ दी। इसके बाद रति की शादी बिजनेसमैन अनिल वीरवानी से हो गई।

उसका पसंदीदा देश

वे गांधी की रामराज्य की भावना से पूरी तरह प्रभावित और अनुप्राणित थे और वास्तव में उस महापुरुष के उपकृत थे जिन्होंने ऐसा दिव्य-दर्शन प्रदान किया जिसे हर व्यक्ति अपने-अपने ढंग से अपनी-अपनी समझ के अनुसार और अपनी-अपनी जरूरतों के अनुरूप उपयोग कर सकता था और लगातार करता भी रहता था।

उसे वह देश बहुत ज्यादा पसंद था। वह इसे अपनी खुशकिस्मती मानता था कि वह उसी देश में पैदा हुआ था। इसके पीछे बहुत सटीक कारण भी था। उस देश में पूरी आजादी थी और पूरा न्याय। खासकर के आजादी। हर चीज की आजादी और हर आदमी को आजादी। यहां तक कि हर संस्था, संगठन, इकाई को भी पूरी स्वतंत्रता। यानि कि जिसकी जो इच्छा हो वह बके। जिसे जो गरियाना हो गरियाए। जिसे जहां जिस रूप में बहकना हो बहके। इस तरह से आदमी के रूप में जन्म लेने पर जिस तरह की आजादी की संकल्पना कई बड़े-बड़े विद्वानों और मनीषियों ने की थी वह सारा का सारा उस देश में नजर आ जाता था।

फिर केवल बोलने की ही आजादी नहीं थी। सबकुछ करने की भी आजादी थी। जी हां, जो मन हो कीजिए। सरेआम कत्ले-आम। हां भाई, कोई रोक-टोक नहीं। अकेले में मारें या सरे आम में- यह आदमी की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर था। किस हथियार से मारे, किस जगह पर मारे, किस तरह से मारे इन सारी बातों की उसे पूरी आजादी थी।

एक और अच्छी बात जो वहां थी वह यह कि वहां की समस्त शासकीय व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से आजादी की भावना से अनुप्राणित थी। अधिकारी आजाद, कर्मचारी आजाद। आजाद हर रूप में- इच्छा हुई काम किया, नहीं इच्छा हुई। इच्छा हुई तो फाईल रखा, इच्छा हुई फाईल उठा कर फेंक दिया। बड़ी आजाद व्यवस्था थी, बड़े आजाद ख्याल थे। मन हुआ देश की बातें की, मन हुआ तो आजादी का नारा देने लगे। और ऊपर से कहते थे यह सब सुदूर स्थित भारत देश की महान विभूति महात्मा गांधी के ही सिद्धांतों के अनुपालन में हो रहा है। उन लोगों का मानना था कि वे गांधी की रामराज्य की भावना से पूरी तरह प्रभावित और अनुप्राणित थे और वास्तव में उस महापुरुष के उपकृत थे जिन्होंने ऐसा दिव्य-दर्शन प्रदान किया जिसे हर व्यक्ति अपने-अपने ढंग से अपनी-अपनी समझ के अनुसार और अपनी-अपनी जरूरतों के अनुरूप उपयोग कर सकता था और लगातार करता भी रहता था।

एक अद्भुत देश जिसका मूल वाक्य था-देर है पर अंधेर नहीं। अत: लगातार जल्दीबाजी की कच-कच को उस देश में पसंद नहीं किया जाता था। बल्कि जो ज्यादा जल्दी में होता उसे जल्दी-जल्दी ऊपर भेज दिया जाता ताकि उसकी जल्दी की इच्छा एक ही बार में पूरी कर दी जाए।

एक और बात उस देश में बहुत अच्छी थी कि वहां के एक बड़े समुदाय को वहां की न्यायपालिका पर भीषण आस्था थी। इस आस्था के कारण भी थे। वहां की न्यायपालिका इस मत की थी कि उसके दरवाजे पर आना तो आने वाले की मर्जी पर है, पर जाना पूरी तरह न्यायपालिका के हाथों में। बल्कि अतिथि देवो भव की भावना से अनुप्राणित वे लोग जल्दी किसी मुवक्किल को छोड़ते भी नहीं थे जब तक या तो वह स्वाभाविक रूप से दम तोड़ देते थे या किसी बहाने उसका विपक्षी ही हथियार डाल दे। हां, गुस्सा वहां की न्यायपालिका को जरूर बहुत आता था- जल्दी-जल्दी आता था, कई बार तो एक दिन में कई बार आता था। और एक बार जब वे क्रोधित हुए तो पुराने मनीषियों की तरह ताबड़-तोड़ उस देश के और विदेशों के धर्म-शास्त्रों, विधि-शास्त्रों, काम-शास्त्रों, दर्शन-शास्त्रों और ना जाने कहां-कहां से बातें खोजकर बस लिखने ही लग जाते जिससे मूल मुद्दा तो वहीं का वहीं रह जाता और बड़ी-बड़ी दार्शनिक विवेचनाएं शुरू हो जातीं। फिर जब मन हुआ अपने देश की कार्यपालिका को गरियाया, कभी विधायिका को फटकारा और कभी-कभी मूड में आ गया तो अपने नीचे की न्यायपालिका पर भी चढ़ बैठे।

लेकिन ये चढ़ने-उतरने की आदत उस देश में सबों की थी। सब सब से नाराज थे। नेता अधिकारियों से, अधिकारी अपने नीचे के अधिकारियों से, नीचे के अधिकारी जनता से, जनता नेता से, मीडिया इन सब से, ये सब लोग मीडिया से। न्यायपालिका मीडिया से भी और बाकी सब से भी।

एक और बात जो उस देश को विशिष्टता देती थी वह थी उसकी त्वरित निर्णय-क्षमता। कोई बात हुई नहीं की जांच। तुरंत आदेश, आनन-फानन में आदेश। कभी-कभी तो इतनी तत्परता रहती कि गड़बड़ी बाद में होती, जांच के आदेश पहले हो जाते। इसके मूल में बस एक भावना रहती, रहीम की वह बानी जो एक सुदूर मुल्क से चलकर आई थी- काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी।

बहुत ही अच्छा देश था वह, बहुत ही बेमिसाल। सभी आजाद, सभी स्वतंत्र। फिर यदि बाकी की चीजों का अभाव भी था तो क्या, जिंदगी चल ही तो रही थी। उस इंसान की एक ही तमन्ना थी कि यदि कई बार भी जन्म लेना पड़े तो वह उसी देश में जन्म ले। अब बाकी कहीं उसका गुजारा हो पाता भला।

● **अमिताभ ठाकुर**

अन्नदाता के जीवन में आयी खुशहाली

गरीब वर्ग को मिला सम्मानजनक जीवन

कमजोर वर्ग के साथ प्रदेश सरकार

आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन

तेज गति से अधोसंरचना विकास

सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अभ्युदय

गौ-संरक्षण एवं संवर्धन

स्वच्छ भारत अभियान में मध्यप्रदेश बना सिरमौर

अन्य उपलब्धियां

भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार अग्रणी मध्यप्रदेश

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन
प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in